

हिन्दी, उर्दू, पंजाबी में एक साथ प्रकाशित दिल्ली सरकार की पत्रिका

अंक: जुलाई-अगस्त 2016

# दिल्ली

दिल्ली

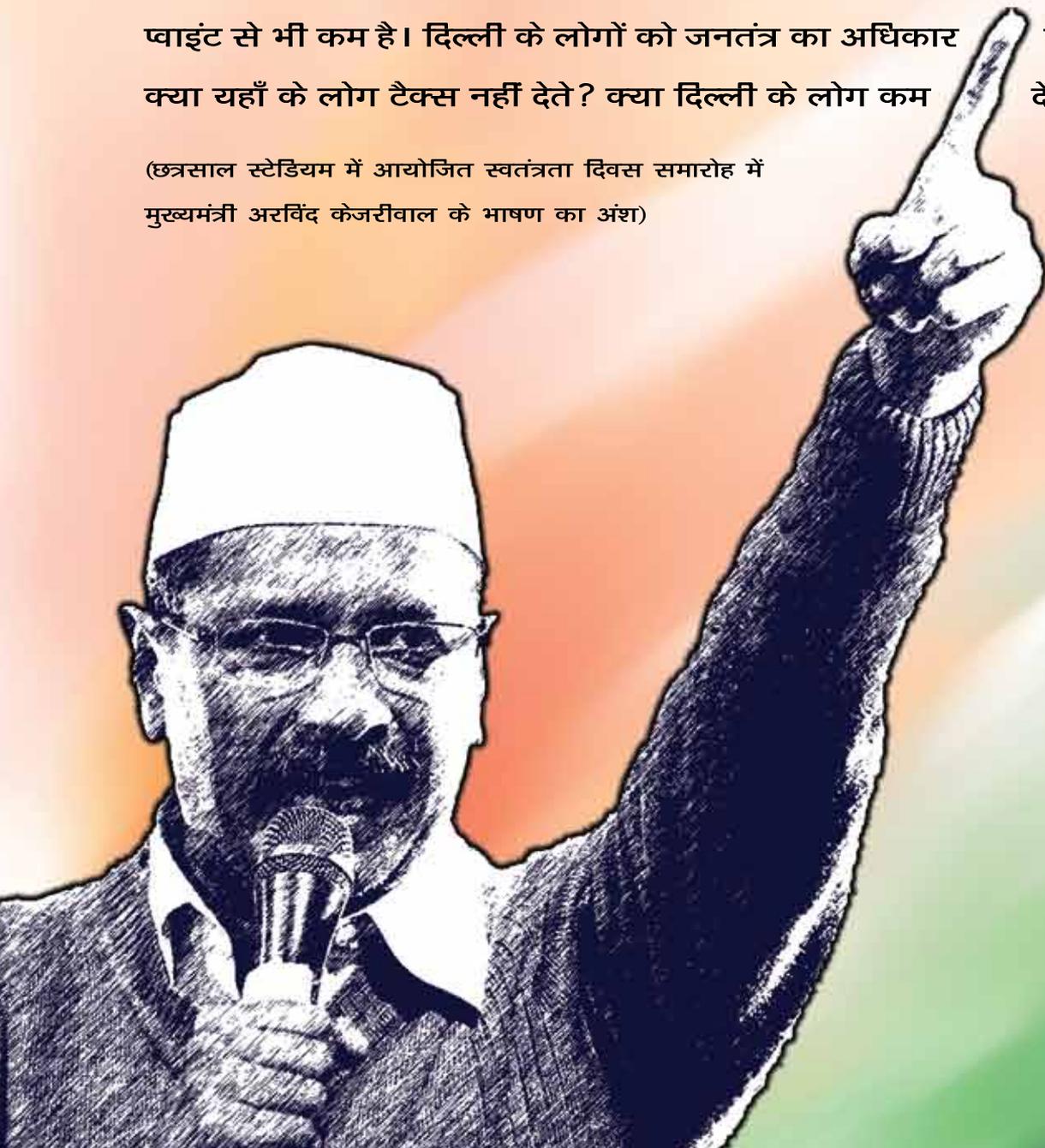
दिल्ली



“1935 में अंग्रेजों ने ‘गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट’ पारित किया था। इससे भारत के लोगों को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला था, लेकिन प्रतिनिधियों को सरकार चलाने का अधिकार नहीं था। आज दिल्ली में वही अंग्रेजों वाली व्यवस्था चल रही है। आज दिल्ली के लोगों को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, वे अपना मुख्यमंत्री चुन सकते हैं, लेकिन चुने हुए लोगों को सरकार चलाने का अधिकार नहीं है। दिल्ली की जनता के अंदर गुस्सा है। वह जानना चाहती है कि दिल्ली के लोगों के वोट की कीमत, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के लोगों के वोट से कम क्यों है?”

अगर महाराष्ट्र के लोगों के वोट की कीमत सौ प्वाइंट है तो दिल्ली के लोगों की 20 प्वाइंट से भी कम है। दिल्ली के लोगों को जनतंत्र का अधिकार क्यों नहीं है? क्या यहाँ के लोग टैक्स नहीं देते? क्या दिल्ली के लोग कम देशभक्त हैं?”

(छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भाषण का अंश)



# दिल्ली

अंक : जुलाई-अगस्त 2016

प्रधान सम्पादक  
सज्जन सिंह यादव

विशेष निदेशक  
संदीप मिश्र

सम्पादक  
डॉ. पंकज श्रीवास्तव

सम्पादकीय सहयोग  
नलिन चौहान  
कंचन आजाद, विनोद गुप्ता  
चन्दन कुमार, अमित कुमार  
मनीष कुमार, उर्मिला बेनिवाल

छाया चित्र

सुधीर कुमार, अजय कुमार, योगेश जोशी

“दिल्ली” पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं  
में अभिव्यक्त विचार रचनाकारों के  
अपने हैं तथा दिल्ली सरकार का इनसे  
सहमत होना आवश्यक नहीं।

पत्राचार का पता

प्रधान सम्पादक

दिल्ली सूचना एवं प्रसार निदेशालय  
दिल्ली सरकार

खंड सं. 9, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

दूरभाष : 23819046, 23817926

फैक्स : 23814081

ई-मेल : delhidip@gmail.com



26

दिल्ली अकादमी कार्यक्रम



20

दिल्ली लौट आये कलाम सर

इस अंक में...

हिन्दी

केंद्र साथ दे तो दो साल में दिल्ली को लंदन बना देंगे .....	2
स्वतंत्र भारत .....	12
स्वदेशी गाढ़ा .....	13
भारत है जान हमारी .....	13
‘चुनौती 2018’ 10वीं में सौ फीसदी रिजल्ट का लक्ष्य .....	14
दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम का आयोजन .....	16
शिक्षकों के अभाव में नहीं छूटेगी उर्दू और पंजाबी की पढ़ाई .....	17
सांप्रदायिकता हमेशा संस्कृति की खाल ओढ़कर आती है .....	18
पूरे भारत में खुले दिल्ली जैसे मोहल्ला क्लिनिक .....	22
असमानता बढ़ती रही तो लोकतंत्र नहीं टिकेगा .....	24
संक्षेप में .....	28

पंजाबी

ਕੇਂਦਰ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੰਦਨ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ .....	1
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਛੁਟੇਗੀ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ .....	11
ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਆਏ ਕਲਾਮ ਸਰ .....	12
ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ .....	14

उर्दू

ٹاک ٹوائے کے میں ہوا عوام سے مکالمہ،	
1..... مرکز ساتھ دے تو دو سال میں دہلی کو لندن بنا دیں گے۔ کچر یوال	
11..... ٹیچروں کی کمی میں نہیں چھوٹے گی اردو اور پنجابی کی پڑھائی	
12..... دہلی سرکار نے بنایا ڈاکٹر کلام کی	
12..... یاد میں میوزیم دہلی لوٹ آئے کلام سر	
14..... مختصر میں ...	

‘टॉक टू ए.के.’ में हुआ जनता से सीधा संवाद

TALK TO AK

# केंद्र साथ दे तो दो साल में दिल्ली को लंदन बना देंगे-केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 जुलाई को जनता के तमाम सवालों का सीधा जवाब देकर सरकार के खिलाफ फैलाई जा रही तमाम अफवाहों की सच्चाई बताई। साथ ही, अपनी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का खाका पेश किया। ‘टॉक टू ए.के.’ (बात करें अरविंद केजरीवाल से) कार्यक्रम में जनता के सवालों को पेश करने का जिम्मा मशहूर संगीतकार विशाल डडलानी ने उठाया। जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री के अलावा उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। सवाल ट्विटर, एसएमएस के जरिये पूछे गये और सीधे फोन करके भी। पेश हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री केजरीवाल के संबोधन और बाद में हुए सवाल-जवाब के संपादित अंश—

अरविंद केजरीवाल—समय-समय पर मैं मीडिया को इंटरव्यू देता रहा हूँ, लेकिन जब जनता के बीच जाता हूँ तो लगता है कि जनता के प्रश्न और मीडिया के सवाल अलग-अलग हैं। पिछले दिनों मैंने गोवा में नौजवानों से बातचीत की थी। करीब एक हजार युवा थे वहाँ। उनसे सीधे बात की तो पता चला कि नौजवानों के मन में कैसे-कैसे सवाल हैं। तो मैंने सोचा कि दिल्ली में भी ऐसा करें। जनता से सीधे बात करने का कोई प्लेटफार्म होना चाहिए। जनता के सवालों का सामना तभी कर सकते हैं जब आप ईमानदार हों। आज हम ऐसा कर रहे हैं ऐसा, यह हमारी ईमानदार राजनीति का प्रमाण है।

सरकार में पैसे की नहीं नीयत की कमी है। स्कूल, पानी, बिजली, अस्पताल सब कुछ हो सकता है। हमारी यात्रा ने सिद्ध किया कि हम जो कहते थे, वह ठीक था। जो काम पहले सौ रुपये में होता था, वह अब 60-70 रुपये में होता है।

फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाजीपुर में रेलरोडपुल का उद्घाटन किया। जब 2009 में यह पुल बनना शुरू हुआ था तो लागत थी 600 करोड़। अब यह तीन हजार करोड़ का हो गया। दिल्ली में एक रानी झांसी फ्लाईओवर है। 2008 में 70 करोड़ की अनुमानित लागत के आधार पर एमसीडी (दिल्ली सरकार नहीं) ने बनाना शुरू किया। अभी बन के तैयार नहीं हुआ और लागत 200 करोड़ हो गई। गोवा में मांडोवी ब्रिज 2014 से बनना शुरू हुआ था तो अनुमानित लागत थी 470 करोड़। अब दो साल में ही यह बढ़कर 886 करोड़ हो गई।

पूरे देश में ऐसे ही होता है। काम समय पर पूरा नहीं होता और लागत बढ़ती जाती है। दिल्ली में कुछ फ्लाईओवर बन रहे थे जब हम आये। पुरानी सरकार काम शुरू करा गई थी। एक की कहानी बताता हूँ। दस फीसदी काम हुआ था। दो-ढाई साल पहले काम शुरू हुआ था तो अनुमानित लागत थी सवा तीन सौ करोड़। हमने यह फ्लाईओवर दो सौ करोड़ में बना कर दिखाया, वह भी समय से पहले। ऐसा उदाहरण कहीं नहीं है। 300 करोड़ की लागत का काम डेढ़ हजार करोड़ में तो होता था, दो सौ करोड़ में पहली बार हुआ।

हमारी सरकार ने पाँच फ्लाईओवर में बचाये कुल साढ़े तीन सौ करोड़। मंगोलपुरी में आईटीआई 24 करोड़ रुपयों में बनना था। हमने सोलह करोड़ में बनाया। पहले डिस्पेंसरी 4-5 करोड़ में बनती थी। अब बीस लाख में एयरकंडीसन्ड डिस्पेंसरी बन रही हैं। इस बचत से हमें पैसा मिला तो तमाम चीजों पर टैक्स कम कर दिया। लोगों ने कहा कि टैक्स कम करने से आमदनी घटेगी, लेकिन उलटे फायदा हुआ। दिल्ली में टैक्स कलेक्शन बढ़ गया।

सरकार का चार चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान है—शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी।

**शिक्षा**—मनीष सिसौदिया, रात दिन शिक्षा को बेहतर करने के बारे में सोचते रहते हैं। हम किसी भी प्रदेश में जायें

तो सरकारी स्कूलों की बुरी हालत दिखती हैं। शौचालय नहीं हैं, बच्चे छुट्टी के पहले भाग जाते हैं, शिक्षक पढ़ाते नहीं। टॉप करने में घोटाला निकल रहा है। डिग्रियाँ बँट रही हैं, नकल चल रही है। ऐसे में देश का क्या होगा, सोचने की बात है।



दिल्ली में सरकार बनाते ही हमने यह चुनौती स्वीकार की। हमने समझा कि शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च, दरअसल निवेश है। कैबिनेट ने फैसला किया कि शिक्षा का बजट दोगुना कर दिया जाये। पाँच हजार करोड़ से सीधे दस हजार करोड़। कभी ऐसा नहीं हुआ कि शिक्षा का बजट सौ फीसदी बढ़ा हो। आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार है।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं नहीं थीं। शौचालयों में ताले लगे रहते थे या उनकी हालत बेहद खराब थी। हमने उन्हें दुरुस्त कराया। जहाँ शौचालय नहीं थे, वहाँ नये बनवाये। लगभग 1100 सरकारी स्कूलों में शौचालय, पीने के पानी, सफाई और सुरक्षा का इंतजाम किया गया।

फिर पता चला कि एक क्लास में डेढ़ सौ बच्चे हैं। हम शिक्षक को कैसे कहते कि वे ठीक से पढ़ा नहीं रहे हैं। हमने पता किया कि कितने क्लासरूम की जरूरत है। एक साल में 8000 नये क्लासरूम बनाये गये। चालीस कमरों का औसत लगायें तो यह 200 नये स्कूलों के बनने के बराबर है। इसके अलावा 45 नये स्कूल बनकर तैयार हैं। 100 नये स्कूलों के लिए जमीन तय कर ली गई है। हमने इन्हें शानदार बनाने के लिए बेस्ट आर्कीटेक्ट ढूँढे हैं। हमारा मानना है कि गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल गई तो वे खुद विकास कर लेंगे।

## केंद्र ये चार क़दम उठाये तो रुकेगी किसानों की खुदकुशी—केजरीवाल

मैंने इंटर-स्टेट काउंसिल में प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ जोड़कर अपील की कि पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। चार चीजें कर दीजिए तो यह समस्या दूर हो सकती है—

- सारा लोन माफ कर दीजिए किसानों का। बहुत पुण्य होगा। देश के किसान आशीष देंगे।
- स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दीजिए। मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के पहले इसे लागू करने का वादा किया था। इसमें है कि लागत से पचास फीसदी जोड़कर फसल का मूल्य तय किया जाएगा। गेहूँ की लागत आ रही है 1950 रुपये प्रति क्विंटल और सरकार ने कीमत तय की है 1450 रुपये। किसान खुदकुशी नहीं करेगा तो क्या करेगा।
- अगर देश के किसी हिस्से में किसानों की फसल बरबाद हो, तो जैसे दिल्ली में 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया गया, वैसे ही केंद्र राज्य सरकार को दे।
- अस्पतालों में दवाइयों और सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए जाएँ।

दिल्ली में कई निजी स्कूल ऐसे हैं जो दुकान बन गए हैं। अनाप-शनाप फीस हर साल बढ़ाते हैं। जनता दुखी है। आज तक कोई उनकी नकेल नहीं कस सका। ऐसे स्कूल सरकार को कुछ नहीं समझते थे क्योंकि हर मंत्री और मुख्यमंत्री वहाँ सिफारिश से एडमिशन कराते थे। हमने एक बच्चे की भी सिफारिश नहीं की। मेरा अपना बेटा नोएडा में पढ़ता है। चाहता तो दिल्ली के किसी भी स्कूल में एडमिशन करा देता। लेकिन नहीं कराया, क्योंकि फिर मैं उन्हें फीस बढ़ाने से कैसे रोकता। वे कहते कि आपका बेटा हमारे यहाँ पढ़ता है। मैं कमजोर हो जाता। मैंने या मनीष ने किसी का भी एडमिशन नहीं कराया। इसलिए हमारे पास हिम्मत है और हम ज्यादा वसूली गई फीस वापस करा रहे हैं।

हम जाँच करा रहे हैं। अगर लगेगा कि फीस बढ़ाने की जरूरत है तभी बढ़ेगी। यह पहली बार है कि निजी स्कूलों की नकेल कसी गई है। अगर यह दिल्ली में हो सकता है तो गुजरात, गोवा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब में क्यों नहीं हो सकता। हमारा अनुभव बताता है कि इच्छाशक्ति हो तो बिल्कुल हो सकता है।

मैं देश को चेता रहा हूँ कि अगर देश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं हुई, नकल और फर्जी डिग्री का सिलसिला चलता रहा तो देश के लिए ठीक नहीं होगा।

कुछ साल पहले 'नो डिटेंशन' पॉलिसी आई। आठवीं तक किसी को फेल नहीं किया जाता। अचानक नवीं में

इम्तहान होता है। पता चलता है कि बच्चा नौवीं में पहुँच गया लेकिन पढ़ना-लिखना नहीं आता। कई बार डिप्रेशन में बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं। बच्चों को बरबाद कर रही है यह 'नो डिटेंशन' पॉलिसी। पहले अगर कोई कमजोर होता था तो कमपार्टमेंट आ जाती थी। सबको पढ़ना पड़ता था। हमने इस पॉलिसी को हटाने का बिल पास करके केंद्र को भेजा है। मैं अपील करता हूँ कि केंद्र जल्द से जल्द इसकी मंजूरी दे।

दिल्ली में हमने सौ फीसदी बजट बढ़ाया शिक्षा में क्योंकि इच्छाशक्ति थी। केंद्र की सरकार ने शिक्षा के बजट में 25 फीसदी कटौती करके 82 हजार करोड़ से 68 हजार करोड़ कर दिया था। अब उसे 71 हजार करोड़ किया है। जबकि हमने पांच हजार से दस हजार करोड़ करके सौ फीसदी बढ़ाया।

सड़कें, फ्लाइओवर, नाली, सब जरूरी है पर सबसे जरूरी शिक्षा है। एक सड़क नहीं बनेगी तो काम चल जाएगा, पर बच्चे नहीं पढ़े-लिखेंगे तो पूरा देश बरबाद हो जाएगा। मेरा अपना मानना है कि हर राज्य सरकार को और केंद्र को शिक्षा पर बजट बहुत बड़े स्तर पर बढ़ाना पड़ेगा, ताकि देश के बच्चे पढ़ लिख सकें।

**स्वास्थ्य**—हमारी दूसरी प्राथमिकता है स्वास्थ्य। हम शिक्षा और स्वास्थ्य में खर्च को निवेश मानते हैं। पूरे देश में सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों का बुरा हाल है। अभी पंजाब गया था थोड़े दिन पहले। वहाँ एक गाँव

गया। गाँववाले पकड़कर एक लोकल डिस्पेंसरी में ले गये। वर्किंग डे था। करीब 11 बजे थे लेकिन वहाँ ताला लगा था। न मरीज, न डॉक्टर, न नर्स। यह हालत है पब्लिक सेक्टर की।



जब हमने दिल्ली में काम शुरू किया तो यहाँ के सरकारी अस्पतालों का भी हाल बुरा था। यहाँ भी हमने सबसे पहले बजट बढ़ाया। जैसे शिक्षा में 100 फीसदी बढ़ाया वैसे ही स्वास्थ्य में 50 फीसदी बजट बढ़ाया। दिल्ली सरकार का कुल बजट 40 हजार करोड़ है। इसमें से करीब 10 हजार करोड़, लगभग 25 फीसदी शिक्षा पर और 18-19 फीसदी स्वास्थ्य पर खर्च किया जाता है।

अभी दिल्ली में बड़े-बड़े अस्पताल और डिस्पेंसरियाँ हैं। खाँसी-जुकाम होने पर भी लोग एम्स भागते हैं। तो हमने तय किया कि अच्छी डिस्पेंसरियाँ बनें। हमने इसके लिए तीन चरणों की व्यवस्था बनाई है। सबसे नीचे है मोहल्ला क्लीनिक ताकि छोटी-मोटी बीमारियों के लिए मुहल्ले में ही इलाज हो जाए।

हमने पीरागढ़ी में पहला आम आदमी क्लीनिक बनाया। झुग्गी बस्ती में एयरकंडीशन्ड। वहाँ डॉक्टर के अलावा 212 किस्म के टेस्ट हो सकते हैं, जिसमें एक-दो तो ऐसे हैं जिनमें एक हजार रुपये तक खर्च होते हैं। सब कुछ फ्री, दवा से लेकर टेस्ट तक। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ऐसी डिस्पेंसरी बन सकती है। पहले ऐसी डिस्पेंसरी बनाने में पाँच करोड़ रुपये लग जाते थे, हमने बीस लाख में बनाया। इसकी तारीफ केवल मैं नहीं कर रहा हूँ, अमेरिका से एक रिपोर्टर आया वाशिंगटन पोस्ट का, उसने इसे देखा। उसे इतना अच्छा लगा कि 'वाशिंगटन पोस्ट' में ख़बर छपी कि क्या अमेरिका, दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक से सीख सकता है?

अभी तक हम अमेरिका से सीखने की बात करते थे, अब वह हमसे सीख चाहने चाहते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। अब तक 100 डिस्पेंसरी बन चुकी हैं। सब बहुत अच्छी चल रही हैं। इस साल 31 दिसंबर तक दिल्ली में ऐसी 1000 डिस्पेंसरी बन जाएँगी।

स्वास्थ्य सुरक्षा का अगला स्तर है पॉलीक्लीनिक का। इसमें अल्ट्रासाउंड से लेकर एक्सरे तक की व्यवस्था होगी और एक साथ सात-आठ तरह की बीमारियों के विशेषज्ञ यहाँ उपलब्ध होंगे। यहां मरीज भर्ती नहीं किए जाएंगे। हाँ, बीमारी गंभीर हुई तो सारी जाँच और डाक्टरी सलाह उपलब्ध होगी। अब तक 22 पॉलीक्लीनिक बन चुके हैं। अभी मैं पश्चिम विहार का पॉलीक्लीनिक देखने गया तो वहाँ मध्यवर्ग के लोग आये थे। उन्होंने कहा कि 5 स्टार अस्पतालों में भी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब अगर अमीर लोग, मिडिल क्लास के लोग, सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने आ रहे हैं तो यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति ही है।

तीसरा स्तर है बड़े अस्पताल। मल्टीस्पेशिलिटी अस्पताल। हमने सारी दवायें और जांचें मुफ्त कर दी हैं। इसलिए कि हम मानते हैं कि स्वास्थ्य और इलाज की सुविधा मौलिक अधिकार जैसा है। बड़ी बीमारी हो तो निजी अस्पतालों में जाने पर गरीब आदमी का सबकुछ लुट जाता है।

आखिर दिल्ली सरकार के पास यह सब करने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। पहले तो लोग पैसे की किल्लत की बात करते थे। दरअसल, यह ईमानदार सरकार है। इसलिए खूब पैसा बच रहा है। दिल्ली में अगर ऐसा हो रहा है तो पंजाब, गोवा, हिमाचल, हर जगह हालात सुधर सकते हैं।

कई बार सुनते हैं कि किसान ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि बीमारी होने पर लाखों का बिल चुकाने के लिए कर्ज लिया था। चुका नहीं पाया और खुदकुशी कर ली। मैंने इंटर-स्टेट काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री जी के सामने यह मुद्दा उठाया। अगर केंद्र सरकार, पैसे देकर सरकारी अस्पतालों में दवाएँ और इलाज फ्री कराने की व्यवस्था करा दे तो पूरा देश गुण गाएगा। किसानों की खुदकुशी कम होगी।

**बिजली**—बिजली को लेकर भी हमारी सरकार ने वादा पूरा किया। जब हमारी सरकार बनी तो देश में सबसे

## जमाखोरी न रुकी तो 400 रुपये किलो बिकेगी दाल—केजरीवाल

देश में दालों की कीमतों में आग लगी हुई है। क्यों बढ़ रही है कीमत इतनी ज्यादा। 17–18 मिलियन टन दाल पैदा होती है देश में। चार–पांच मिलियन टन बाहर से मंगाते हैं। करीब 22–23 मिलियन खपत है। इस साल भी वैसा ही है। फिर आग क्यों लगी हुई है दाल में ? गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1450–1500 रुपये है, बाजार में 17–18 रुपये प्रति किलो मिल रहा है। अरहर–मूँग का है 50 रुपये, बाजार में 200 रुपये किलो है। कहाँ जाते हैं 150 रुपये। बीच में बड़े–बड़े जमाखोर पैदा हो रहे हैं। यह 8–10 लोग हैं जो जमाखोरी कर रहे हैं।

मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा मीटिंग में बड़े–बड़े लोग दाल की जमाखोरी कर रहे हैं। ऐसे आरोप हैं तो जांच तो हो। अगर इस पर सख्ती न हुई तो 400 रुपये किलो हो जाएगी दाल, न हम खा पाएँगे न आप।

ज्यादा महँगी बिजली शायद दिल्ली में थी। हमने आते ही दाम आधे कर दिये। दिल्ली में यदि कोई परिवार दो सौ युनिट बिजली खर्च करता है तो उसका बिल आता है 550 रुपये, गुजरात में आता है 1170 रुपये, मुंबई में 1950 रुपये और पंजाब में 1229 रुपये का बिल आता है।

अगर दिल्ली में 400 युनिट बिजली खर्च हो तो बिल आता है 1370 रुपये, गुजरात में 2615, मुंबई में 4300, कोलकाता में 2927 रुपये और पंजाब में 2690 रुपये।

Meter No.	Reading	Previous Reading	Consumption	Rate	Amount
123456789	1000	900	100	1.42	142.00

एक दो राज्यों को छोड़कर दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली मिलती है। लेकिन एक चुनौती है। बिजली का इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहद खराब है। युद्ध–स्तर पर ट्रान्सफार्मर लगाने हैं। लोकल फाल्ट बहुत होते हैं। दिल्ली में बिजली की कमी नहीं है।

**पानी**—हम मानते हैं कि पानी मौलिक अधिकार है। लेकिन निजीकरण और उपभोक्तावाद के दौर में माहौल बनाया जा रहा है कि पानी बिकना चाहिए। मेरा मानना है कि पानी तो हर हाल में चाहिए। पानी तो गरीब से गरीब आदमी पियेगा। नहीं दोगे तो चोरी करके पियेगा। तो प्यास बुझाने लायक निःशुल्क पानी देना सरकार का धर्म है।

हमने सरकार बनाने के बाद 20,000 लीटर पानी मुफ्त कर दिया। पाँच लोगों का परिवार हो तो इतना पानी बहुत

है। लोगों को यकीन नहीं हुआ। बिल जीरो हो गया। कई लोग कहने लगे कि जल–बोर्ड बरबाद हो जाएगा। साल भर बाद हमें 173 करोड़ राजस्व ज्यादा मिला जबकि पानी मुफ्त था, क्योंकि हमने भ्रष्टाचार कम किया। पानी बरबाद भी नहीं हुआ। लोग कहते थे फिजूल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हुआ यह कि 3 मीलियन गैलन प्रतिदिन की बचत होने लगी क्योंकि बीस हजार लीटर के ऊपर पानी इस्तेमाल होने पूरा बिल देने का डर था।

एक समस्या बिल की है। पूरे देश में यह समस्या है। यहाँ भी गलत बिल आते थे, जिसे ठीक कराने के नाम पर भ्रष्टाचार होता था। हमने सरकार में आने के बाद सबका पुराना बिल माफ कर दिया। तीन–चार लाख तक का बिल माफ हो गया। इसके साथ ही मोबाइल फोन से खुद मीटर रीडिंग करके बिल बनाने की व्यवस्था कर दी। मीटर रीडर की व्यवस्था खत्म हुई।

बहुत से इलाके हैं जहाँ अब तक पानी नहीं पहुँचा था। हमने 263 नई कालोनियों में पाइप बिछाकर पानी पहुँचाया। हमने दिसंबर 2017 तक हर घर तक पानी पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। पानी भी ऐसा कि टोटी खोलो और पी लो। पहले भी न आर.ओ. होता था और न प्लास्टिक की बोतल। टोटी से हम लोग पानी पीते थे। तो हमने साफ पानी का लक्ष्य रखा है।

किसानों के लिए भी हमने बहुत कुछ किया। किसानों ने कहा कि फसलें बरबाद हुईं। 20 हजार रुपये प्रति एकड़ और 50 हजार हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया। देश में कभी नहीं हुआ ऐसा। इसी तरह भूमि अधिग्रहण में पहले 54 लाख रुपये प्रति एकड़ सरकार देती थी जबकि मार्केट रेट तीन करोड़ के करीब था। हमने तीन से चार

करोड़ का रेट कर दिया। छह गुना प्रति एकड़ इजाफा हुआ। इसके लिए लड़ना पड़ा।



व्यापारियों का हाल बहुत खराब है। कमाई घट रही है। जो सौ कमाते थे, अब 80 कमा रहे हैं। लेकिन आठ-दस-पंद्रह लोग हैं, जिनकी संपत्ति दोगुनी-तीगुनी हो रही है। उनका मुनाफा कहाँ से आ रहा है? मान लीजिए किसी ने तीस रुपये किलो दाल खरीद ली और अब 200 रुपये में बेच रहा है तो मेरी और आपकी जेब से ही जा रहा है उसके पास। यानी देश भर में व्यापारी दुखी है लेकिन कुछ बढ़ते जा रहे हैं। ध्यान देना पड़ेगा।

**विशाल डडलानी-दिल्ली से पुलकित पूछते हैं कि एक तरफ आप कहते हैं कि मोदी जी आपको काम नहीं करने दे रहे हैं और उसी वक्त आप करोड़ों के विज्ञापन देते हैं कि कितना काम किया। यह दोनों कैसे हो सकते हैं...?**

**अरविंद केजरीवाल-**मैंने जो काम गिनाए, वह हुए हैं। कल्पना नहीं है। जाकर देख आइये मोहल्ला क्लीनिक और स्कूल। पानी, बिजली तो आप खुद महसूस कर रहे होंगे। लेकिन बाधाएँ नहीं आती तो काम दोगुना-तिगुना हो सकता था। हमारी विधानसभा ने 14 कानून पास किये। जैसे हमने एक कानून पास किया कि अगर 15 दिन में आपका राशनकार्ड नहीं बना तो हर अगले दिन के हिसाब से अफसर की जेब से पैसा कटेगा और आपको मुआवजा मिलेगा। अगर राशनकार्ड और लाइसेंस आदि बनने की समय सीमा तय हो जाए तो भ्रष्टाचार नहीं बचेगा। लेकिन आठ महीने से कानून केंद्र के पास अटका पड़ा है। जनलोकपाल बिल, नो डिटेन्शन बिल भी पड़ा हुआ है। 14 बिल पड़े हुए हैं।

दूसरा, कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार के 11 अफसरों को बिना हमसे पूछे ट्रॉसफर कर दिया गया। हम मानते हैं कि केंद्र को ऐसा करने का अधिकार है पर क्या अधिकार का बेजा इस्तेमाल होगा। लोकतंत्र संवाद से चलता है। हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो जनता से पूछते हैं। जो अफसर सीसीटीवी लगा रहा था उसका तबादला कर दिया गया। जो अनिधकृत कॉलोनी में पानी, बिजली, खडंजा, नाली का काम करा रहा था, उसका ट्रॉसफर कर दिया।

दिल्ली सरकार में सचिव स्तर पर 39 पोस्ट हैं जिसमें 20 खाली हैं। फिर भी उठाकर तबादला कर देते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार और अच्छे से चलेगी। हम बाहर से जनता के बीच से लोगों को लाएँगे।

हमारे पास एसीबी (एंटी करप्शन ब्रांच) थी तो 49 दिन की सरकार में ही भ्रष्टाचार खत्म कर दिया था। हमारी सरकार बनने के चार महीने बाद तक यही हाल रहा, लेकिन 8 जून को पिछले साल केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बल भेजकर एसीबी पर कब्जा कर लिया। आज दिल्ली में मेरे सामने कोई रिश्वत ले तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने 32 केस एक साल में एसीबी के पास सबूत के साथ भेजा, 150 शिकायतें जनता ने की हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई।

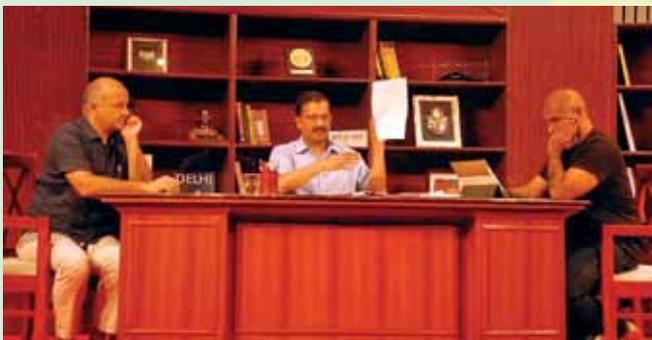
केंद्र ने तमाम फाइलें रोक रखी हैं। मिड डे मील का बुरा हाल है। कर्नाटक में इसे लेकर 'अक्षय पात्र' योजना चल रही है। इस्कॉन वाले अच्छा काम कर रहे हैं। गरम खाना, शानदार किचन। आठ राज्यों में वे काम कर रहे हैं। गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक आदि में। हर जगह नामांकन के आधार पर। वे एनजीओ हैं, टेंडर में आवेदन नहीं करते। वे कहते हैं कि हम मुनाफा नहीं कमाते। उलटा डोनेशन लेकर आते हैं। हमने भी फाइल चलाई, कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके भेजा कि दिल्ली में मिड-डे मील में उनकी सेवाएं लेंगे। लेकिन एलजी साहब ने मना कर दिया।

मनीष ने 8 हजार कमरे बनाये, 45 नये स्कूल बनाये। अब हमें 20 हजार शिक्षक चाहिए। 15 हजार अस्थायी शिक्षक हैं। हमने उन्हें पक्का करने के लिए फाइल चलाई लेकिन रोक दी गई। बताइये कि स्कूल कैसे चलाएँ। हमने दस नए अस्पतालों के लिए फाइल भेजी है, पैसा दे रहे हैं लेकिन जमीन देने को तैयार नहीं हैं। महिलाओं की सुरक्षा

के लिए 'कमीशन आफ इन्क्वायरी' बनाया जिसे खारिज कर दिया गया। अगर साथ देते, भारत-पाकिस्तान जैसी स्थिति न बनाते तो चार गुना काम हो सकता था। मैंने मोदी जी से हाथ जोड़कर कहा कि कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिए। मुझे पैसे नहीं चाहिए। बहुत बजट है। बस रोज-रोज की खिच-खिच बंद करा दीजिए। आप स्वच्छ भारत की बात करते हैं, मैं दो साल में दिल्ली को लंदन जैसा बना दूँगा। 'स्किल इंडिया' सबसे बेहतर कर देंगे। सारी तारीफ़ आपकी करूँगा, लेकिन नहीं माने।

**विशाल डडलानी-सवाल आया है विज्ञापन बजट के बारे में। मुंबई से पंकज पूछते हैं कि क्या आपने 526 करोड़ का बजट खर्च किया है विज्ञापनों पर, और दिल्ली सरकार के विज्ञापन दूसरे राज्यों में क्यों दिखाते हैं ?**

**अरविंद केजरीवाल**-पहली चीज तो ये गलतफहमी फैलाई जा रही है कि 526 करोड़ विज्ञापन पर खर्च किये। पिछले साल इस मद में खर्च हुए सिर्फ 75 करोड़। ये आरएसएस अफवाहें फैलाने में माहिर है। मुझे नहीं लगता कि इस मामले में दुनिया में उनका कोई सानी है। वे एक अफवाह शुरू करते हैं और फैलाते जाते हैं, फैलाते जाते हैं जब तक कि वह लोगों के बीच बैठ नहीं जाती है। पहले हर विभाग अलग-अलग विज्ञापन देता था। उसमें घपला होता था। अब हमने सेंट्रलाइज कर दिया है और इस लिहाज से 75 करोड़ ज्यादा नहीं हैं।



दूसरा सवाल है कि हम दूसरे राज्यों में विज्ञापन क्यों दिखाते हैं। दो-तीन कारण हैं। दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ सारे देश के लोग रहते हैं। केरल के, तमिलनाडु के, पंजाब के लोग भी, हर राज्य के लोग रहते हैं। दिल्ली में एक छोटी घटना हो जाए तो टीवी वाले दिन भर दिखाते हैं। मध्यप्रदेश में क्या हो रहा है उसे नहीं दिखाते, क्योंकि दिल्ली में जो हो रहा है, उसे सारे देश के लोग जानना चाहते हैं।

दिल्ली में अच्छा काम चल रहा है, यह पूरे देश को बताना जरूरी है ताकि पूरे देश से निवेश यहाँ आये। पहले सारे इंटरनेशनल इवेंट यहाँ होते थे। लेकिन दस साल से नहीं हो रहे थे। बताया गया कि एक इवेंट के लिए 27 विभागों से एनओसी लेनी पड़ती है। पाँच-छह महीने चक्कर लगाने पड़ते हैं। हमने सभी विभागों के प्रमुखों को साथ बैठाया और कई एनओसी की जरूरत खत्म कर दी। बाकी को ऑनलाइन कर दिया। पिछले दिनों एक आयोजक मेरे पास आये जिन्होंने बताया कि 20 मिनट के अंदर उन्हें इवेंट करने की इजाजत मिल गई। अब अगर दिल्ली में ऐसा काम हो रहा है तो मुंबईवालों को बताना जरूरी तो है। दिल्ली में आओ, इवेंट करो। सारे देश को नहीं दुनिया को बताना जरूरी है कि दिल्ली में आओ, बिजनेस करो।

**विशाल डडलानी-पुडुचेरी से सुधाकर पूछते हैं कि आपके 21 विधायक संसदीय सचिव बने हैं जिसकी वजह से सदस्यता रद्द होने का खतरा है। आप कहते हैं कि वेतन नहीं लेते, भत्ता नहीं लेते तो फिर ऐसे ही काम कर सकते थे। नाम देने की जरूरत क्या थी। बगैर पोस्ट के भी काम कर सकते थे।**

**अरविंद केजरीवाल**-दरअसल विपक्षी दलों को काम करने की आदत नहीं है। हमारे विधायक काम कर रहे हैं। समस्या क्या है। अगर हमारा विधायक एक स्कूलों में राउंड लगाकर बता रहा है कि शिक्षक आये कि नहीं या पढ़ाई कैसे हो रही है। इस काम के लिए सरकार एक पैसा नहीं देती। न गाड़ी देती है न बँगला देती है और न नौकर। अपने जेब से पैसे खर्च करके समाज सेवा के नाम पर वह यह सब काम करता है। फिर मनीष को रिपोर्ट देता है। फिर मनीष जाते हैं। उसी तरह दूसरे विधायक अस्पतालों के हाल पर नजर रखते हैं। कई विधायकों को ऐसी ही जिम्मेदारी है जिसका एक पैसा नहीं देते हम, तो फिर यह 'आफिस ऑफ प्रॉफिट' कैसे हो गया ?

उन्हें पोस्ट देने की जरूरत इसलिए थी कि ऐसे अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर कोई विधायक नहीं जा सकता। तो उसको एक अधिकार दिया कि स्कूल जाकर देखे कि सब ठीक-ठाक है या नहीं।

अब ये कह रहे हैं कि सबको संसदीय सचिव पद से हटाओ, घर बैठाओ। यानी घर बैठे अच्छे हैं, काम नहीं

करना चाहिए। काम तो करेंगे जी। हमने बड़े-बड़े वकीलों से बात की है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि कुछ पैसे का लाभ मिलना चाहिए, तब 'ऑफिस ऑफ प्राफिट' है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग उचित निर्णय लेगा।

दूसरे राज्यों में भी संसदीय सचिव हैं। उन्हें वेतन, गाड़ी, बँगला सब मिलता है। पंजाब, गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश सब जगह मिलता है। हम धेला नहीं दे रहे हैं, अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं फिर भी बीजेपी और कांग्रेस वालों को दिक्कत है।

**रंजीत माथुर (साउथ दिल्ली)—नमस्कार मेरा नाम रंजीत माथुर है, साउथ दिल्ली में तुगलकाबाद कालोनी से। हमारी गली नंबर 16 में सीवर लाइन बदलने का काम शुरू हुआ था। बारिश का मौसम है, गली खुदी है। बच्चों के गिरने का डर है।**

**अरविंद केजरीवाल—**मैं आपकी डिटेल नोट करा रहा हूँ। अधिकारी आपके पास जाकर समस्या हल करेंगे।

**नेपालदास (चेन्नई)—क्या जरूरत थी विधायकों की सैलरी बढ़ाने की, क्या वेतन पर्याप्त नहीं था ?**

**अरविंद केजरीवाल—**पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक सरकार करप्शन पर जीरो टालरेंस रख रही है। कोई विधायक करप्शन नहीं कर सकता। मैं भी निगाह रखता हूँ। अभी तक धारणा ऐसी थी कि लोग करप्ट हैं, हाँलाकि कुछ ईमानदार भी होते हैं। कई जगह लोग बिना वेतन के काम करते हैं, जैसे म्युनिस्पल कॉरपोरेशन में 200 रुपये प्रति बैठक पाते हैं, लेकिन उनके बड़े-बड़े बँगले हैं, गाड़ियाँ हैं। कहाँ से आते हैं यह सब? यह सिस्टम हम नहीं करना चाहते कि खुला छोड़ दो विधायकों को कि जो मर्जी जहाँ से कमाये, लेकिन दिखाने के लिए तनखाह नहीं देंगे। हमने इसे उल्टा किया है। हमने तय किया है कि तनखाह देंगे और कहकर देंगे। इतनी देंगे कि उसका घर और दफ्तर चल जाए। लेकिन फिर किसी तरह का करप्शन बर्दाश्त नहीं होगा। पकड़कर जेल में डाल देंगे।

हमारी सरकार बनी तो एक विधायक की तनखाह 12 हजार थी। हमने बढ़ाकर 50 हजार किया तो चैनल वाले चलाने लगे कि 400 फीसदी इज़ाफा। हमने पूछा उनसे कि आपको कितने मिलते हैं, तो कहने लगे कि हमारी मत

पूछो। उन्हें मिलते हैं चार करोड़। हम कहकर दे रहे हैं, खुलकर दे रहे हैं। अगर नहीं देंगे तो भ्रष्टाचार के लिए बाध्य करेंगे।

**प्रदीप (हैदराबाद)—**बहुत सारे युवा प्रशासन में मदद करना चाहते हैं, उनकी भागीदारी कैसे हो सकती है। और सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या योजना है ?

**अरविंद केजरीवाल—**पहली चीज तो यह है कि यह युवाओं की सरकार है। हममें ज्यादातर ऐसे हैं जिनके परिवार के लोग कभी राजनीति में नहीं थे। हमारी अपील है कि युवा राजनीति में आयें। हम लोगों ने मुख्यमंत्री अर्बन फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें 9 हजार लोगों ने आवेदन किया है।

दिल्ली देश की राजधानी है और यह शर्म की बात है कि यहाँ चारो तरफ गंदगी है। रॉकेट साइंस नहीं है इसे साफ करना। हम भी कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा राजनीतिक है। यह जिम्मा एमसीडी के पास है न कि दिल्ली सरकार के पास। उन्होंने सफाई का मसला पूरी तरह बरबाद कर दिया है।

उम्मीद है कि अगले साल स्थिति बदलेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में क्रांतिकारी काम हुआ। सफाई में भी करेंगे। साल-डेढ़ साल तो लगेगा लेकिन फिर दिल्ली को साफ कर देंगे।

**संजीव (केरल)—**आप कहते हैं कि केंद्र और पीएम काम नहीं करने देते। क्यों नहीं आप आम जनता के सामने लोगों से वोटिंग कराते कि वे दिल्ली की सरकार अलग चाहते हैं या केंद्र के अधीन?

**अरविंद केजरीवाल—**अच्छा आयडिया है। हम यह करेंगे। रायशुमारी संविधान में नहीं है, लेकिन ओपीनियन पोल कर सकते हैं। लोगों से पूछेंगे कि क्या पुलिस जमीन वगैरह दिल्ली सरकार के अधीन रहे? हम जरूर करायेंगे।

**रवि (गोवा)—**आप क्यों केंद्र सरकार के हमेशा खिलाफ रहते हैं, क्या विकटिम-कार्ड खेल रहे हैं ?

**अरविंद केजरीवाल—**मैंने बताया कि 14 बिलों को कैसे रोका गया, अफसरों का ट्रॉसफर भी सामने है। हम विकिटम नहीं हैं दिल्ली की जनता पीडित है। केंद्र सरकार जिस तरह से बदला ले रही है, उससे दिल्ली के लोग

परेशान हैं। दिल्ली के लोगों को परेशान न किया जाये, हम बस यह चाहते हैं।

**पूजा सोबती (चंडीगढ़) नमस्कार, हमें बड़ी खुशी है कि दिल्ली में आपकी सरकार का काम बहुत अच्छा चल रहा है। दिल्ली में शिक्षकों के लिए जो पॉलिसी है, क्या वैसे ही पंजाब में बनाएंगे ?**

**अरविंद केजरीवाल**—हम लोग जिस तरह दिल्ली में काम कर रहे हैं, वैसे ही बाकी राज्यों में भी करेंगे। आप सबको साथ लेकर करेंगे।

**इंदु भास्कर (दिल्ली)—दिल्ली में ऑड-ईवन क्या फिर होगा ?**

**अरविंद केजरीवाल**—जरूर करेंगे विचार। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने कहा है कि सर्दियों में करेंगे। ऐप-बेस्ड बस सर्विस की स्कीम भी है जिसकी फाइल एलजी साहब के यहां है। इस तरह के कई काम करने होंगे दिल्ली की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए।

**रतन सिंह (दिल्ली)—हर रोज आपके विधायक गिरफ्तार हो जाते हैं। आपके सचिव भी अरेस्ट हुए। क्या आपने बैकग्राउंड चेक नहीं किया था ?**

**अरविंद केजरीवाल**—ये कमांडो सुरेंद्र हैं। 26/11 हमला हुआ तो दिल्ली से जो 200 कमांडो मुंबई भेजे गए, उसमें यह भी थे। इनके सामने बम फटा तो सुनने की ताकत चली गई। कैंट से विधायक हैं। ये एक दिन सड़क पर जा रहे थे तो एक अफसर सब्जी वाले से पैसा मांग रहा था। इन्होंने रोका तो विवाद हुआ और पुलिस ने इनके खिलाफ एस-सी/एस-टी एक्ट की धाराएँ लगाकर जेल भेज दिया। मैं गलत काम बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारे एक मंत्री के बारे में पता चला। उनकी रिकॉर्डिंग मिली तो 24 घंटे में निकालकर सीबीआई में दे दिया। भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि अपने मंत्री को किसी ने इस तरह सीबीआई को सौंपा हो। जबकि मामले का पता मीडिया को भी नहीं था। यह दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। मारे गये तो शहीद कहलाएंगे, जीत गये तो शूरवीर और भागे तो कायर। हम कायर नहीं बनेंगे।

इसी तरह राजेंद्र कुमार जी सीएम दफ़तर में प्रमुख सचिव थे। कहा जा रहा है कि मेरी पुरानी दोस्ती है। मेरी कोई जान पहचान नहीं। मैं आईआईटी खड़गपुर से हूँ और वे

कानपुर से। मैं सीएम बना तो कई पत्रकारों से पूछा कि ईमानदार और इफीशिएंट अफसर कौन है। सबने राजेंद्र जी का नाम लिया तो उन्हें सचिव बनाया। इनके साथ काम करने वाले ईमानदारी की कसमें खाते हैं। उन पर आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया। जाँच चल रही है, अगर उन्होंने गड़बड़ी की है तो टांग दो, दोगुनी सजा दे दो। आरोप लगा रहे हैं कि 2006, 2010 में घोटाला किया। अगर ऐसा है तो उस समय के नेताओं ने किया था भ्रष्टाचार। हमने एफआईआर 49 दिन की सरकार में की थी कॉमनवेल्थ घोटालों की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इनको इसलिए पकड़ा गया, क्योंकि वे मेरे आफिस में थे। अगर वे नहीं होते तो चैलेंज है कि कोई कार्रवाई नहीं करते। ईमानदार अफसर पकड़कर लटका दिया तो मैसेज है कि अफसरों को, कि अगर दिल्ली सरकार का काम किया तो छोड़ेंगे नहीं।

**विशाल डडलानी—ट्विटर पर सवाल है कि अरविंद सर, वाईफाई कहां है..अब तक क्यों नहीं हुआ ?**

**अरविंद केजरीवाल**—वाई-फाई पर काम हो रहा है। कैबिनेट नोट बनकर तैयार है। इसको दो पार्ट में कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में फाइबर ऑप्टिकल का नेटवर्क बिछा रहे हैं। हर घर तक यह जाएगा। इससे तमाम सुविधा मिलेगी जैसे इंटरनेट मिलेगा, केबल टीवी, टेलीफोन जैसी सुविधाएँ। सीसीटीवी भी जुड़ सकेगा। हम टेंडरिंग कर रहे हैं जल्दी, लेकिन दो-तीन साल लगेगा। तब तक फिलहाल हम 'हॉट स्पॉट' का नेटवर्क बना रहे हैं। पूर्वी दिल्ली में दिसंबर या जनवरी तक लागू हो जाएगा।

**विशाल डडलानी—ट्विटर पर अमरेश कुमार पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी को मंजूरी क्यों नहीं दे रहे हैं ?**

**अरविंद केजरीवाल**—इस पर विचार हो रहा है। इसमें प्रस्ताव है कि डीडीए जमीन विकसित करके 60 फीसदी वापस देगा और 40 फीसदी रख लेगा। हमारा कहना है कि जो जमीन डीडीए खुद रखेगा, उसमें दस फीसदी हमें दे दीजिए स्कूल और अस्पताल जैसे चीजें बनाने के लिए। बात हो रही है।

**विशाल डडलानी—हिमांशु दत्ता रोहिणी सेक्टर 6 से पूछ रहे हैं कि खेलों के बारे में क्या सोचा है, इसे बढ़ावा देने के लिए क्या आयडिया है ?**

**मनीष सिसोदिया**—खेलों के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। स्कूलों के मैदान खोल दिए गये हैं। कई जगह ट्रैक बन रहे हैं। स्कूलों में मैदान खाली पड़ा रहता है शाम को, तो अगर कोई एकेडमी चला रहा है तो वहाँ ट्रेनिंग दे सकता है। 77 स्कूलों के मैदान खोले गये हैं। वहाँ सरकारी स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग मुफ्त है। अभी सारे विधानसभा क्षेत्रों में कबड्डी कराई थी। जो खिलाड़ी विदेश जाकर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उनके लिए भी पैसा बढ़ाया है। एक बड़ी चीज है स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी। खेल को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएँगे। खेलने पर भी डिग्री मिलेगी।

**अरविंद केजरीवाल**—मनीष की फिलासफी है कि अगर आप चार साल फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको बीएससी की डिग्री मिलती है, लेकिन चार साल फुटबाल खेलते हो या बास्केटबाल तो कोई बीए डिग्री नहीं मिलती। स्पोर्ट्स युनिवर्सिटी इसीलिए बनाई जा रही है कि डिग्री मिले स्पोर्ट्स में। साथ ही 'मिशन 100' की योजना है जिसमें प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। नेशनल और इंटरनेशनल गेम्स के लिए तैयार किया जाएगा। उनके खाने, पीने, रहने, ट्रैवल का सारा खर्चा सरकार उठाए जाएगी।

**विशाल डडलानी**—ट्विटर पर एक सवाल है कि पंजाब में तमाम एजेंट हैं जो इमीग्रेशन के नाम पर लोगों को लूटते हैं। कनाडा या दूसरी जगहों पर भेजने के नाम पर। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे ?

**अरविंद केजरीवाल**—बिल्कुल, हमारी सरकार बनी तो इनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। जो विदेश जाना चाहते हैं, उनकी सहायता के लिए पंजाब सरकार एक सेल बनाएगी।

**विशाल डडलानी**—सवाल आया है कि सरकारी शिक्षकों को अच्छी तनख्वाह मिलती है, लेकिन शिक्षा की दशा खराब है। शिक्षकों की जवाबदेही के लिए क्या किया जाना चाहिए ?

**अरविंद केजरीवाल**—सरकारी शिक्षकों को वेतन ठीक-ठाक मिलता है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था खराब है, इसलिए वे डिप्रेशन में हैं। उन्हें मोटीवेट करने की जरूरत है। दिल्ली में हमने यह किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि

शिक्षकों के साथ सीएम और डिप्टी सीएम ने मीटिंग की हो और मोटीवेट किया हो। हमने किया। उन्हें कैंब्रिज भेजा, आईआईएम भेजा। अब टीचर को भी काम करने में मजा आने लगा है। इसे ही पंजाब में ही करेंगे, गोवा में भी गुजरात में भी मध्यप्रदेश में, सब जगह।

**अभिषेक (दिल्ली)**—मेरी बहन ने इस साल 12 वीं पास है किया है। मैंने सुना है कि दिल्ली के बच्चों को एडमीशन में रिजर्वेशन मिलेगा और यह शिक्षा लोन कैसे मिल सकता है ?

**मनीष सिसोदिया**—हम लोग बात कर रहे हैं कि जिन 28 कॉलेजों में दिल्ली की जनता के टैक्स का पैसा लगा है, वहाँ कटऑफ में 5 फीसदी छूट मिले। अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। और स्टूडेंट लोन लेना तो बहुत आसान हो गया है। ऑनलाइन अप्लाई करिये और प्रिंटआउट लेकर करीब के बैंक में जाइए, आपका लोन हो जाएगा, आपको किसी गारंटी की जरूरत नहीं है।

**अमन झा (दिल्ली)**—सड़कों का बुरा हाल है, कैसे ठीक होंगी ?

**अरविंद केजरीवाल**—60 फिट से चौड़ी रोड दिल्ली सरकार की हैं, उससे कम चौड़ी एमसीडी की हैं। पीडब्ल्यूडी ने अपनी सारी सड़कें दुरुस्त कर दी हैं। बरसात के बाद फिर देखेंगे अगर कहीं खराब हुई तो। 60 फिट से कम चौड़ी सड़कों का वाकई बुरा हाल है। जब एमसीडी पर हमारा नियंत्रण होगा तो वहाँ भी सारी सड़कें प्राथमिकता से दुरुस्त करा दी जाएँगी।

**विशाल डडलानी**—एक सवाल आया है, अब अगला 'टॉक टू ए.के.' कब होगा ?

**अरविंद केजरीवाल**—महीने-डेढ़ महीने में करेंगे। आप लोग अगली बार सवाल ही न पूछें, सुझाव भी दें।

**विशाल डडलानी**—जितने भी मैसेज आये हैं, उन सबको जवाब दिया जाएगा। बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे तमाम सवाल जिनकी चर्चा सिर्फ ट्विटर पर होती है, आज यहाँ उनके जवाब मिले।

धन्यवाद ■

# 70वें स्वतंत्रता दिवस पर विशेष

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गीतों और कविताओं की बड़ी भूमिका रही है। उस दौरान ऐसे तमाम तराने लोगों की जवान पर थे, जिनके रचनाकारों का पता नहीं था। वैसे भी क्रांतिकारी विचारों वाले साहित्य को जब्त करना और रचयिता को जेल भेज देना, अंग्रेजों के लिए आम बात थी। पढ़िये, उस दौर के अज्ञात रचनाकारों के ऐसे ही तीन गीत—

## स्वतंत्र भारत

अहाहा गाँधी के मुँह से निकला  
स्वतंत्र भारत ! स्वतंत्र भारत !  
सुना सभी ने सचेत होकर  
स्वतंत्र भारत ! स्वतंत्र भारत !

विशाल लौ पूर लिक्खी दिल में  
महासभा के वितान तल में,  
कहा यह मोहन ने रावी तट पर  
स्वतंत्र भारत ! स्वतंत्र भारत !

समय था उनतीस सन का आखिर  
पर मस्त थे राजमद में शासक,  
सुनाया गाँधी ने तब गरजकर  
स्वतंत्र भारत ! स्वतंत्र भारत !

समीर में, नीर में, गगन में  
वचन में, तन में, हरेक मन में  
समा गया वो महा मधुर सुर  
स्वतंत्र भारत ! स्वतंत्र भारत !

हर एक घर में मची हुई है  
स्वतंत्रता की अजीब हलचल,  
यह कहते बच्चे गुहार कर—कर  
स्वतंत्र भारत ! स्वतंत्र भारत !

स्वतंत्रता के लिए सभी के  
दिलों में जलती है आग भारी  
हैं देखते ख्वाब में भी पड़कर  
स्वतंत्र भारत ! स्वतंत्र भारत !

बना के कुटिया स्वतंत्रता की  
सपूत जेलों में रम रहे हैं  
तपस्वी देखेंगे अब निकलकर  
स्वतंत्र भारत ! स्वतंत्र भारत !

कुमारी, हिमगिरि, अटक, कटक तक  
बजेगा डंका स्वतंत्रता का  
कहेंगे तैतीस करोड़ मिलकर  
स्वतंत्र भारत ! स्वतंत्र भारत !

उड़ेगा दुनिया में सबसे ऊँचा  
विशाल झंडा स्वतंत्रता का,  
कहेंगे नर—नारी जग के लखकर  
स्वतंत्र भारत ! स्वतंत्र भारत !

रहा हमेशा स्वतंत्र भारत,  
रहेगा फिर भी स्वतंत्र भारत,  
प्रकाश बाँटेगा विश्व को फिर  
स्वतंत्र भारत ! स्वतंत्र भारत !



# स्वदेशी गाढ़ा

# भारत है जान हमारी

मुझे गाढ़ा स्वदेशी मंगा दो सजन !

है फैली काहिली दुनिया जहान में सारे,  
इसी ख्याल से मेरे ख्याल हैं न्यारे  
तमाम दिन मेरा बेकार गुजरे है प्यारे,

मैं तो कातूँगी चरखा करूँगी भजन  
मुझे गाढ़ा स्वदेशी मंगा दो सजन !

इसी की साड़ियाँ—चादर—कमीज बनवाना  
इसी का कोट—ओ—कुरता बनाओ मनमाना,  
इसी की टोपियाँ, अचकन, रजाई बनवाना,

जो सुधारा चाहो तुम अपना वतन  
मुझे गाढ़ा स्वदेशी मंगा दो सजन !

रुई की कद्र विलायत में लोग करते हैं,  
इसी के जोर से दुनिया में कब वो डरते हैं,  
हमारे मुल्क से लेकर जहाज भरते हैं

है यह नजरों से हल्की, पै भारी वजन  
मुझे गाढ़ा स्वदेशी मंगा दो सजन !

अज्ञात ■

भारत है जान हमारी और जान है तो सब कुछ  
ईमान है हमारा, ईमान है तो सब कुछ ।

मिट्टी से, जिसकी पलकर हम सब बड़े हुए हैं  
इसके लिए मरेंगे, यह शान है तो सब कुछ ।

खंजर चले, चले गर, उफ भी नहीं करेंगे  
परतंत्रता में रहकर बस जान है तो सब कुछ ।

आए अजल भले ही, फिर भी न हम डरेंगे  
डरकर न हम हटेंगे, यह आन है तो सब कुछ ।

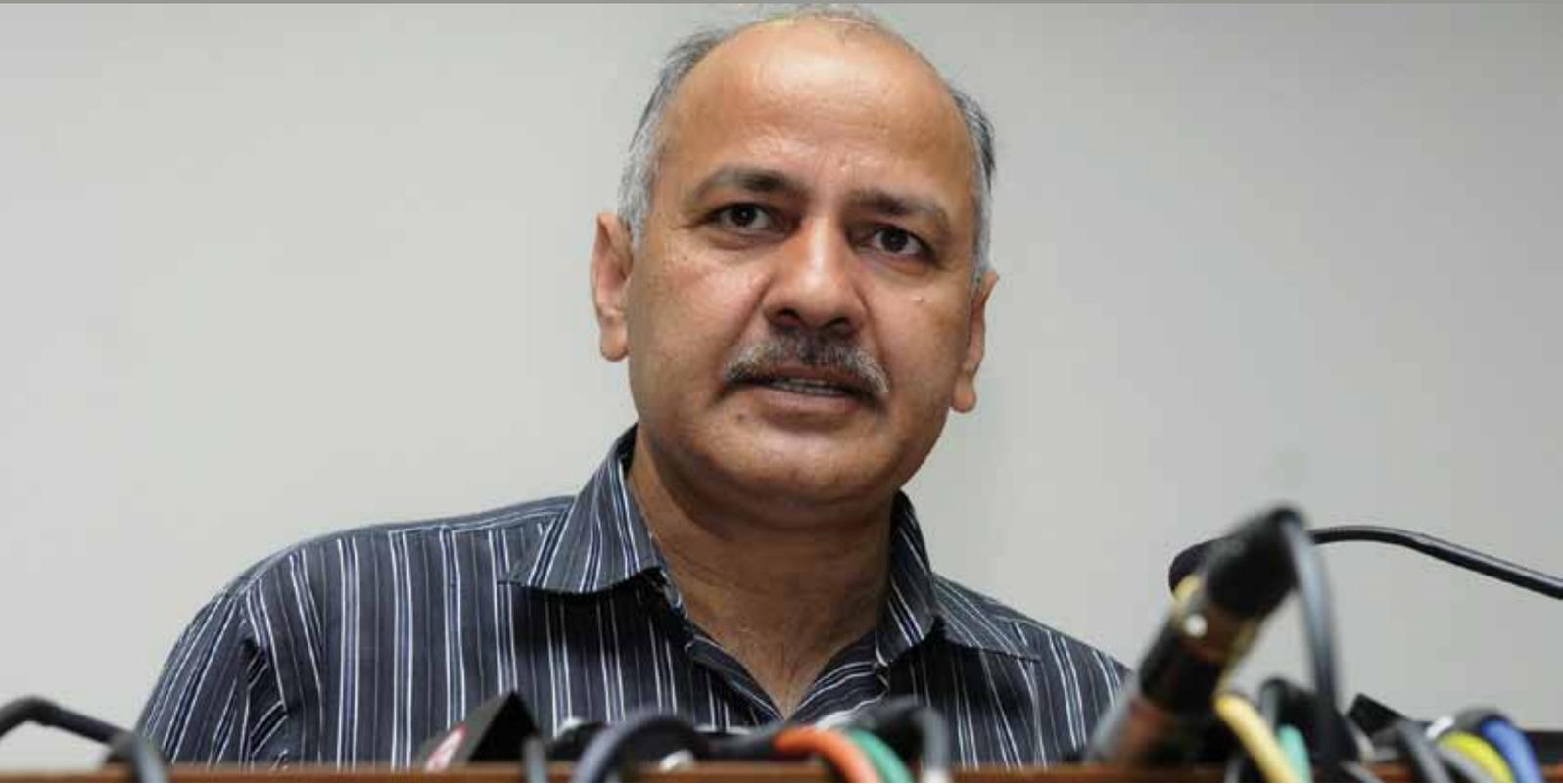
मजहब जुदा है लेकिन अहले—वतन सभी हैं  
तन, प्राण, धन, वतन पर कुर्बान है तो सब कुछ

मरना वतन पे सीखे, जीना वतन पे सीखे,  
इंसान में अगर ये अरमान है तो सब कुछ ।

अज्ञात ■

# 10 वीं में 100% रिज़ल्ट का लक्ष्य

नौवीं में फ़ेल होने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान



पढ़ाई-लिखाई में बेहद कमजोर रहने के बावजूद लाखों बच्चे आराम से कक्षा नौ में पहुँच जाते हैं। वजह है ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’। इस नीति के तहत बच्चों को निचली कक्षाओं में फेल नहीं किया जा सकता। नतीजा यह है कि आठवीं के बच्चे कक्षा नौ में पहुँच जाते हैं लेकिन उन्हें कक्षा पाँच के स्तर का भी ज्ञान नहीं होता। नौवीं में पहुँचने पर अचानक बच्चों पर पढ़ाई का बोझ पड़ता है और वे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने में जुटी दिल्ली सरकार ने ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ खत्म करने का बिल विधानसभा से पास कर दिया था, लेकिन केंद्र ने इसे मंजूरी नहीं दी।

बहराहल, दिल्ली सरकार ने मंजूरी के इंतजार करने के बजाय कुछ करने की ठानी है। उसके इस संकल्प का नाम है ‘चुनौती 2018’। मतलब यह कि सरकारी स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का स्तर उन्नत करना, खासतौर पर जो 2018 में हाईस्कूल की परीक्षा में बैठेंगे। रिजल्ट बेहतर हो, इसलिए कमजोर बच्चों को चिन्हित करके उनकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

दिल्ली सरकार की इस महात्वाकांक्षी योजना के तहत –

1. बच्चों की जरूरत और पढ़ाई में कमजोरी के हिसाब से विशेष ग्रुप बनाए जाएंगे।



2. उनका बेसलाइन असेसमेंट होगा।
3. इस काम में सबसे अच्छे शिक्षकों को लगाया जाएगा।
4. जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त अतिथि शिक्षक नियुक्त होंगे।
5. फेल हुए बच्चों की मैपिंग होगी ताकि जो बच्चे 9 वीं में फेल होकर स्कूल छोड़ गए हैं, उनको वापस मुख्यधारा में लाया जा सके।
6. इन बच्चों को आम दिनों में आम बच्चों की ही तरह पढ़ाया जाएगा ताकि उनमें कोई हीन भावना न आए।
7. 9वीं में फेल हुए बच्चे को अपना स्कूल बदलने की सुविधा दी जाएगी
8. जो शिक्षक बच्चों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने में अच्छे नतीजे देंगे उनको इनाम मिलेगा।
9. पिछले दो साल में 9 वीं में फेल हुए बच्चों को सरकार फिर से पढ़ने का मौका देगी।
10. पत्राचार में पढ़ने वाले बच्चों को भी इसमें मौका दिया जाएगा। वे भी रेग्युलर कक्षाओं में पढ़कर इम्तिहान दे सकते हैं।

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि 6, 7, 8, 9, 10वीं की शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर खराब पाया गया

है। 'नो डिटेंशन पॉलिसी' इसका एक बड़ा कारण है। अचानक पड़ने वाला बोझ बच्चे बरदाश्त नहीं कर पाते और नौवीं कक्षा में फेल हो जाते हैं।

शिक्षामंत्री ने बताया कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में पिछले 3 सालों में यानी 2013-14 में 44 फीसदी, 2014-15 में 48.5 फीसदी और 2015-16 में 50 फीसदी बच्चे फेल हुए। फेल होने के कारण बहुत से बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं या पत्राचार की ओर रुख कर लेते हैं। सरकार ऐसे बच्चों में पढ़ाई-लिखाई के प्रति रुचि जगाने और उनके अध्ययन का स्तर बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्ध है। वे स्वयं एक-एक बच्चे के रिजल्ट पर नजर रखेंगे।

श्री सिसोदिया ने बताया कि बच्चों के स्तर का मूल्यांकन करके उन्हें समूहों में विभाजित किया जाएगा। 24000 प्रशिक्षित शिक्षक एडीशनल लर्निंग मैटीरियल की मदद से इन बच्चों को उनकी कक्षा के योग्य बनाएँगे।

नौवीं कक्षा में दो या उससे ज्यादा बार फेल होने वालो छात्र मॉडीफाइड पत्राचार स्कीम एक्जामिनेशन (एमपीएसई) के जरिये 10 वीं कक्षा की परीक्षा दे सकेंगे। सरकार को उम्मीद है कि चुनौती 2018 का प्रयोग सरकारी स्कूलों की छवि बदल देगा। ■



# दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम का आयोजन

## पीटीएम को बनाएँगे पाठ्यक्रम का हिस्सा—मनीष सिसोदिया

‘दिल्ली के सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से बेहतर बनाना है’—दिल्ली सरकार का यह संकल्प अब शकल लेने लगा है और हर कोई इसे महसूस भी कर रहा है। इसी प्रयास में 31 जुलाई को दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में मेगा पैरेंट्स टीचर्स मीटिंग (पीटीएम) का आयोजन हुआ। प्राइवेट स्कूलों में तो पीटीएम का आयोजन हर महीने होता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में ऐसा पहली बार हुआ। छात्रों और अभिभावकों ने बड़े उत्साह से इसमें भाग लिया। पीटीएम की कामयाबी से उत्साहित सरकार ने कहा है कि आने वाले दिनों में सरकारी स्कूलों में पीटीएम जल्दी-जल्दी आयोजित की जाएँगी।

दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर बदलने में जुटे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया खुद कई स्कूलों में गए और शिक्षकों तथा अभिभावकों से बात की। दिल्ली के सरकारी

स्कूलों में पढ़ रहे 16 लाख बच्चों और उनके अभिभावकों के जीवन की यह अनोखी घटना थी जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कई अभिभावकों ने कहा कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में हमेशा शिक्षकों और प्रधानाचार्यों से बात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता था। उन्होंने



उपमुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया कि दिल्ली सरकार शिक्षा क्षेत्र का माहौल बदल रही है। कुछ अभिभावक तो बातचीत में काफी भावुक हो गये। कुछ विद्यालयों के पूर्व छात्र भी अभिभावक बतौर पीटीएम में हिस्सा लेने पहुँचे थे। उन्होंने कहा कि काश, उनके समय भी ऐसा किया गया होता।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ऐसे तमाम प्रयोग आगे भी करेगी। मकसद यही है कि लोग निजी विद्यालयों का मोह छोड़ें और सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ायें। उन्होंने कहा कि अभी साल में दो बार मेगा पीटीएम आयोजित

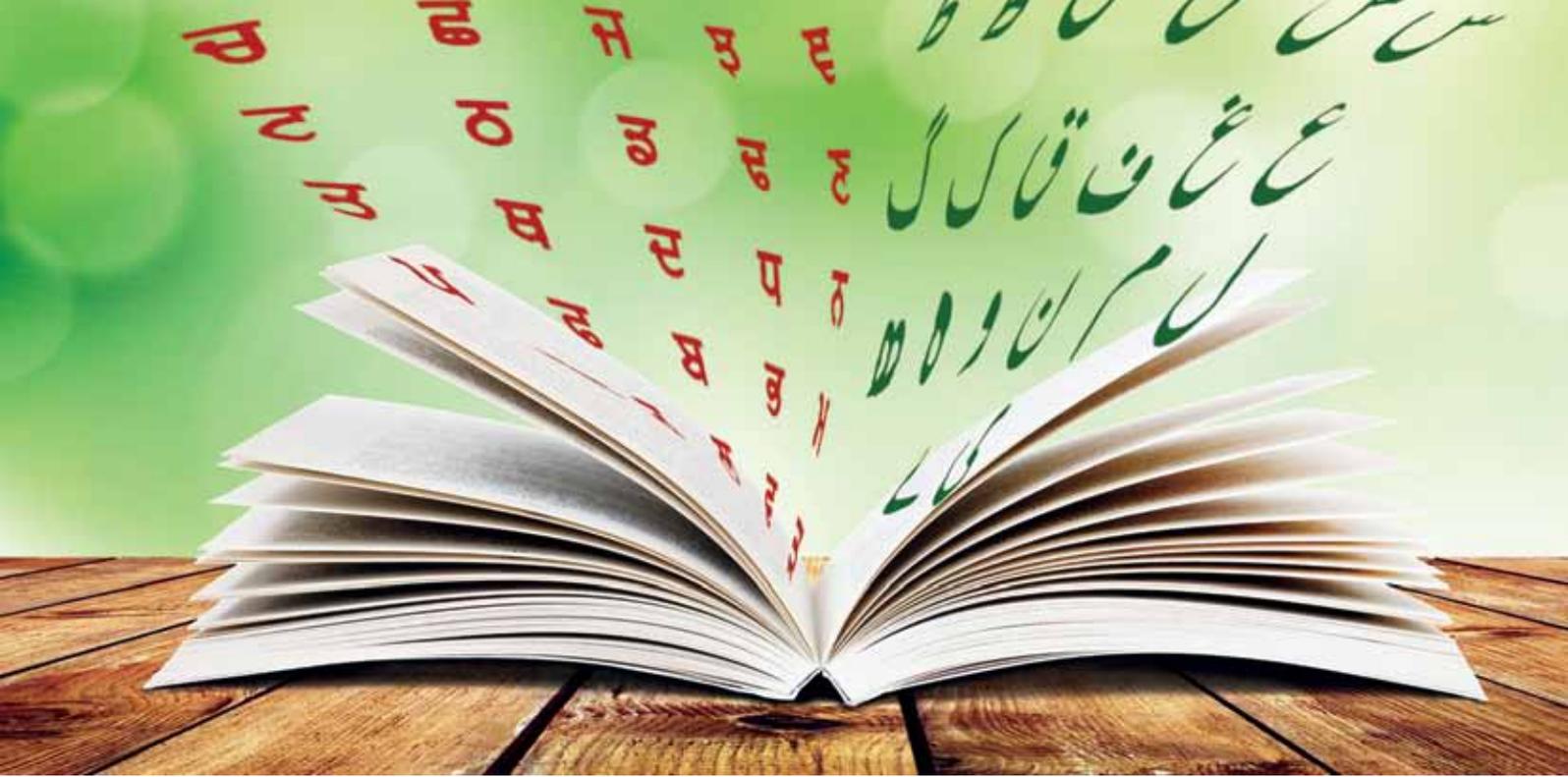
करने की योजना है, लेकिन आगे इसे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। मेगा पीटीएम के दौरान सुबह चलने वाले स्कूलों में सुबह 8 बजे से और दोपहर के स्कूलों में 2 बजे से बैठक शुरू हुई। इस मौके पर स्कूलों को सुंदर तरीके से सजाया गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उत्सव हो। अभिभावकों ने मीटिंग में अपने बच्चों की पढ़ाई की जानकारी तो ली ही, साथ ही स्कूलों के माहौल और इन्फ्रास्ट्रक्चर में आ रहे बदलावों का भी जायजा लिया। दिल्ली सरकार अपने बजट का करीब 18 फीसदी शिक्षा पर खर्च कर रही है और उसका नतीजा साफ महसूस किया जा सकता है।

मेगा पीटीएम जैसी अनूठी पहल और कामयाबी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बेहद खुशी जताई।

उन्होंने अपने संदेश में कहा कि सरकारी स्कूलों को लेकर बनी धारणा को बदलना एक चुनौती है जिसे उनकी सरकार ने कबूल किया है।

मेगा पीटीएम को सफलता यूँ ही नहीं मिली। कुछ प्रधानाचार्यों के मुताबिक पहले जब कभी अभिभावकों को मीटिंग के लिए बुलाया जाता था, वे रुचि नहीं

दिखाते थे। वजह यह है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादातर गरीब तबके के हैं जिनके माँ-बाप को खुद काम से छुट्टी नहीं मिलती, और उनमें बहुत से शिक्षित भी नहीं हैं। लेकिन इस बार लगातार प्रचार किया गया। एसएमएस भेजे गये और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से भी रेडियो समेत विभिन्न माध्यमों से आह्वान किया गया। बच्चों में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखा और उन्होंने भी अभिभावकों पर दबाव डाला कि वे स्कूल की नई धज चलकर खुद देखें।



# शिक्षकों के अभाव में नहीं छूटेगी उर्दू और पंजाबी की पढ़ाई

दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों को मिले पंजाबी और उर्दू शिक्षक  
उर्दू के 601 और पंजाबी के 769 शिक्षकों की नियुक्ति पर कैबिनेट की मुहर

**उ**र्दू और पंजाबी भाषा के महत्व को समझते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूलों में 601 उर्दू और 769 पंजाबी भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। ऐसा करने से दिल्ली के हर सरकारी स्कूल में उर्दू एवं पंजाबी भाषा की शिक्षा देने के लिए कम से कम एक शिक्षक मौजूद रहेगा।

शिक्षामंत्री मनीष सिसौदिया का कहना है कि दिल्ली के विद्यार्थी अब केवल इस नाम पर उर्दू या पंजाबी भाषा पढ़ना नहीं छोड़ेंगे कि स्कूल में इन भाषाओं को पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं हैं। दिल्ली सरकार भारतीय भाषाओं को लेकर काफी संजीदा है और यह फैसला उसी का एक उदाहरण है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद

केजरीवाल ने 24 मई 2006 को निर्णय लिया कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में संस्कृत भाषा के अलावा माध्यमिक स्तर पर उर्दू और पंजाबी के शिक्षक भी होंगे। फिलहाल दिल्ली में 1042 सरकारी स्कूल हैं जिसमें 24 प्रतिशत स्कूलों में पंजाबी पढ़ाई जाती है, जबकि 25 फीसदी स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जाती है। शैक्षिक वर्ष 2015-16 में प्रवेश के समय तकरीबन 28,612 विद्यार्थियों ने पंजाबी भाषा एवं 82,341 विद्यार्थियों ने उर्दू भाषा का चयन किया। दिल्ली सरकार के इस फैसले से पंजाबी और उर्दू भाषा से प्रेम करने वालों में खुशी की लहर है। उनका कहना है कि इस फैसले से मूल रूप से पंजाबी और उर्दूभाषी घरों के बच्चों को अपनी मातृभाषा के व्याकरण और साहित्य से परिचित होने का मौका मिलेगा। इससे व्यक्तित्व विकास में उनके लिए संभावनाओं के कई और द्वार खुलेंगे। ■

मुंशी प्रेमचंद के जन्मदिन (31 जुलाई) पर विशेष

# सांप्रदायिकता हमेशा संस्कृति की खाल ओढ़कर आती है-प्रेमचंद

**सा**म्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती है। उसे अपने असली रूप में निकलने में शायद लज्जा आती है, इसलिए वह उस गधे की भाँति जो सिंह की खाल ओढ़कर जंगल में जानवरों पर रोब जमाता फिरता था, संस्कृति का खोल ओढ़कर आती है। हिन्दू अपनी संस्कृति को कयामत तक सुरक्षित रखना चाहता है, मुसलमान अपनी संस्कृति को। दोनों ही अभी तक अपनी-अपनी संस्कृति को अछूती समझ रहे हैं, यह भूल गये हैं कि अब न कहीं हिन्दू संस्कृति है, न मुस्लिम संस्कृति और न कोई अन्य संस्कृति। अब संसार में केवल एक संस्कृति है, और वह है आर्थिक संस्कृति मगर आज भी हिन्दू और मुस्लिम संस्कृति का रोना रोये चले जाते हैं। हालाँकि संस्कृति का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं। आर्य संस्कृति है, ईरानी संस्कृति है, अरब संस्कृति है। हिन्दू मूर्तिपूजक हैं, तो क्या मुसलमान कब्रपूजक और स्थान पूजक नहीं है। ताजिये को शर्बत और शीरीनी कौन चढ़ाता है, मस्जिद को खुदा का घर कौन समझता है। अगर मुसलमानों में एक सम्प्रदाय ऐसा है, जो बड़े से बड़े पैगम्बरों के सामने सिर झुकाना भी कुफ्र समझता है, तो हिन्दुओं में भी एक ऐसा है जो देवताओं को पत्थर के टुकड़े और नदियों को पानी की धारा और धर्मग्रन्थों को गपोड़े समझता है। यहाँ तो हमें दोनों संस्कृतियों में कोई अन्तर नहीं दिखता।

तो क्या भाषा का अन्तर है? बिल्कुल नहीं। मुसलमान उर्दू को अपनी मिल्ली भाषा कह लें, मगर मद्रासी मुसलमान के लिए उर्दू वैसी ही अपरिचित वस्तु है जैसे मद्रासी हिन्दू के लिए संस्कृत। हिन्दू या मुसलमान जिस प्रान्त में रहते हैं सर्वसाधारण की भाषा बोलते हैं चाहे वह उर्दू हो या हिन्दी, बंगला हो या मराठी। बंगाली मुसलमान उसी तरह उर्दू नहीं बोल सकता और न समझ सकता है, जिस तरह बंगाली हिन्दू। दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। सीमाप्रान्त का हिन्दू उसी तरह पश्तो बोलता है, जैसे वहाँ का मुसलमान।

फिर क्या पहनावे में अन्तर है? सीमाप्रान्त के हिन्दू और मुसलमान स्त्रियों की तरह कुर्ता और ओढ़नी पहनते-ओढ़ते हैं। हिन्दू पुरुष भी मुसलमानों की तरह कुलाह और पगड़ी बाँधता है। अक्सर दोनों ही दाढ़ी भी रखते हैं। बंगाल में जाइये, वहाँ हिन्दू और मुसलमान स्त्रियाँ दोनों ही साड़ी पहनती हैं, हिन्दू और मुसलमान पुरुष दोनों कुर्ता और धोती पहनते हैं तहमद की प्रथा बहुत हाल में चली है, जब से साम्रदायिकता ने जोर पकड़ा है।

खान-पान को लीजिए। अगर मुसलमान मांस खाते हैं तो हिन्दू भी अस्सी फीसदी मांस खाते हैं। ऊँचे दरजे के हिन्दू भी शराब पीते हैं, ऊँचे दर्जे के मुसलमान भी। नीचे दर्जे के हिन्दू भी शराब पीते हैं नीचे दर्जे के मुसलमान भी। मध्यवर्ग के हिन्दू या तो बहुत कम शराब पीते हैं, या भंग के गोले चढ़ाते हैं जिसका नेता हमारा पण्डा-पुजारी क्लास है। मध्यवर्ग के मुसलमान भी बहुत कम शराब पीते हैं, हाँ कुछ लोग अफीम की पीनक अवश्य लेते हैं, मगर इस पीनकबाजी में हिन्दू भाई मुसलमानों से पीछे नहीं है। हाँ, मुसलमान गाय की कुर्बानी करते हैं और उनका मांस खाते हैं लेकिन हिन्दुओं में भी ऐसी जातियाँ मौजूद हैं, जो गाय का मांस खाती हैं यहाँ तक कि मृतक मांस भी नहीं छोड़तीं, हालांकि बधिक और मृतक मांस में विशेष अन्तर नहीं है। संसार में हिन्दू ही एक जाति है, जो गो-मांस को अखाद्य या अपवित्र समझती है। तो क्या इसलिए हिन्दुओं को समस्त विश्व से धर्म-संग्राम छेड़ देना चाहिए?

संगीत और चित्रकला भी संस्कृति का एक अंग है, लेकिन यहाँ भी हम कोई सांस्कृतिक भेद नहीं पाते। वही राग-रागनियाँ दोनों गाते हैं और मुगलकाल की चित्रकला से भी हम परिचित हैं। नाट्य कला पहले मुसलमानों में न रही हो, लेकिन आज इस सींगे में भी हम मुसलमान को उसी तरह पाते

हैं जैसे हिन्दुओं को। फिर हमारी समझ में नहीं आता कि वह कौन सी संस्कृति है, जिसकी रक्षा के लिए साम्प्रदायिकता इतना जोर बाँध रही है। वास्तव में संस्कृति की पुकार केवल ढोंग है, निरा पाखण्ड। यह सीधे-सादे आदमियों को साम्प्रदायिकता की ओर घसीट लाने का केवल एक मन्त्र है और कुछ नहीं। हिन्दू और मुस्लिम संस्कृति के रक्षक वही महानुभाव और वही समुदाय हैं, जिनको अपने ऊपर, अपने देशवासियों के ऊपर और सत्य के ऊपर कोई भरोसा नहीं, इसलिए अनन्त तक एक ऐसी शक्ति की जरूरत समझते हैं जो उनके झगड़ों में सरपंच का काम करती रहे।

इन संस्थाओं को जनता को सुख-दुख से कोई मतलब नहीं, उनके पास ऐसा कोई सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है जिसे राष्ट्र के सामने रख सकें। उनका काम केवल एक-दूसरे का विरोध करके सरकार के सामने फरियाद करना है। वे ओहदों और रियायतों के लिए एक-दूसरे से चढ़ा-ऊपरी करके जनता पर शासन करने में शासक के सहायक बनने के सिवा और कुछ नहीं करते।

मुसलमान अगर शासकों का दामन पकड़कर कुछ रियायतें पा गया है तो हिन्दू क्यों न सरकार का दामन पकड़ें और क्यों न मुसलमानों की भाँति सुखरू बन जायें। यही उनकी मनोवृत्ति है। कोई ऐसा काम सोच निकालना जिससे हिन्दू और मुसलमान दोनों एक राष्ट्र का उद्धार कर सकें, उनकी विचार शक्ति से बाहर है। दोनों ही साम्प्रदायिक संस्थाएँ मध्यवर्ग के धनिकों, जमींदारों, ओहदेदारों और पदलोलुपों की हैं। उनका कार्यक्षेत्र अपने समुदाय के लिए ऐसे अवसर प्राप्त करना है, जिससे वह जनता पर शासन कर सकें, जनता पर आर्थिक और व्यावसायिक प्रभुत्व जमा सकें। साधारण जनता के सुख-दुख से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। अगर सरकार की किसी नीति से जनता को कुछ लाभ होने की आशा है और इन समुदायों को कुछ क्षति पहुँचने का भय है, तो वे तुरन्त उसका विरोध करने को तैयार हो जायेंगे। अगर और ज्यादा गहराई तक जायें तो हमें इन संस्थाओं में अधिकांश ऐसे सज्जन मिलेंगे जिनका कोई न कोई निजी हित लगा हुआ है। और कुछ न सही तो हुक्काम के बंगलों पर उनकी रसोई ही सरल हो जाती है। एक विचित्र बात

है कि इन सज्जनों की अफसरों की निगाह में बड़ी इज्जत है, इनकी वे बड़ी ख़ातिर करते हैं।

इसका कारण इसके सिवा और क्या है कि वे समझते हैं, ऐसों पर ही उनका प्रभुत्व टिका हुआ है। आपस में खूब लड़े जाओ, खूब एक-दूसरे को नुकसान पहुँचाये जाओ। उनके पास फरियाद लिये जाओ, फिर उन्हें किसका नाम है, वे अमर हैं। मजा यह है कि बाजों ने यह पाखण्ड फैलाना भी शुरू कर दिया है कि हिन्दू अपने बूते पर स्वराज प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास से उसके उदाहरण भी दिये जाते हैं। इस तरह की गलतहमियाँ फैला कर इसके सिवा कि मुसलमानों में और ज्यादा बदगुमानी फैले और कोई नतीजा नहीं निकल सकता। अगर कोई जमाना था, तो कोई ऐसा काल भी था, जब हिन्दुओं के जमाने में मुसलमानों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था, उन जमानों को भूल जाइये। वह मुबारक दिन होगा, जब हमारे शालाओं में इतिहास उठा दिया जायेगा। यह जमाना साम्प्रदायिक अभ्युदय का नहीं है। यह आर्थिक युग है और आज वही नीति सफल होगी जिससे जनता अपनी आर्थिक समस्याओं को हल कर सके जिससे यह अन्धविश्वास, यह धर्म के नाम पर किया गया पाखण्ड, यह नीति के नाम पर गरीबों को दुहने की कृपा मिटाई जा सके। जनता को आज संस्कृतियों की रक्षा करने का न अवकाश है न जरूरत। 'संस्कृति' अमीरों, पेटभरों का बेफिक्रों का व्यसन है। दरिद्रों के लिए प्राणरक्षा ही सबसे बड़ी समस्या है।

उस संस्कृति में था ही क्या, जिसकी वे रक्षा करें। जब जनता मूर्च्छित थी तब उस पर धर्म और संस्कृति का मोहछाया हुआ था। ज्यों-ज्यों उसकी चेतना जागृत होती जाती है वह देखने लगी है कि यह संस्कृति केवल लुटेरों की संस्कृति थी जो, राजा बनकर, विद्वान बनकर, जगत सैठ बनकर जनता को लूटती थी। उसे आज अपने जीवन की रक्षा की ज्यादा चिन्ता है, जो संस्कृति की रक्षा से कहीं आवश्यक है। उस पुरान संस्कृति में उसके लिए मोह का कोई कारण नहीं है। और साम्प्रदायिकता उसकी आर्थिक समस्याओं की तरफ से आँखें बन्द किये हुए ऐसे कार्यक्रम पर चल रही है, जिससे उसकी पराधीनता चिरस्थायी बनी रहेगी।

(यह लेख 15 जनवरी 1934 को प्रकाशित हुआ) ■

“ यह आर्थिक युग है और आज वही नीति सफल होगी जिससे जनता अपनी आर्थिक समस्याओं को हल कर सके जिससे यह अन्धविश्वास, यह धर्म के नाम पर किया गया पाखण्ड, यह नीति के नाम पर गरीबों को दुहने की कृपा मिटाई जा सके। जनता को आज संस्कृतियों की रक्षा करने का न अवकाश है न जरूरत। 'संस्कृति' अमीरों, पेटभरों का, बेफिक्रों का व्यसन है। दरिद्रों के लिए प्राणरक्षा ही सबसे बड़ी समस्या है। ”

दिल्ली सरकार ने बनाया डॉ. कलाम की याद में संग्रहालय

# दिल्ली लौट आये कलाम सर



दिल्ली सरकार ने अपना वादा पूरा किया और कलाम सर वापस दिल्ली लौट आये। जी हाँ, दिल्ली हाट में भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का संग्रहालय बनकर तैयार हो गया है जहाँ उनसे जुड़ी तमाम चीजों को देखा जा सकता है। इसे 'कलाम स्मारक' का नाम दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 30 जुलाई को इस 'कलाम स्मारक' का उद्घाटन किया।

'कलाम स्मारक' में डॉ. कलाम के बचपन से लेकर मिसाइल मैन बनने और फिर देश के राष्ट्रपति बनने तक के सफर और उपलब्धियों को तस्वीरों के जरिये प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा डॉ. कलाम की किताबें, उनकी लिखावट, उनके कपड़े, बाल संवारने वाली कंधी,

टीशर्ट, चश्मे सहित निजी इस्तेमाल की कई चीजें भी वहाँ मौजूद हैं। डॉ. कलाम के तमाम संदेशों को बेहद सुंदर तरीके से संग्रहालय में जगह-जगह उकेरा गया है।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यह संग्रहालय देश को समर्पित करते हुए कहा कि इससे आने वाली पीढ़ियाँ डॉ. कलाम से प्रेरणा ले सकेंगी। वे आम आदमी के राष्ट्रपति थे। एक ईमेल भेज देने पर उनसे मिलने का वक्त मिल जाता था। वे हमेशा चाहते थे कि वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं, उन्हें एक शिक्षक के रूप में याद किया जाए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दिल्ली में संग्रहालय खोलने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाने वाली संस्था को भी सम्मानित किया।

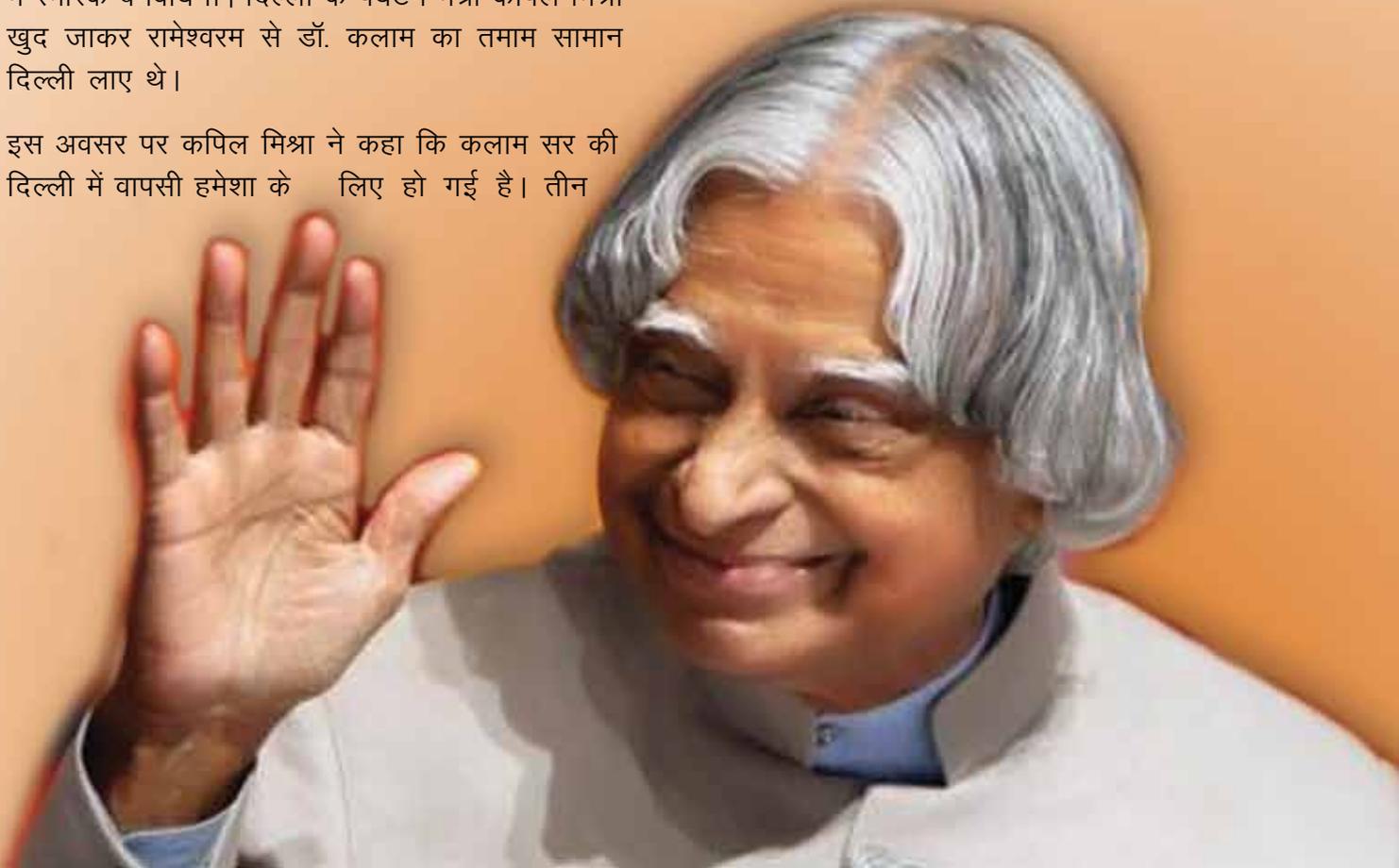
वहीं उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि डॉ. कलाम को गीता, कुरान और विज्ञान, तीनों की व्याख्या करने में



महारात हासिल थी। दिल्ली सरकार, शिक्षा को लेकर डॉ. कलाम के विचारों पर अमल करने का पूरा प्रयास करेगी। कार्यक्रम के दौरान डॉ. कलाम के परिवार के लोग भी मौजूद थे। गौरतलब है कि 27 जुलाई 2015 को शिलांग में एक सेमिनार में भाषण देते वक्त डॉ. कलाम का निधन हो गया था। इसके बाद परिवार ने दिल्ली में उनका संग्रहालय बनाने की माँग की थी लेकिन उनके सामान को उनके पैतृक स्थान रामेश्वरम भेज दिया गया था। तब दिल्ली सरकार ने संकल्प लिया था कि वह डॉ. कलाम की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए देश की राजधानी में स्मारक बनवायेगी। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा खुद जाकर रामेश्वरम से डॉ. कलाम का तमाम सामान दिल्ली लाए थे।

इस अवसर पर कपिल मिश्रा ने कहा कि कलाम सर की दिल्ली में वापसी हमेशा के लिए हो गई है। तीन

महीने के छोटे से अंतराल में दिल्ली सरकार ने यह संग्रहालय बनवा दिया। भविष्य में उनसे जुड़ी जो भी चीज मिलेगी उसे संग्रहालय में लाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में 3D होलोग्राम की तकनीक लाने की योजना है ताकि लोग कलाम साहब के विचारों को लाइव सुन सकें। 'कलाम स्मारक' सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेगा और यहाँ मुफ्त प्रवेश मिलेगा। सरकार का कहना है कि 'कलाम स्मारक' को रिसर्च सेंटर बनाने के लिए सुझाव मिला है। सरकार आने वाले दिनों में इस पर विचार करेगी। ■



# पूरे भारत में खुलें दिल्ली जैसे

## मोहल्ला क्लीनिक-जस्टिस काटजू

(जस्टिस मार्कण्डेय काटजू सुप्रीम कोर्ट से अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं। वे अपनी बेलाग टिप्पणियों के लिए मशहूर हैं। पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली के दो मोहल्ला क्लीनिकों का औचक निरीक्षण किया और पाया कि यह बेहद कारगर हैं। उन्होंने इसकी प्रशंसा अपने ब्लॉग 'सत्यम बुआत' में की। हम इसे साभार यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं।)

**मैं** ने आम आदमी सरकार की ओर से बनाये गये मोहल्ला क्लीनिकों के बारे में सुना था, लेकिन कभी खुद जाकर नहीं देखा था। इसलिए मैंने औचक निरीक्षण करने का फैसला किया और जाकिर नगर में मस्जिद नूह के पीछे और ओखला के जोगाबाई एक्सटेंशन में चल रहे क्लीनिकों को जाकर देखा।

ये क्लीनिक काफी भीड़भाड़ वाले इलाकों में हैं जहाँ पहुँचने के लिए मुझे तंग गलियों से गुजरना पड़ा। यह स्वाभाविक है कि बड़ी तादाद में गरीब लोग वहाँ रहते हैं।

सबसे पहले मैं जाकिर नगर के क्लीनिक पहुँचा। मुझे वहाँ डॉक्टर मिर्जा आजम बेग मिले जिन्होंने मुझे पहुँचाना। डॉ. बेग काफी मिनलसार लगे। उन्होंने मुझे क्लीनिक के बारे में निम्नलिखित तथ्य बताये—

- क्लीनिक सुबह 9 बजे से 1 बजे तक खुलता है और 50–80 मरीजों का रोजाना इलाज होता है।
- मरीजों के लिए करीब 80–85 तरह की दवायें उपलब्ध हैं जिसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता। इनमें डायबिटीज, हायपरटेंशन, थायरॉयड की दवायें भी हैं और मेडिकल जाँच भी पूरी तरह मुफ्त है।
- मोहल्ला क्लीनिक में 200 तरह की जाँच हो सकती है।
- यहाँ तैनात डाक्टर अनुबंध पर हैं और दिल्ली सरकार उन्हें 30 रुपये प्रति मरीज के हिसाब से देती है।



- क्लीनिक में एक पैथोलजिस्ट और एक एएनएम भी तैनात है। यहां तमाम तरह का टीका भी लगता है।
- क्लीनिक में कोई एक्स-रे मशीन नहीं है, लेकिन करीब के बाटला नगर डिस्पेंसरी में इसकी व्यवस्था है।
- डा. बेग ने बताया कि कि वे निजी प्रैक्टिस में इतने समय में दोगुना कमाई कर सकते हैं, लेकिन वे 20 रुपये प्रति मरीज पर भी काम करने को तैयार हैं क्योंकि गरीबों की मदद करने में उन्हें बेहद आंतरिक संतोष मिलता है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर स्थानीय मरीज को सफदरजंग अस्पताल या किसी दूसरे बड़े अस्पताल में जाना हो तो 100 रुपये तो केवल ऑटोरिक्षा का किराया लग जाएगा। इसके अलावा बाजार से दवा खरीदने में

भी खर्च करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ सब कुछ मुफ्त है।

- ▶ यह क्लीनिक किराये की जगह पर चलता है और आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने क्लीनिक के लिए कुछ फर्नीचर दान किये हैं।
- ▶ मैंने वहाँ कुछ मरीजों से भी बात की और वे इस व्यवस्था से काफी संतुष्ट नजर आये।

इसके बाद मैं पैदल ही पहलवान चौक स्थित दूसरे क्लीनिक के लिए निकला। रास्ते में मुझे हाजी मोहम्मद अली मिले। उन्होंने मुझे पहचान लिया। वे भी मेरे साथ हो लिए। उन्होंने मुझे बताया कि स्थानीय विधायक, जो अमानतुल्ला खान नाम का एक नौजवान है, वह इलाके में अच्छा काम कर रहा है।

जब मैं दूसरे क्लीनिक पहुँचा तो वहाँ मुझे एक सिख डॉक्टर, डॉ. ब्रजेंद्र सिंह मिले। बेहद शिष्ट डॉ. सिंह को मैंने बताया कि मैं औचक निरीक्षण के लिए आया हूँ ताकि पता चल सके कि मोहल्ला क्लीनिक में सचमुच कैसा काम हो रहा है।

उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ के जितने बच्चों को उन्होंने देखा है, वे सब विटामिन की कमी के शिकार हैं, जबकि कई महिलाओं में आयरन की कमी है। उन्होंने बताया कि मोहल्ला क्लीनिक में विटामिन की गोलियाँ मुफ्त उपलब्ध हैं।

डॉ. सिंह भी अपने काम, खासकर गरीबों की सेवा करने को लेकर काफी संतुष्ट नजर आये। उन्होंने बताया कि रोजाना करीब 60-80 मरीज क्लीनिक में इलाज के लिए आते हैं। चूँकि क्लीनिक सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलता है और अगर 60 मरीज भी आये तो मतलब यह कि हर मरीज को ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट ही दिया जा सकता है। मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में सबके साथ न्याय कर पाना मुमकिन नहीं होता।

ऐसे में उन्होंने सुझाया कि क्लीनिक शाम को भी चार घंटे के लिए खोला जाए। मैं समझता हूँ कि यह अच्छा सुझाव है और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव को इस संबंध में जरूरी पहल करनी चाहिए।

उन्होंने यह भी बताया कि कुछ ऐसी दवायें हैं जो सरकारी सूची में नहीं हैं और उन्हें बाजार से भी खरीदने की अनुमति नहीं है। मैंने कहा कि ऐसा शायद इसलिए किया गया होगा क्योंकि ऐसी शिकायतें आती हैं कि कुछ डॉक्टर दवा कंपनियों के साथ मिलकर उनकी दवायें ही लिखते हैं। मेरी सलाह है कि डॉक्टरों की सलाह से सरकारी दवा खरीद की सूची को बढ़ाना जाना चाहिए और जो सस्ती हों, उन्हें जोड़ना चाहिए।

एक सज्जन ने मुझे यह भी बताया कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन खुद जाकर अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं और मरीजों से जानकारी लेते हैं कि उनका इलाज और देख-रेख उचित ढंग से हो रही है कि नहीं।

मोहल्ला क्लीनिकों का मुझ पर अच्छा प्रभाव पड़ा। बेशक वे संपूर्ण अस्पताल नहीं हैं, लेकिन मुझे बताया कि करीब 80 फीसदी बीमारियाँ वहाँ ठीक हो सकती हैं और मुफ्त दवा भी दी जा रही है। अभी तक तो भारत में गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवा तो न के बराबर थी, लेकिन मोहल्ला क्लीनिक एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकते हैं।

मेरी राय में यह एक बेहतर प्रयास है और भारत के दूसरे राज्यों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए। वास्तव में, मुझे तो यह भी बताया गया है कि दुनिया में अपनी तरह

की अनोखी योजना है और कई देश इसका अध्ययन करना चाहते हैं। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने भी इसकी सराहना की है।

दोनों डॉक्टरों ने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव काफी ऊर्जावान हैं और मोहल्ला क्लीनिक परियोजना की बेहतर तरीके से निगरानी कर रहे हैं। ■

**नई दिल्ली का मोहल्ला क्लीनिक अमेरिका को भी सेहत सुरक्षा क्षेत्र के मामले में काफी कुछ सिखा सकता है।**

वाशिंगटन पोस्ट

**भारत की यह निशुल्क स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था शहरी अमेरिका के लिए एक मॉडल है।**

शिकागो ट्रिब्यून

**अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लीनिक से अमेरिका को भी सीखना चाहिए।**

एनडीटीवी

**मोहल्ला क्लीनिक संभाव्यताओं का विस्तार है।**

ईपीडब्ल्यू



# असमानता बढ़ती रही तो लोकतंत्र नहीं टिकेगा-पी. साईनाथ

“भारत में असमानता इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। 2015 के आँकड़ों के हिसाब से देश के एक फीसदी उच्च वर्ग का कुल संसाधनों के 53 फीसदी पर कब्जा है जो 2014 में 49 फीसदी था। जबकि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वाँ हो गया है। केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों ने अरबपतियों की तादाद में तो इजाफा किया है, लेकिन किसानों की खुदकुशी बढ़ी है और आम आदमी के लिए जीना मुश्किल होता जा रहा है”—यह आँख खोलने वाला बयान देश के प्रसिद्ध पत्रकार पी. साईनाथ का है जो 27 जून 2016 को दिल्ली विधानसभा द्वारा आयोजित व्याख्यानमाला का उद्घाटन भाषण देने आये थे।

पत्रकारिता में योगदान के लिए मैगसैसे अवार्ड से सम्मानित पी. साईनाथ ने ‘भारत में पानी और कृषि संकट’ विषय पर अपना व्याख्यान देते हुए जो जमीनी तस्वीर पेश की, वह खतरे की घंटी है। उन्होंने बताया कि आधुनिकीकरण

के नाम पर भूजल दोहन इस स्तर पर पहुँच चुका है कि धरती के नीचे हजारों साल पुराने संचित जल को भी खींचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि समस्या सिर्फ बारिश की कमी की नहीं है। लगातार तीन साल तक अच्छा मानसून रहे फिर भी भारत जिस भयानक जल संकट के कगार पर है, उसका खतरा टलेगा नहीं। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार देश की ऐसी नदियाँ सूख रही हैं जो सदानीरा रहती थीं। उन्होंने बताया कि त्रयंबेक्श्वर में गोदावरी और सतारा में कृष्णा नदी के मूल स्रोत कुंडों में पाइप से जलापूर्ति की जाती है।

उन्होंने बताया कि जीवनशैली का फर्क यह है कि देश में उपलब्ध कुल पानी का 53 फीसदी इस्तेमाल सिर्फ मुंबई, पुणे जैसे तीन शहर करते हैं। महानगरों में ऐसी बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं जहां हर मंजिल पर अलग स्वीमिंग पूल की व्यवस्था की जा रही है, जबकि लाखों किसान सिंचाई के पानी के अभाव में खेती छोड़ शहरों को



पलायन करने के लिए मजबूर हैं। विडंबना यह है कि यही किसान शहर पहुँचकर निर्माण मजदूर के रूप में स्वीमिंग पूल वाली इमारतों के लिए पसीना बहाते हैं।

श्री साईनाथ ने कहा कि सवाल प्राथमिकता का है। सरकार की नीतियाँ ऐसी हैं कि पानी धीरे-धीरे संपत्तिशाली वर्ग की जागीर बनता जा रहा है। यह तय करना जरूरी है कि पानी मानवाधिकार है या फिर उपभोग की वस्तु। पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता घटती जा रही है।

पी. साईनाथ ने मौजूदा केंद्र सरकार पर किसानों की परिभाषा बदलने की आरोप लगाया। उनके मुताबिक बटाई पर खेती करने वालों को किसानों की परिभाषा से बाहर करने का मकसद किसानों की खुदकुशी की तादाद में कमी दिखाना है जबकि कृषि संकट गहराता जा रहा है। उन्होंने बताया कि दस साल पहले एक संसदीय समिति ने किसान आयोग को लेकर अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन वह धूल फाँक रही है। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। लागत का 50 फीसदी अतिरिक्त जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का मुद्दा भी ठंडे बस्ते में है। कृषि लोन महंगा है जबकि कार लोन सस्ता। कृषि लोन भी किसानों की पहुँच से बाहर है। नाबार्ड ने 51 फीसदी लोन मुंबई और कुछ बड़े शहरों के लोगों को दिया। सरकार कृषि से जुड़े उद्योग और कारोबारियों को लोन देने को भी कृषि लोन में जोड़ देती है। अंग्रेजों के बनाये काननों के आधार पर किसानों को बेइज्जत करके जेल भेज दिया जाता है जबकि बड़े कर्जदारों का नाम तक छिपाया जाता है।

श्री साईनाथ ने कहा कि किसान परिवार की औसत आय तेजी से घटी है और अब कोई खेती नहीं करना चाहता। मीडिया भी किसानों या ग्रामीण भारत को कवर नहीं करता। हाँलाकि वह गरीब शहरी भारत को भी कवर नहीं



करता। असमानता ऐसे ही बढ़ती रही तो लोकतंत्र का टिक पाना मुश्किल होगा। इन समस्याओं का समाधान भारत के संविधान में है अगर सत्ता में बैठे लोगों की नीयत साफ हो।

इस मौके पर पी. साईनाथ का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे श्री साईनाथ के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। उन्होंने इस सिलसिले में उनकी किताब "एवरीवन लव्स अ गुड ड्राउट" का खासतौर पर उल्लेख किया जिसने ग्रामीण भारत में जारी लूट का बड़ी बेबाकी से पर्दाफाश किया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की प्राथमिकता के केंद्र में सबसे गरीब आदमी है, इसीलिए सरकार शिक्षा पर बजट का 25 फीसदी और स्वास्थ्य पर 18 फीसदी खर्च कर रही है। उन्होंने मोहल्ला क्लीनिक का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे यह एक योजना दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा की तस्वीर बदल रही है। यहाँ दवा से लेकर जाँच तक मुफ्त है और कुल मरीजों के 97 फीसदी तक का इलाज हो जाता है। उन्होंने बताया कि फसल खराब होने पर दिल्ली के किसानों को सरकार ने 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जो देश में सर्वाधिक है।

वहीं उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पी. साईनाथ को अपने समय का एक बड़ा चिंतक बताया जो अपने लेखन से तमाम सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं की चेतना को धार देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने पी. साईनाथ का स्वागत करते हुए कहा कि उनके विचारों से दिल्ली के विधायकों को विषय की बेहतर समझ हासिल हुई है जो इस व्याख्यानमाला का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि इस व्याख्यानमाला के तहत भविष्य में भी तमाम विषय विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा। विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिड़ला ने धन्यावाद ज्ञापन किया। ■

हिंदी अकादमी ने बदला दिल्ली का सांस्कृतिक परिदृश्य

# ‘‘मैंने कमानी सभागार में नाटक देखने के लिए लोगों को गिड़गिड़ाते देखा’’



दिल्ली के कमानी सभागार में 27 जून की शाम, प्रख्यात कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास 'मैला आँचल' का मंचन हुआ। दिल्ली हिंदी अकादमी की इस प्रस्तुति का निर्देशन सुरेंद्र शर्मा ने किया था। मंचन के दौरान अकादमी की पत्रिका इंद्रप्रस्थ भारती के मासिक स्वरूप का लोकार्पण भी हुआ। पहले यह पत्रिका त्रैमासिक थी। हिंदी की यशस्वी कथाकार मैत्रेयी पुष्पा ने जब से उपाध्यक्ष बतौर अकादमी की कमान संभाली है, दिल्ली के सांस्कृतिक परिदृश्य में जैसे नया रंग भर गया है। 'मैला आँचल' देखने पहुँचे 'न्यूज 24' के चर्चित एंकर नवीन कुमार ने दिल्ली में आये इस परिवर्तन को रेखांकित करते हुए एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी, जिसे हम यहाँ साभार प्रकाशित कर रहे हैं—

‘कोई पचास साल की एक महिला कमानी ऑडिटोरियम के मुख्य गेट के भीतर गार्ड से झगड़ा कर रही थी—‘मैं अंदर चली आई, मेरे पति को पार्किंग की जगह खोजने

में देर लग गई उन्हें अंदर आने दीजिए प्लीज’। उनके बुजुर्ग पति गेट के बाहर से हाथ हिलाते हुए कह रहे थे, ‘मैं ही हूँ इनका पति’। गार्ड हाथ जोड़ रहा था, ‘मैंडम आपकी बात ठीक है लेकिन उनके लिए गेट खोला तो डेढ़ सौ लोग चढ़ बैठेंगे।’

27 जून को शाम 7 बजकर 10 मिनट पर दिल्ली के कमानी सभागार का ऐसा ही नजारा था। अंदर हॉल ठसाठस भरा हुआ। बीच की गैलरी के कारपेट तक पर लोग बैठे हुए थे। बाहर लोग मिन्नतें कर रहे थे हमें कोई कुर्सी नहीं चाहिए.. बहुत दूर से किराया भाड़ा खर्च करके आधी छुट्टी लेकर आए हैं बस नाटक देखने दीजिए।

मुझसे देखा नहीं गया तो मैंने अपने बूते में कमानी के प्रबंधकों से कहा कि लोग किसी भी तरह देखने को तैयार हैं तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। उनका जवाब था कि पहले से लोग खड़े हैं, अगर गेट खोल

दिया तो नाटक ही नहीं हो पाएगा, पहले से खड़े लोग हंगामा कर देंगे। मैं निरुत्तर था। नाटक था 'मैला आंचल'। ऐसा भी नहीं था कि अनुराग कश्यप ने निर्देशित किया हो, ऐसा भी नहीं था कि शबाना आजमी अभिनय कर रही हों, ऐसा भी नहीं था किसी रिएलिटी शो का मजा आने वाला हो। मैं



दंग था कि दिल्ली जैसे शहर में रेणु के इतने कद्रदान आए कहां से? यह एक ऐसी चाहना थी जिससे आमिर खान और शाहरुख खान तक को रश्क हो सकता है।

मैत्रेयी पुष्पा के नेतृत्व में दिल्ली हिंदी अकादमी ने जिस तरह से साहित्यिक दायरे में रहते हुए राजनैतिक हस्तक्षेप का सिलसिला शुरू किया है वह दंग करने वाला है। रेणु की कहानियों का नाट्य रूपांतरण करवाना, उनपर एक महीने की वर्कशॉप करवाना, पूरे हफ्ते रोजाना दो नाटकों का मंचन और आखिर में मैला आंचल की भव्य प्रस्तुति। एक ऐसे समय में जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अपने अभिजातपन के खोल से बाहर आने को ही तैयार नहीं है, हिंदी अकादमी का अपने सरकारीपन से बाहर निकलकर मंडी हाउस के चौराहे पर चीख पड़ना चौंकाता है।

एक ऐसे समय में जब साहित्य अकादमी ने अपने सम्मानित लेखकों का पक्ष छोड़कर पूरी वैचारिकी पर ताला जड़ दिया है तो हिंदी अकादमी का जड़ता को तोड़कर साहित्य के मूल सरोकारों को विमर्श में ला देना आश्चर्य पैदा करता है। एक ऐसे समय में जब चेतन भगत और सुरेंद्र मोहन पाठक जैसे लेखक पुस्तक मेलों के टॉम बॉय हो चले हैं, गांधी स्मृति के आहाते में पाश, धूमिल, गोरख या बल्ली सिंह चीमा के आदमकद पोस्टरों पर यूनिवर्सिटी के छात्रों को बात करते देखना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कोई अकादमी अदम



गोंडवी को भी शिद्दत से याद करती है और दिनेश शुक्ल से 'जइसे आवैं गुइयाँ चार' सुनने के लिए मंचीय योगासनों को छिन्न-भिन्न कर डालती है।

खैर, आगे की कथा यह है कि मैं अपने शो 'ये है इंडिया' की वजह से ऑफिस पहुंचने के लिए नाटक के बीच से सात

बजकर दस मिनट पर हॉल से निकला। बाहर गेट बंद और उस तरफ इतने लोग कि जितने आ जाएँ तो कोई भी नाटककार अपने को धन्य समझता है। लेकिन गार्ड किसी भी तरह से बाहर वालों को आने देने को तैयार नहीं थे। मैंने कहा कि मुझे तो बाहर जाना है। गार्ड ने कहा सवाल ही नहीं। आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा गेट एक ही है आपके लिए खुलेगा तो उनके लिए भी खुल ही जाएगा। फिर पूछा तो क्या करूं। उसका जवाब था करना क्या है अंदर जाकर नाटक देखिए।

अंदर जाकर देखा तो सबसे आगे की मेरी वाली कुर्सी पर कोई और बैठा था। मैंने पूरा नाटक सबसे पीछे खड़े-खड़े देखा। जिन लेखकों और नाटककारों को पाठक और दर्शक न मिलने की शिकायत है, उन्हें मेरा जवाब है "इसका मतलब आप मर चुके हैं, अपनी मृत्यु के शोकगीत को साहित्य मत कहिए। आप अपने आपको जिंदा तो कीजिए। मैंने कल कमानी ऑडिटोरियम के गेट पर मैला आंचल देखने के लिए 17 साल के किशोर से 70 साल के बुजुर्ग तक को गिड़गिड़ाते हुए देखा है।" ■

# संक्षेप में...

## 102 नंबर पर मिलेगी एंबुलेंस

दिल्ली वालों को इमरजेंसी में अब एंबुलेंस के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने कैट्स एंबुलेंस के बेड़े में 55 नई एंबुलेंस जोड़ीं जिनका लोकार्पण उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया। श्री सिसोदिया ने बताया कि इस सेवा के सुचारु संचालन के लिए विश्वस्तरीय नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। इसके साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर 102 भी शुरू किया गया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। सेंट्रलाइज्ड एंबुलेंस ट्रॉमा सर्विस (कैट्स) एक सोसाइटी के तौर पर पंजीकृत है। कोई भी व्यक्ति इस सेवा का लाभ ले सकता है।

## अंबेडकर विश्वविद्यालय को मिला नया परिसर

दिल्ली सरकार के वित्त पोषित अंबेडकर विश्वविद्यालय को करमपुरा इलाके में अपना नया परिसर मिल गया है। 28 जुलाई को इस परिसर का उद्घाटन करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हर साल स्कूलों से पढ़ाई पूरी कर निकलने वाले ढाई लाख से अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए कालेज नहीं जा पाते। वे या तो पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं या दिल्ली से बाहर कालेजों में दाखिला लेते हैं। निजी कालेजों में दाखिले के लिए उन्हें भारी रकम फीस के रूप में भरनी पड़ती है। सरकार का सपना है कि दिल्ली में सभी को प्रवेश मिले। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में हुई थी। 2020 तक रोहिणी और धीरपुरारे में भी इस विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन परिसरों का काम पूरा होने की संभावना है।

## पूर्वी दिल्ली में जल्द मिलेगा फ्री इंटरनेट

दिल्ली सरकार ने पूर्वी दिल्ली में 1000 हॉटस्पॉट के जरिये फ्री इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। पूर्वी दिल्ली में फ्री इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए 571 जगहों का चयन किया गया है। इस सुविधा से हर जोन में 120 यूजर एकसाथ लॉगिन कर पाएँगे। पूर्वी दिल्ली देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र होगा, जहाँ पर लोगों को मुफ्त वाई-फाई की सुविधा दी जाएगी। हर घर तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए कॉमन फाइबर नेटवर्क बिछाने के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है ताकि गीगा बाइट स्पीड पर दिल्ली की जनता इंटरनेट का इस्तेमाल कर सके।

## दिल्ली ग्रीष्म उत्सव का आयोजन

दिल्ली पर्यटन विभाग ने इस बार जनकपुरी के दिल्ली हाट में आम-उत्सव को नये रूप में प्रस्तुत किया। इस उत्सव में ग्रीष्म ऋतु में उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं जैसे रंग-बिरंगी छतरियों और मिट्टी के सुसज्जित मटकों की धूम थी। इसके अलावा विभिन्न किस्म के आमों की प्रदर्शनी, आम खाओ प्रतियोगिता, आम और आम से बने उत्पादों की बिक्री, बच्चों के लिए मनोरंजन कोना, आम से बने व्यंजनों को बनाने की विधि और '100 है दाम-कितने भी खाओ

आम' प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस उत्सव में रंगीले पंजाबी बैंड की प्रस्तुति, अभिषेक आचार्य का मैजिक शो, उल्ले खां व सहयोगियों की राजस्थानी प्रस्तुति, विक्रमाजीत और जीवेश के हास्य कार्यक्रम और जोया बैंड की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहे।

## पत्रकारों के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत

दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने पत्रकारों की सुविधाओं के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से पत्रकार, सूचना एवं प्रचार निदेशालय की ओर से दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के लिए कहीं से और कभी भी आवेदन कर सकते हैं। पत्रकारों के लिए ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च करते हुए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे एक अच्छी शुरुआत बताया। दिल्ली प्रेस मान्यता समिति के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध शर्मा ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि यह सुविधा पत्रकारों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। प्रैस कार्ड के नवीनीकरण के लिए इस आनलाईन सेवा का उपयोग कर सकते हैं। फ्री डीटीसी पास, रेलवे रियायती कूपन, पार्किंग लेबल और स्वास्थ्य संबंधित सेवा हेतु हैल्थ कार्ड के फार्म भी इस सेवा में उपलब्ध हैं।

## सभी गेस्ट टीचर्स की दोबारा नियुक्ति का निर्देश जारी

दिल्ली सरकार ने अपने वादे के मुताबिक सभी गेस्ट शिक्षकों की दोबारा नियुक्ति संबंधी निर्देश जारी कर दिया है। शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी स्कूल प्रमुखों को सूचित किया गया है कि वे 1 जुलाई से गेस्ट शिक्षकों की दोबारा नियुक्ति कर सकते हैं। शिक्षा निदेशालय के निर्देश में ये भी कहा गया है कि तबादले और पदोन्नति से स्थायी शिक्षकों के आने से हटाए गए गेस्ट टीचर्स की भी दोबारा नियुक्ति होगी। पिछले दिनों दिल्ली अतिथि शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने गेस्ट टीचर्स को जल्द से जल्द दोबारा नियुक्ति करने का आश्वासन दिया था।

## स्किल डेवलपमेंट के लिए त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स

दिल्ली सरकार के अथक प्रयासों से दिल्ली एजूकेशन हब बन रही है। 'कौन कहता है कि सिर्फ टॉपर्स ही एक्सपर्ट बन सकते हैं' टैगलाइन के साथ दिल्ली सरकार ने विभिन्न तकनीकी विषयों में 3 वर्षीय डिग्री कोर्स की शुरुआत की है। इन्हें एआईसीटीई और यूजीसी की गाइडलांस के अनुसार अकादमिक क्षेत्र और इंडस्ट्री के दिग्गजों ने तैयार किया है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुछ चुनिंदा कालेज इन कोर्सों के माध्यम से स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अहम भूमिका अदा करेंगे। उच्चतर शिक्षा निदेशालय द्वारा साफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल कम्प्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल, प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में शुरू हुए तीन वर्षीय डिग्री कोर्स के लिए कोई काट ऑफ और आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

‘ਟਾਕ ਟੂ ਏ.ਕੇ.’ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ

TALK TO AK

## ਕੇਂਦਰ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੰਦਨ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ - ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੱਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। “ਟਾਕ ਟੂ ਏ.ਕੇ.” (ਗਲ ਕਰੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਡਲਾਨੀ ਨੇ ਚੁਕਿਆ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਪਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੌਦਿਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਵਾਲ ਟਵੀਟਰ, ਐਸਐਮਐਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਅੰਸ਼-

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੈਂ ਗੋਵਾ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਥੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਗਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿਹੋ-ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰੀਏ। ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਗਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨੀਅਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਜੋ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਰੁਪੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 60-70 ਰੁਪੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿਚ ਰੇਲ ਰੋਡ ਪੁਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਜਦ 2009 ਵਿਚ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਸੀ 600 ਕਰੋੜ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੈ। 2008 ਵਿਚ 70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਮਸੀਡੀ (ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ) ਨੇ ਬਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਾਗਤ 200 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਗੋਵਾ ਵਿਚ ਮਾਂਡੋਵੀ ਬ੍ਰਿਜ 2014 ਤੋਂ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਸੀ 470 ਕਰੋੜ। ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 886 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ।

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋ-ਚਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਸੀ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਐਸਾ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ।

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਵਿਚ ਬਚਾਏ ਕੁਲ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ। ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਵਿਚ ਆਈਟੀਆਈ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਲਾਂ ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 4-5 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀਹ ਲੱਖ ਵਿਚ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੱਚਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਘਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ ਘਟੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਲਟੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ- ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ।

**ਸਿਖਿਆ**-ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਯਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਸ਼ੋਚਾਲਯ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਟਾਪ ਕਰਨ ਵਿਚ ਘੋਟਾਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਕਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੱਚਣ ਦੀ ਗਲ ਹੈ।



ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਸਥ ਵਿਚ ਖਰਚ, ਦਰਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਦੋਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ। ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼ੋਚਾਲਯਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲੇ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹਦ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਥੇ ਸ਼ੋਚਾਲਯ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਥੇ ਨਵੇਂ ਬਣਵਾਏ। ਲਗਭਗ 1100 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੋਚਾਲਯ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਫਿਰ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਇਕ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਡੇਢ ਸੌ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 8000 ਨਵੇਂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਚਾਲੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 200 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 45 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। 100 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਲੱਭੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ

## ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਚਾਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਰੁਕੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਮੈਂ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਿਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:-

- ਸਾਰਾ ਲੋਨ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਉ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣਗੇ।
- ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰੀਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਉ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਜੋੜ ਕੇ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 1950 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ 1450 ਰੁਪੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ।
- ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ।
- ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ।

ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਈ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਨਾਪ-ਸ਼ਨਾਪ ਫੀਸ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੁੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕਸ ਸਕਿਆ। ਐਸੇ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਉਥੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਨੌਇਡਾ ਵਿਚ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਦ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਵਾ, ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛਤੀਸਗੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਬੇਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਕਲ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ। ਅੱਠਵੀਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਨੌਵੀਂ ਵਿਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨੌਵੀਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਨਾ-ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨੇ ਡਿਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਮਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਵੇ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸੋ ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰਕੇ ਸੋ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ।

ਸੜਕਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰ, ਨਾਲੀ, ਸਭ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਸਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ 'ਤੇ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਸਕਣ।

**ਸਵਾਸਥ-ਸਾਡੀ ਦੂਜੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਸਵਾਸਥ।** ਅਸੀਂ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਸਥ ਵਿਚ ਖਰਚ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਥੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਫੜ ਕੇ ਇਕ ਲੋਕਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ। ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਸੀ। ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਉਥੇ ਤਾਲਾ ਲਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਮਰੀਜ਼, ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਨਰਸ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ।



ਜਦ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਵਾਸਥ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਵਧਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਲ ਬਜਟ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਿਖਿਆ 'ਤੇ ਅਤੇ 18-19 ਫੀਸਦੀ ਸਵਾਸਥ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਂਸੀ-ਜੁਕਾਮ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਏਮਸ ਭਜਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬਣਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏ।

ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂਗੜੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਤੁੱਠੀ ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਡ। ਇਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 212 ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੋ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਤਕ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਤਕ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਸੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵੀਹ ਲਖ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੇ ਵਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਆਇਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ

ਚੰਗਾ ਲਗਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਖਬਰ ਛਾਪੀ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਸਿਖ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਹੁਣ ਤਕ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ 100 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬਣ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਐਸੀਆਂ 1000 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਵਾਸਥ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ ਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਰੇ ਤਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਸਤ ਅਠ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਬੀਮਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਕ 22 ਪਾਲੀਕਲੀਨਿਕ ਬਣ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪੱਛਮ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪਾਲੀਕਲੀਨਿਕ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਮਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਟਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਐਸੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਸਥ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਰਾਂਤੀ ਹੀ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਮਲਟੀਸਪੈਸ਼ਿਲਟੀ ਹਸਪਤਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਸਥ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਖਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿਲਤ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੂਬ ਪੈਸਾ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਵਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਤਮਹਤਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਿਲ ਚੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੁਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮੁਦਾ ਚੁਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਘਟ ਹੋਵੇਗੀ।

## ਜ਼ਮਾਖੋਰੀ ਨਾ ਰੁਕੀ ਤਾਂ 400 ਰੁਪੈ ਕਿਲੋ ਵਿਕੇਰੀ ਦਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦਾਲ 17-18 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ। ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮਿਲੀਅਨ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੀਬ 22-23 ਮਿਲੀਅਨ ਖਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਾਲ ਵਿਚ? ਕਣਕ ਦਾ ਘਟੇ ਘਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ 1450-1500 ਰੁਪੈ ਹੈ, ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 17-18 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਹਰ-ਮੂੰਗ ਦਾ ਹੈ 50 ਰੁਪੈ, ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ 200 ਰੁਪੈ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਕਿਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 150 ਰੁਪੈ। ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਜ਼ਮਾਖੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ 8-10 ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮਾਖੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਦਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਖੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ 400 ਰੁਪੈ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦਾਲ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ।

**ਬਿਜਲੀ**-ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰੇਟ ਅੱਧੇ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 550 ਰੁਪੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 1170 ਰੁਪੈ, ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ 1950 ਰੁਪੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1229 ਰੁਪੈ ਦਾ ਬਿਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

Billing Cycle	Billing Period	Billing Amount
13-06-2017	01-06-2017	1370
13-06-2017	01-06-2017	2615
13-06-2017	01-06-2017	4300
13-06-2017	01-06-2017	2927
13-06-2017	01-06-2017	2690

ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 1370 ਰੁਪੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 2615, ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ 4300, ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚ 2927 ਰੁਪੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2690 ਰੁਪੈ।

ਇਕ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬੇਹਦ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਯੁਧ-ਪੱਧਰ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਲੋਕਲ ਫਾਲਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ।

**ਪਾਣੀ**-ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪੀਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਚੋਰੀ

ਕਰਕੇ ਪੀਏਗਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਾਇਕ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 20,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਜਲ ਬੋਰਡ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਲ ਭਰ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 173 ਕਰੋੜ ਰਾਜਸਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫਿਜ਼ੂਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਲਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਲਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਦੇ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਦੇਣ ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ।

ਇਕ ਸਮਸਿਆ ਬਿਲ ਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਸਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਲੱਖ ਤਕ ਦਾ ਬਿਲ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਖੁਦ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋਈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਅਜੇ ਤਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ 263 ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤਕ ਹਰ ਘਰ ਤਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿ ਟੋਟੀ ਖੋਹਲੋ ਅਤੇ ਪੀ ਲਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਆਰ.ਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ। ਟੋਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਰਖਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ। 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 54 ਲਖ ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੇਟ ਕਰ ਦਿਤਾ।



ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਕਮਾਈ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੌ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 80 ਕਮਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਨ-ਦਸ-ਪੰਦਰਾਂ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੋਗੁਣੀ-ਤੀਗੁਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੀਹ ਰੁਪੈ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ 200 ਰੁਪੈ ਵਿਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਦੁੱਖੀ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।

**ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਡਲਾਨੀ-ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁਲਕਿਤ ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ..?**

**ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ**-ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਗਿਣਾਏ ਹਨ ਉਹ ਹੋਏ ਹਨ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਆਓ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲ। ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੋ-ਗੁਣਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੇ 14 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਟੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਨਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ

ਆਦਿ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ, ਨੌ ਡਿਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 14 ਬਿਲ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁਛੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਲਬਾਤ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੁਛਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਫਸਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਅਣਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਖੜ੍ਹਾ, ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਕਤਰ ਤੇ 39 ਪੋਸਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੁਕ ਕੇ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।

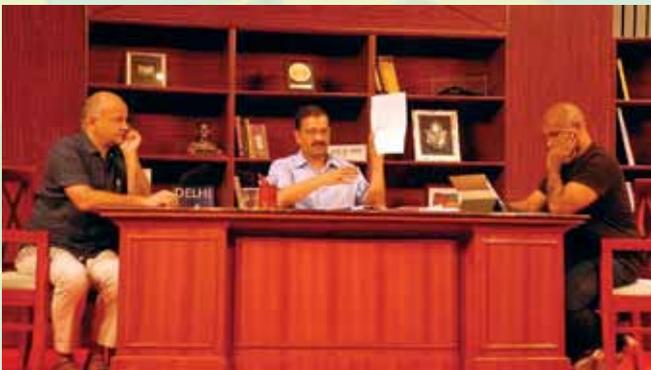
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਸੀਬੀ (ਐਂਟਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਸੀ ਤਾਂ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਕ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਭੇਜ ਕੇ ਏਸੀਬੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 32 ਕੇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਏਸੀਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇ, 150 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰੋਕ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਅਕਸ਼ੈ ਪਾਤਰ' ਯੋਜਨਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਕਾਨ ਵਾਲੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਸੋਈ। ਅਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ, ਛਤੀਸਗੜ, ਕਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਵਿਚ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਮਾਂਕਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਉਹ ਐਨਜੀਓ ਹਨ, ਟੈਂਡਰ ਵਿਚ ਆਵੇਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਉਲਟਾ ਡੋਨੇ ਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਚਲਾਈ, ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਲਜੀ ਸਾਹਬ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਮਨੀਸ਼ ਨੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ, 45 ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 15 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਲ ਚਲਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਕ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਦਸੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਦਸ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕਵਾਯਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਉ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਹੁਤ ਬਜਟ ਹੈ। ਬਸ ਰੋਜ-ਰੋਜ ਦੀ ਖਿਚ-ਖਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੰਦਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। 'ਸਕਿਲ ਇੰਡੀਆ' ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ।

**ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਡਲਾਨੀ-ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 526 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ?**

**ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ**-ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 526 ਕਰੋੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਦ ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਿਰਫ 75 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਅਫਵਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਘਪਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੇਂਟ੍ਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ 75 ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।



ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਦੇ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਥੇ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਈਵੈਂਟ ਇਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਲਈ 27 ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਆਯੋਜਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਓ ਈਵੈਂਟ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਓ, ਬਿਜਨੈਸ ਕਰੋ।

**ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਡਲਾਨੀ-ਪੁਛੁਚੇਰੀ ਤੋਂ ਸੁਧਾਕਰ ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 21 ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ। ਬਗੈਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।**

**ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ**-ਦਰਅਸਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਊਂਡ ਲਗਾ ਕੇ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਨਾ ਗੱਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਗਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਨੌਕਰ। ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੀਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਕਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਓ, ਘਰ ਬੈਠਾਓ। ਯਾਨੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਚਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ, ਗੱਡੀ, ਬੰਗਲਾ ਸਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੋਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਕਤ ਹੈ।

**ਰੰਜੀਤ ਮਾਥੁਰ (ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ) ਨਮਸਕਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੰਜੀਤ ਮਾਥੁਰ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 16 ਵਿਚ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਗਲੀ ਖੁਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।**

**ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ**—ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨਗੇ।

**ਨੇਪਾਲਦਾਸ (ਚੇਨਈ)—ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ, ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ?**

**ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ**—ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੇਂਸ ਰਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦਾ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਤਕ ਧਾਰਨਾ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰਪਟ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਈਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ 200 ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਠਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ ਹਨ, ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਭ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਖੁਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਉ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਥੋਂ ਕਮਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਚਲ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ 400 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾ ਪੁਛੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਚਾਰ ਕਰੋੜ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਾਂਗੇ।

**ਪ੍ਰਦੀਪ (ਹੈਦਰਾਬਾਦ)—ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੁਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਲਿਡ ਵੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।**

**ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ**—ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਖਮਤਰੀ ਅਰਬਨ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਮਾ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੇਗੀ। ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਸਫਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਲ-ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਗੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।

**ਸੰਜੀਵ (ਕੇਰਲ)—ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਲਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਹਿਤ?**

**ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ**—ਚੰਗਾ ਆਇਡੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲੀਸ ਜਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਹਿਣ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।

**ਰਵੀ (ਗੋਵਾ)—ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਵਿਕਟਿਮ-ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ?**

**ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ**—ਮੈਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 14 ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਿਮ

ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

**ਪੂਜਾ ਸੋਬਤੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਨਮਸਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਕੀ ਵੈਸੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਾਓਗੇ?**

**ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ**—ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਂਗੇ।

**ਇੰਦੂ ਭਾਸਕਰ (ਦਿੱਲੀ)—ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਡ-ਈਵਨ ਕੀ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ?**

**ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ**—ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਪ-ਬੇਸਡ ਬਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਐਲਜੀ ਸਾਹਬ ਦੇ ਇਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ।

**ਰਤਨ ਸਿੰਘ (ਦਿੱਲੀ) ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਤਰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਗਰਾਊਂਡ ਚੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ?**

**ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ**—ਇਹ ਕਮਾਂਡੋ ਸੁਰੇਂਦਰ ਹੈ। 26/11 ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੋ 200 ਕਮਾਂਡੋ ਮੁੰਬਈ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਬ ਫਟਿਆ ਤਾਂ ਸੁਨਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਦਿਨ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਕ ਅਫਸਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸ-ਸੀ/ਐਸ-ਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪਤਾ ਚਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਕਢ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਮੀਡਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਤ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਅਤੇ ਭੱਜੇ ਤਾਂ ਕਾਇਰ। ਅਸੀਂ ਕਾਇਰ ਨਹੀਂ ਬਨਾਂਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸੀਐਮ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕਤਰ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ

ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਨ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਈਆਈਟੀ ਖਡਗਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਪਤਕਰਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਐਫੀਸੀਐਟ ਅਫਸਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਰਾਜੇਂਦਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੰਗ ਦਿਉ, ਦੋਗੁਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 2006, 2010 ਵਿਚ ਘੋਟਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ 49 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਚੈਲੇਂਜ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਫੜ ਕੇ ਲਟਕਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ।

**ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਡਲਾਨੀ-ਟਵੀਟਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਸਰ, ਵਾਈਫਾਈ ਕਿਥੇ ਹੈ.. ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?**

**ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ**—ਵਾਈ-ਫਾਈ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੌਟ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟੀਕਲ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਘਰ ਤਕ ਇਹ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੇ ਬਲ ਟੀਵੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਗਣਗੇ। ਤਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਟ ਸਪਾਟ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

**ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਡਲਾਨੀ-ਟਵੀਟਰ ਤੇ ਅਮਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ?**

**ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ**—ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਡੀਡੀਏ ਜਮੀਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਾਪਸ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਖ ਲਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਮੀਨ ਡੀਡੀਏ ਖੁਦ ਰਖੇਗਾ। ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

**ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਡਲਾਨੀ-ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਦਤਾ ਰੋਹਿਣੀ ਸੇਕਟਰ 6 ਤੋਂ ਪੁਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਇਡੀਆ ਹੈ?**

**ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਯਾ**-ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਟ੍ਰੈਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 77 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਬੱਡੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਖੇਡ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਖੇਡਣ ਤੇ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ-ਮਨੀਸ਼ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਫਿਜਿਕਸ ਪੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਐਸਸੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਫੁਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੀਏ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿਚ। ਨਾਲ ਹੀ 'ਮਿਸ਼ਨ 100' ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਪੀਣ, ਰਹਿਣ ਟ੍ਰੈਵਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁਕੇਗੀ।

**ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਡਲਾਨੀ-ਟਵੀਟਰ ਤੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਹਨ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਦੇ ਹਨ। ਕਨਾਡਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ?**

**ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ**-ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸੈਲ ਬਣਾਏ ਗੀ।

**ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਡਲਾਨੀ-ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?**

**ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ**-ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ,

ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਿਟ ਭੇਜਿਆ, ਆਈਆਈਐਮ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਲਗਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੋਵਾ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ।

**ਅਭਿਸ਼ੇਕ (ਦਿੱਲੀ)-ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਲੈਣ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?**

**ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਯਾ**-ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 28 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਟਾਫ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇ। ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਆਊਟ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

**ਅਮਨ ਝਾ (ਦਿੱਲੀ)-ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ?**

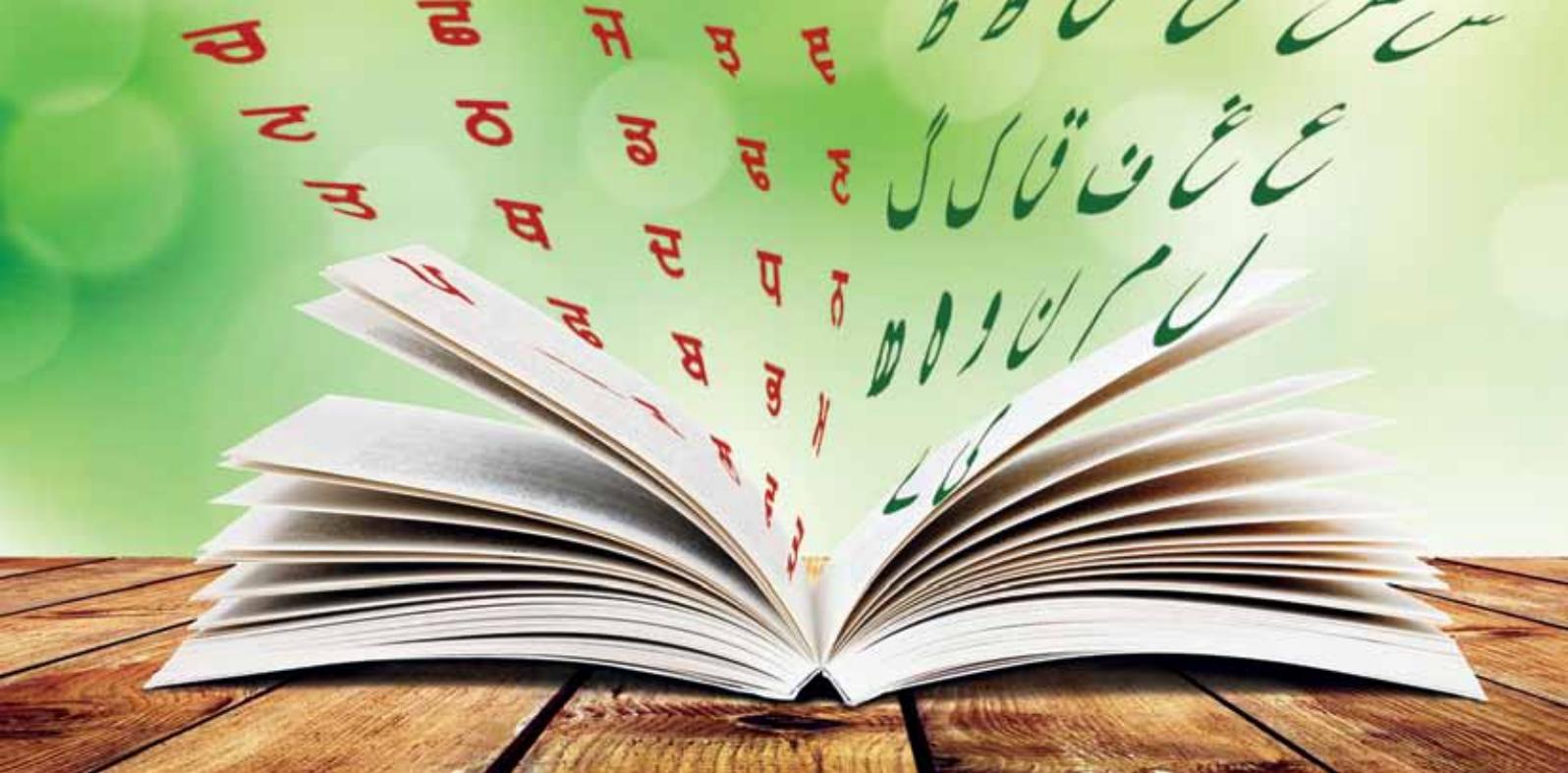
**ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ**-60 ਫੁਟ ਤੋਂ ਚੌੜੀ ਰੋਡ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਘਟ ਚੌੜੀ ਐਮਸੀਡੀ ਦੀ ਹੈ। ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਤਾਂ। 60 ਫੁਟ ਤੋਂ ਘਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਾਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਦ ਐਮਸੀਡੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

**ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਡਲਾਨੀ-ਇਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੈ.. ਹੁਣ ਅਗਲਾ 'ਟਾਕ ਟੂ ਏ.ਕੇ.' ਕਦ ਹੋਵੇਗਾ ?**

**ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ**-ਮਹੀਨੇ ਡੇਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪੁਛੋ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਵੋ।

**ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਡਲਾਨੀ-ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ ਟਵੀਟਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ।**

ਧੰਨਵਾਦ ■



# ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਛੁਟੇਰੀ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ

**ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕ  
ਉਰਦੂ ਦੇ 601 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 769 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਮੁਹਰ**

**ਉ**ਰਦੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਹਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 601 ਉਰਦੂ ਅਤੇ 769 ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ।

ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੌਦਿਯਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇਸ ਨਾਮ ਤੇ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਦਾ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 24 ਮਈ 2006 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ

ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਾਧਿਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 1042 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ 2015-16 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 28,612 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ 82,341 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਆਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਪਰਿਚਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦਵਾਰ ਖੁਲਣਗੇ। ■

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਡਾ. ਕਲਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ

# ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਆਏ ਕਲਾਮ ਸਰ



ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਲਾਮ ਸਰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਆਏ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 11ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਕਲਾਮ ਸਮਾਰਕ' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

ਕਲਾਮ ਸਮਾਰਕ ਵਿਚ ਡਾ. ਕਲਾਮ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਾਈਲ ਮੈਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤਕ ਦੇ ਸਫਰ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਵਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ, ਵਾਲ

ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਘੀ, ਟੀਸ਼ਰਟ, ਚਸ਼ਮੇ ਸਮੇਤ ਨਿਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਡਾ. ਕਲਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਉਕੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਡਾ. ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ। ਇਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ।

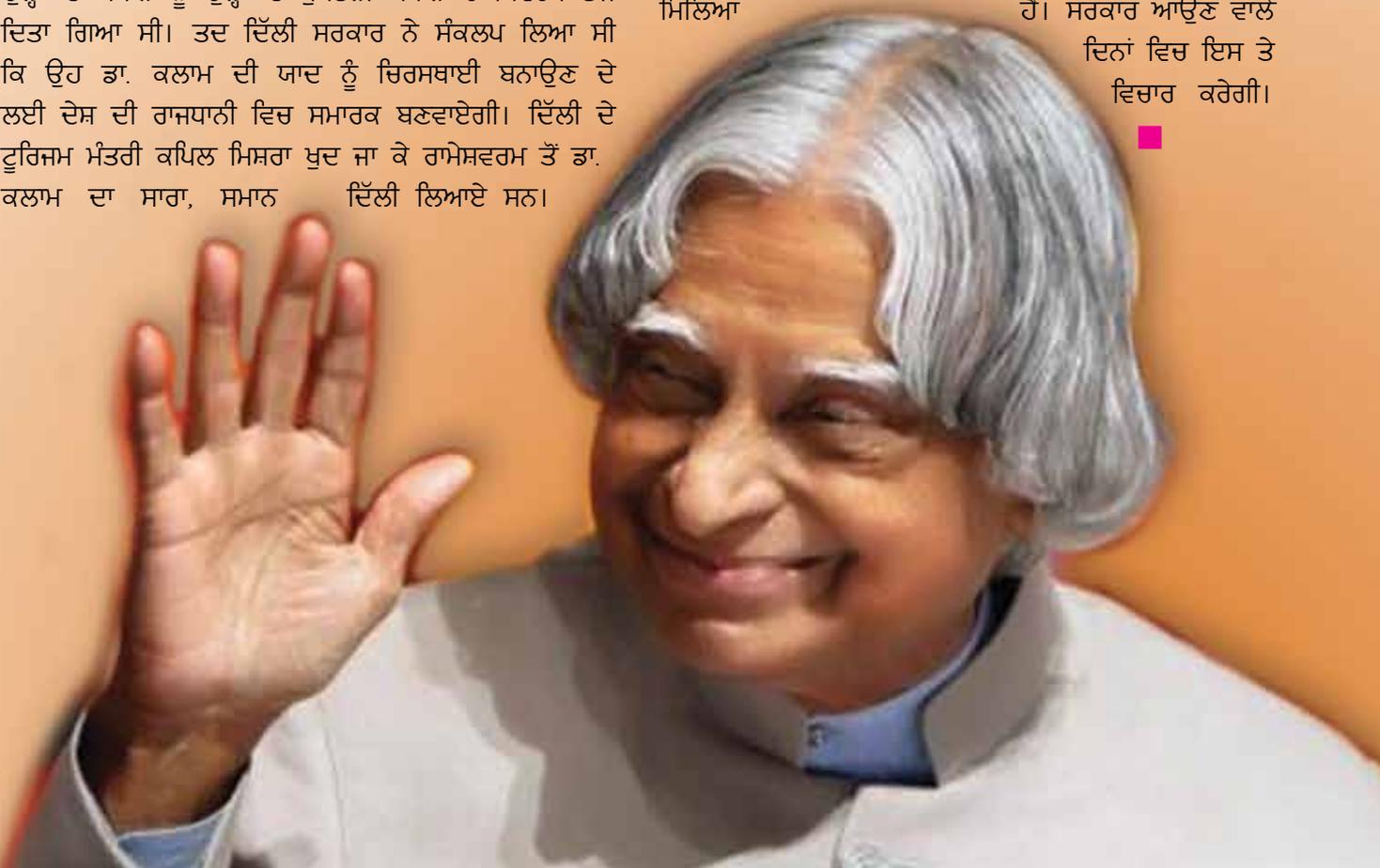


ਇਥੇ ਉਪਖੰਡਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾ. ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਕਲਾਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿਚ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਵਕਤ ਡਾ. ਕਲਾਮ ਦਾ ਦੋ ਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਸਥਾਨ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਾ. ਕਲਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਚਿਰਸਥਾਈ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸਮਾਰਕ ਬਣਵਾਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਤੋਂ ਡਾ. ਕਲਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਸਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਏ ਸਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਮ ਸਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਵਾ ਦਿਤਾ। ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 3ਣ ਹੌਲੇਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਲਾਮ ਸਾਹਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਸਕਣ। 'ਕਲਾਮ ਸਮਾਰਕ' ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤਕ ਖੁਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਥੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਕਲਾਮ ਸਮਾਰਕ' ਨੂੰ ਰੀਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ

ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।



# ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ...

## 102 ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ

ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਟਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿਚ 55 ਨਵੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜੋੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਅਰਪਨ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਆਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 102 ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੋਂਦਰ ਜੈਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੇ ਟ੍ਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਟ੍ਰਾਂਸ ਸਰਵਿਸ (ਕੈਟਸ) ਇਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

## ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਪਰਿਸਰ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੱਖਿਤ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਮਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਪਰਿਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ-ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਢਾਈ ਲਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2008 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ। 2020 ਤਕ ਰੋਹਿਣੀ ਅਤੇ ਧੀਰਪੁਰਾਰੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਰਿਸਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

## ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗਾ ਫ੍ਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 1000 ਹਾਟਸਪਾਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਫ੍ਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫ੍ਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 571 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਹਰ ਜੋਨ ਵਿਚ 120 ਯੂਜ਼ਰ ਇਕੱਠੇ ਲਾਗਿਨ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰ ਘਰ ਤਕ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਨ ਫਾਈਬਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੀਗਾ ਬਾਈਟ ਸਪੀਡ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ।

## ਦਿੱਲੀ ਗਰਮੀ ਉਤਸਵ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਦਿੱਲੀ ਸੈਰਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਕਪੁਰੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਟ ਵਿਚ ਆਮ-ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਤਸਵ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਰੁਤ ਵਿਚ ਉਪਯੋਗ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਛਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੁਸੱਜਿਤ ਮਟਕਿਆਂ ਦੀ ਧੂਮ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਅੰਬ ਖਾਓ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅੰਬ ਅਤੇ ਅੰਬ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੋਨਾ, ਅੰਬ ਨਾਲ ਬਣੇ ਵਿਅੰਜਣਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ '100 ਹਨ ਦਾਮ-ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਖਾਓ ਆਮ' ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ

ਗਿਆ। ਇਸ ਉਤਸਵ ਵਿਚ ਰੰਗੀਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਚਾਰੀਆ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ੋਅ, ਉਲੇ ਖਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਿਸਥਾਨੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਅਤੇ ਜੀਵੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਜੋਯਾ ਬੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਆਕਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ।

## ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਯ ਨੇ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਤਰਕਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਯ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਖ-ਵਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਸਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮਾਨਤਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪਤਰਕਾਰ ਅਨਿਰੁਧ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫ੍ਰੀ ਡੀਟੀਸੀ ਪਾਸ, ਰੇਲਵੇ ਰਿਆਇਤੀ ਕੂਪਨ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਸਵਾਸਥ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

## ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਯ ਦੇ ਵਲੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਯ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਗਏ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਮੰਡਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖਮੰਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦਿਆ ਨੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।

## ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਥਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਐਂਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟਾਪਰਸ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਟੈਗਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਖ-ਵਖ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈਸੀਟੀਈ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਦਿਗਜਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਕਾਲਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਇਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਦੇਸ਼ਾਲਯ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਮੋਬਾਈਲ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਪਬਲਿਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਟ ਆਫ ਅਤੇ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ■

پنجابی بینڈ کی پیش کش، ابھیٹیک آچار یہ کا جادوئی پروگرام، اُتے خان اور ساتھیوں کی راجستھانی پیش کش، وکرماجیت اور جیولیش کے ظرافت پروگرام اور زویا بینڈ کی پیش کش کش کامرکز رہے۔

## صحافیوں کیلئے آن لائن پورٹل کی شروعات

دہلی سرکار کے ڈائریکٹوریٹ اطلاعات و تشہیر نے صحافیوں کی سہولتوں کیلئے آن لائن پورٹل کی شروعات کی ہے۔ اس پورٹل کے ذریعے صحافی، ڈائریکٹوریٹ اطلاعات و تشہیر کی طرف سے دی جانے والی الگ الگ سہولتوں کیلئے کہیں سے اور کبھی بھی درخواست کر سکتے ہیں۔ صحافیوں کیلئے آن لائن پورٹل لانچ کرتے ہوئے دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیانے اسے ایک اچھی شروعات بتایا ہے۔ دہلی پریس منظوم شدہ کمیٹی کے صدر اور سینئر صحافی انیرودھ شرمانے اس سہولت کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ یہ سہولت صحافیوں کیلئے میل کا پتھر ثابت ہوگی۔ پریس کارڈ کی تجدید کاری کیلئے اس آن لائن خدمات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ فری ڈی ٹی سی بس باس، ریلوے رعایتی کوپن، پارکنگ لیبل اور صحت سے متعلق خدمات کیلئے ہیلتھ کارڈ کے فارم بھی اس خدمات میں موجود ہیں۔

## سبھی گیسٹ ٹیچرس کی دوبارہ تقرری کی ہدایت جاری

دہلی سرکار نے اپنے وعدے مطابق سبھی گیسٹ ٹیچرس کی دوبارہ تقرری سے متعلق ہدایت نامہ جاری کر دیئے ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ برائے ایجوکیشن کی جانب سے سبھی اسکول پرنسپلوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ یکم جولائی سے گیسٹ ٹیچرس کو دوبارہ بحال کر سکتے ہیں۔ ڈائریکٹوریٹ برائے ایجوکیشن کی ہدایت نامہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تبادلے اور پرموشن سے مستقل ٹیچرس کے آنے سے ہٹائے گئے گیسٹ ٹیچرس کی بھی دوبارہ تقرری ہوگی۔ پچھلے دنوں دہلی گیسٹ ٹیچرس جماعت کے ایک نمائندہ وفد سے ملاقات کے دوران دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر تعلیم منیش سسودیانے گیسٹ ٹیچرس کو جلد سے جلد دوبارہ بحال کرنے کا دلاسا دیا تھا۔

## اسکل ڈیولپمنٹ کیلئے تین سالہ ڈگری کورس

دہلی سرکار کے بے انتہا کوششوں سے دہلی ایجوکیشن ہب بن رہی ہے۔ کون کہتا ہے کہ صرف ٹاپرس ہی ایکسپرٹ بن سکتے ہیں۔ ٹیگلائن کیساتھ دہلی سرکار نے الگ الگ تکنیکی مسئلوں میں 3 سالہ ڈگری کورس کی شروعات کی ہے۔ انہیں اے آئی سی ٹی ای اور یوجی سی کی گائڈ لائنس کے مطابق اکادمی حلقہ اور انڈسٹری کے دگجوں نے تیار کیا ہے۔ گروگو بند سنگھ اندر پرستھ یونیورسٹی کے تحت کچھ چندہ کالج ان کورسوں کے ذریعہ سے اسکل ڈیولپمنٹ کے میدان میں اہم رول ادا کریں گے۔ ڈائریکٹوریٹ برائے اعلیٰ ایجوکیشن کے ذریعے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، موبائل کمیونیکیشن، آٹو موبائل، پرنٹنگ اور پبلیشنگ، پاور ڈسٹریبیوشن منیجمنٹ اور کنسٹرکشن ٹکنالوجی میں شروع ہوئے تین سالہ ڈگری کورس کیلئے کٹ آف اور عمر کی حد طے نہیں کی گئی ہے۔

## 102 نمبر پر ملے گی ایبوی لینس

دہلی والوں کو ایمرجنسی میں اب ایبوی لینس کیلئے پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ دہلی سرکار نے کیٹس ایبوی لینس کے بیڑے میں 55 نئی ایبوی لینس شامل کی جس کا رپن کاٹ کر افتتاح نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیانے کیا۔ جناب سسودیانے بتایا کہ اس خدمات کے بہتر طریقے سے انجام دینے کیلئے عالمی درجے کا کنٹرول روم بھی بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک ہیملپ لائن نمبر 102 بھی شروع کیا گیا ہے۔ اس موقع پر وزیر صحت ستید رجین بھی موجود تھے۔ سینٹرلائزڈ ایبوی لینس ٹراما سروس (کیٹس) ایک سوسائٹی کے طور پر رجسٹرڈ ہے۔ کوئی بھی شخص اس خدمت کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

## امبیڈ کر یونیورسٹی کو ملا نیا پریسر

دہلی سرکار کے خرچے پر چلنے والی امبیڈ کر یونیورسٹی کو کرپورہ علاقے میں اپنا نیا پریسر مل گیا ہے۔ 28 جولائی کو اس پریسر کا افتتاح کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیانے کہا کہ ہر سال اسکولوں سے پڑھائی پوری کر نکلنے والے ڈھائی لاکھ سے زیادہ طالب علم اعلیٰ تعلیم کیلئے کالج نہیں جاپاتے۔ وہ ہا تو پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں یا دہلی سے باہر کالجوں میں داخلہ لیتے ہیں۔ نئی کالجوں میں داخلے کیلئے انہیں ساری رقم فیس کے طور پر بھرنی پڑتی ہے۔ سرکار کا سہنا ہے کہ دہلی میں سبھی کو داخلہ ملے۔ اس یونیورسٹی کا قیام 2008 میں ہوا تھا۔ 2020 تک روٹی اور دھیر پور میں بھی اس یونیورسٹی کے زیر تعمیر پریسروں کا کام پورا ہونے کا امکان ہے۔

## مشرقی دہلی میں جلد ملے گا فری انٹرنیٹ

دہلی سرکار نے مشرقی دہلی میں 1000 ہاٹ اسپاٹ کے ذریعے فری انٹرنیٹ خدمات حاصل کرانے کیلئے 571 جگہوں کا انتخاب کیا ہے۔ اس سہولت سے ہر زون میں 120 یوزر ایک ساتھ لاگ ان کر پائیں گے۔ مشرقی دہلی ملک کا ہی نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا علاقہ ہوگا، جہاں پر لوگوں کو فری وائی فائی کی سہولت دی جائے گی۔ ہر گھر تک تیز رفتار انٹرنیٹ پہنچانے کیلئے کامن فابریٹ ورک بچھانے کیلئے پروجیکٹ بنایا ہے تاکہ تیز اسپڈ سے دہلی کی عوام انٹرنیٹ کا استعمال کر سکے۔

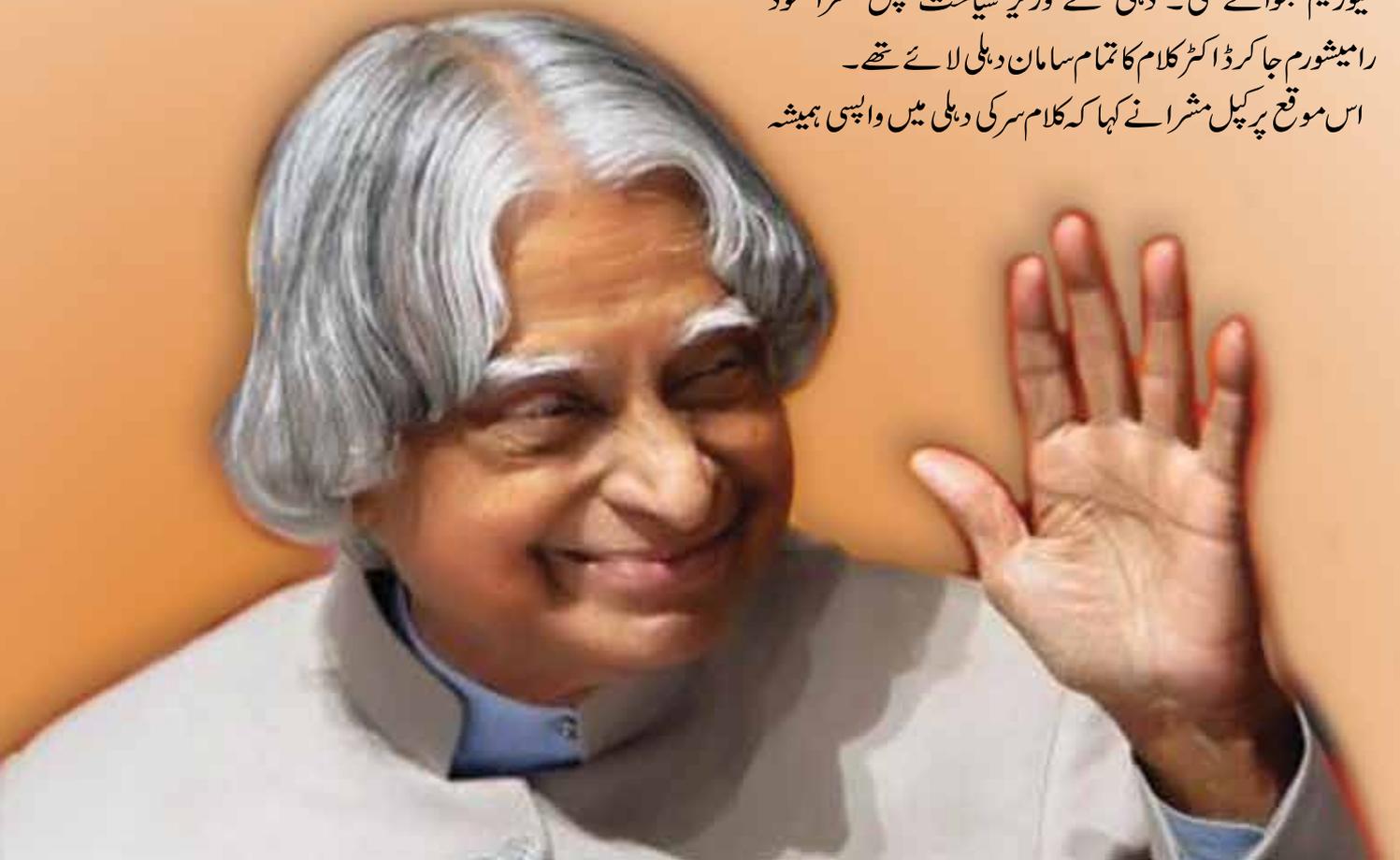
## دہلی موسم گرما اتسو کا انعقاد

دہلی کے محکمہ سیاحت نے اس بار جنکپوری کے دہلی ہاٹ میں موسم گرما اتسو کو نئے انداز میں پیش کیا۔ اس اتسو میں گرمی کے موسم میں استعمال میں لائی جانے والی چیزوں جیسے رنگ برنگی چھتریوں اور مٹی کے جاذب نظر منگلوں کی دھوم تھی۔ اس کے علاوہ الگ الگ قسم کے آموں کی پردرشنی، آم کھاؤ کیپٹیشن، آم اور آم سے بنی چیزوں کی فروختگی، بچوں کیلئے تفریح گاہ، آم سے بنے علامتوں کو بنانے کا طریقہ اور 100 ہے دام۔ کتنے بھی کھاؤ۔ آم کیپٹیشن کا انعقاد کیا گیا۔ اس اتسو میں رنگیلے



کیلئے ہوگئی ہے۔ تین مہینے کے چھوٹے سے وقفہ میں دہلی سرکار نے یہ میوزیم بنوادیا۔ مستقبل میں ان سے جڑی جو بھی چیز ملے گی اسے میوزیم میں لایا جائیگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آنے والے دنوں میں 3D ہولوگرام کی تکنیک لانے کا منصوبہ ہے تاکہ لوگ کلام صاحب کے خیالوں کو لائیوسن سکے۔ 'کلام اسمارک' صبح 11 بجے سے شام 7 بجے تک کھلے گا اور یہاں داخلہ مفت ہے۔ سرکار کا کہنا ہے کہ 'کلام اسمارک' کوریسٹریج سینٹر بنانے کیلئے سجھاؤ ملا ہے۔ سرکار آئیوا لے دنوں میں اس پر غور کرے گی۔ ■

تعلیم کولیکر ڈاکٹر کلام کے خیالوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرے گی۔ پروگرام کے دوران ڈاکٹر کلام کے خاندان کے لوگ بھی موجود تھے۔ غور طلب ہے کہ 27 جولائی 2015 کو شیلانگ میں ایک سمینار میں لیکچر دیتے وقت ڈاکٹر کلام کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اہل خانہ نے دہلی میں ان کا میوزیم بنانے کی مانگ کی تھی لیکن ان کے سامان کو ان کی آبائی گاؤں رامیشورم بھیج دیا گیا تھا۔ تب دہلی سرکار نے ارادہ کیا تھا کہ وہ ڈاکٹر کلام کی یاد کو یادگار بنانے کیلئے ملک کی دارالحکومت میں میوزیم بنوائے گی۔ دہلی کے وزیر سیاحت کپیل مشرا خود رامیشورم جا کر ڈاکٹر کلام کا تمام سامان دہلی لائے تھے۔ اس موقع پر کپیل مشرا نے کہا کہ کلام سر کی دہلی میں واپسی ہمیشہ



دہلی سرکار نے بنایا ڈاکٹر کلام کی یاد میں میوزیم

# دہلی لوٹ آئے کلام سر

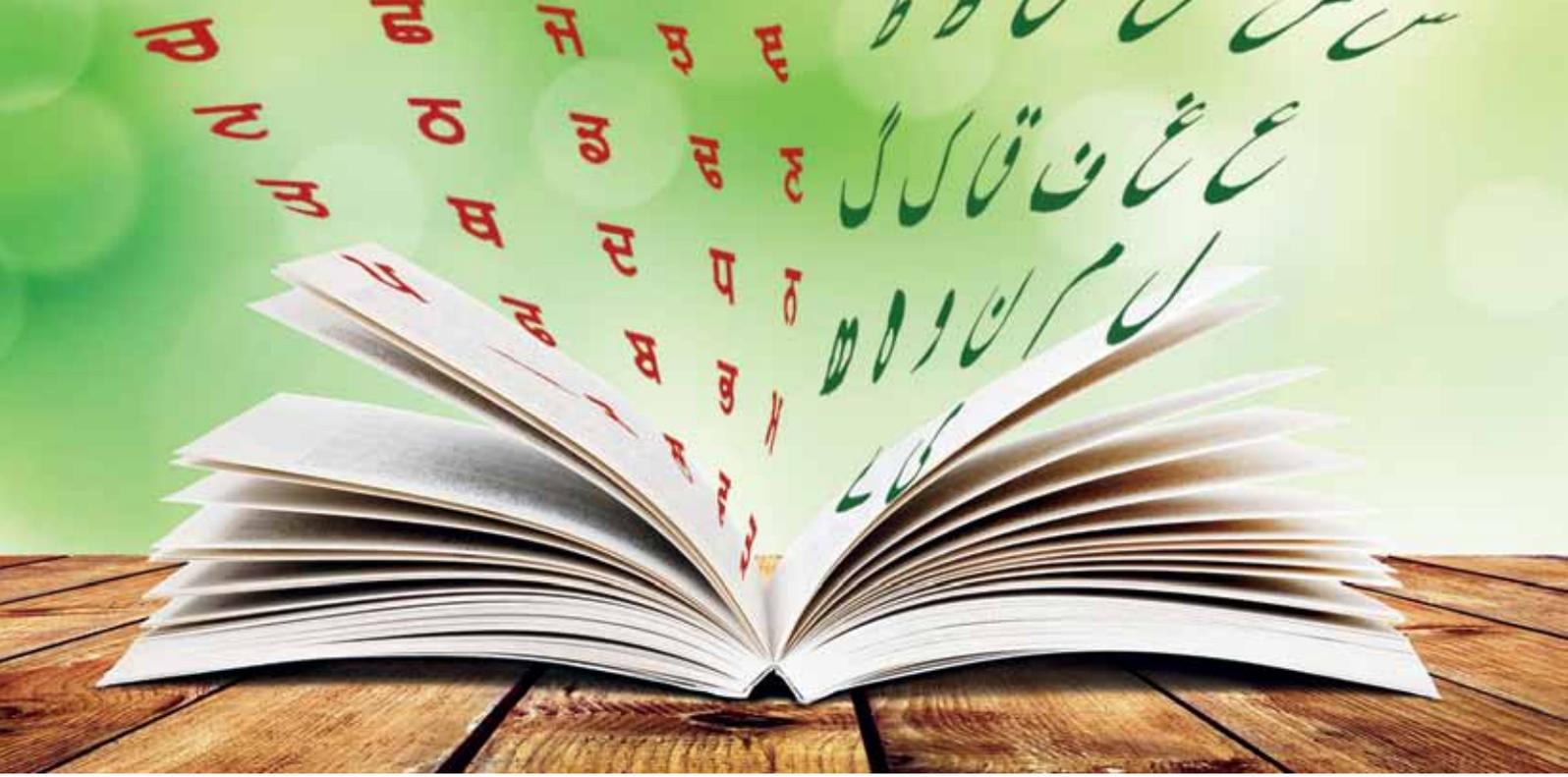


استعمال کی کئی چیزیں بھی وہاں موجود ہے۔ ڈاکٹر کلام کے تمام پیغاموں کی بچھڑی صورت طریقے سے میوزیم میں جگہ جگہ نقاشی کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کچھریوال نے یہ میوزیم قوم کے نام وقف کرتے ہوئے کہا کہ اس سے آنے والی نسلیں ڈاکٹر کلام سے تحریک لے سکیں گی۔ وہ عام آدمی کے صدر جمہوریہ تھے۔ ایک ای میل بھیج دینے پر ان سے ملنے کا وقت مل جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ سائنس داں یا صدر جمہوریہ نہیں، انہیں ایک استاذ کے طور پر یاد کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر دہلی میں میوزیم کھولنے کیلئے دستخط مہم چلانے والی تنظیم کو بھی عزت افزائی کی۔

وہیں نائب وزیر اعلیٰ منیش سوسو دیانے کہا کہ ڈاکٹر کلام کو گیتا، قرآن اور سائنس، تینوں کی تشریح کرنے میں مہارت حاصل تھی۔ دہلی سرکار

**دہلی** سرکار نے اپنا وعدہ پورا کیا اور کلام سر واپس دہلی لوٹ آئے۔ جی ہاں، دہلی ہاٹ میں ہندوستان کے 11 ویں صدر جمہوریہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کا میوزیم بن کر تیار ہو گیا ہے جہاں ان سے جڑی تمام چیزوں کو دیکھا جاسکتا ہے۔ اسے 'کلام اسمارک' (یادگار) کا نام دیا گیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کچھریوال نے 30 جولائی کو اس کلام یادگار کا افتتاح کیا۔

'کلام اسمارک' میں ڈاکٹر کلام کے بچپن سے لیکر میزائل میں بننے اور پھر ملک کے صدر جمہوریہ بننے تک کے سفر اور کامیابیوں کو تصویروں کے ذریعہ دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر کلام کی کتابیں، ان کی تحریر، ان کے کپڑے، بال سنوارنے والی کنگھی، ٹی شرٹ، چشمے سمیت نجی



# ٹیچروں کی کمی میں نہیں چھوٹے گی اردو اور پنجابی کی پڑھائی

**دہلی کی سبھی سرکاری اسکولوں کو ملے پنجابی اور اردو ٹیچر  
اردو کے 601 اور پنجابی کے 769 ٹیچروں کی تقرری پر کابینہ کی مہر**

لیا کہ دہلی کے سرکاری اسکولوں میں سنسکرت زبان کے علاوہ درمیانی درجے پر اردو اور پنجابی کے استاذ بھی ہوں گے۔ فی الحال دہلی میں 1042 سرکاری اسکول ہیں جس میں 24 فیصدی اسکولوں میں پنجابی پڑھائی جاتی ہے جب کہ 25 فیصدی اسکولوں میں اردو پڑھائی جاتی ہے۔ تعلیمی سال 2016-17 میں داخلے کے وقت تقریباً 28612 طالب علموں نے پنجابی زبان اور 82341 طالب علموں نے اردو زبان کا انتخاب کیا۔ دہلی سرکار کے اس فیصلے سے خاص طور سے پنجابی اور اردو زبان سے محبت کرنے والوں میں خوشی کی لہر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے خاص طور سے پنجابی اور اردو زبان گھروں کے بچوں کو اپنی مادری زبان کے تلفظ اور ادب سے واقف ہونے کا موقع ملے گا۔ اس سے شخص ترقی میں ان کیلئے امکانات کے کئی دروازے کھلیں گے۔ ■

اردو اور پنجابی زبان کی اہمیت کوس سمجھتے ہوئے دہلی کی کچر یوال سرکار نے ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ کابینہ نے سرکاری اسکولوں میں 601 اردو اور 769 پنجابی زبان کے ٹیچروں کی تقرری کی تجویز پر مہر لگا دی ہے۔ ایسا کرنے سے دہلی کے ہر سرکاری اسکول میں اردو اور پنجابی زبان کی تعلیم دینے کیلئے کم سے کم ایک استاذ موجود رہے گا۔ وزیر تعلیم منیش سسودیا کا کہنا ہے کہ دہلی کے طالب علم اب صرف اس نام پر اردو اور پنجابی زبان پڑھنا نہیں چھوڑیں گے کہ اسکول میں ان زبانوں کو پڑھانے والے استاذ ہی نہیں ہیں۔ دہلی سرکار ہندوستانی زبانوں کو لے کر کافی سنجیدہ ہے اور یہ فیصلہ اسی کی ایک مثال ہے۔ غور طلب ہے کہ وزیر اعلیٰ اروند کچر یوال نے 24 مئی 2016 کو فیصلہ

کیساتھ سی ایم اور ڈپٹی سی ایم نے مٹینگ کی ہو اور حوصلہ افزائی کیا ہو۔ ہم نے کیا۔ انہیں کیمرج بھیجا، آئی آئی ایم بھیجا۔ اب ٹیچر کو بھی کام کرنے میں مزا آنے لگا ہے۔ ایسے ہی پنجاب میں بھی کریں گے، گوا میں بھی، گجرات میں بھی، مدھیہ پردیش میں، سب جگہ۔

**ابھیشیک (دہلی) - میری بہن نے اس سال 12 ویں پاس کیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ دہلی کے بچوں کو ایڈمیشن میں ریزرویشن ملے گا اور تعلیمی لون کیسے مل سکتا ہے؟**

منیش سسو دیا۔ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ جن 28 کالجوں میں دہلی کی عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگا ہے، وہاں کٹ آف میں 5 فیصدی چھوٹ ملے گی۔ ابھی لاگو نہیں ہوا ہے۔ لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسٹوڈینٹ لون لینا تو بہت آسان ہو گیا ہے۔ آن لائن اپلائی کریئے اور پرنٹ آؤٹ لے کر قریب کے بینک میں جائیے۔ آپ کا لون پاس ہو جائیگا، آپ کو کسی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے۔۔۔

**امن جھا (دہلی) - سڑکوں کا بُرا حال ہے، کیسے ٹھیک ہوگی؟**

اروند کچر یوال۔ 60 فٹ سے چوڑی روڈ دہلی سرکار کی ہیں۔ اس سے کم چوڑی ایم سی ڈی کی ہے۔ پی ڈبلو ڈی نے اپنی ساری سڑکیں درست کر دی ہیں۔ برسات کے بعد پھر دیکھیں گے اگر کہیں خراب ہوئی تو۔ 60 فٹ سے کم چوڑی سڑکوں کا واقعی بُرا حال ہے۔ جب ایم سی ڈی پر ہمارا قابو ہوگا تو وہاں بھی ساری سڑکیں پہلی فرصت میں درست کرا دی جائیں گی۔

**وشال ڈڈلا نی - ایک سوال آیا ہے، اب اگلے ٹاک ٹو اے کے کب ہوگا؟**

اروند کچر یوال۔ مہینے ڈیڑھ مہینے میں کریں گے۔ آپ لوگ اگلی بار سوال ہی نہ پوچھیں سچھاؤ بھی دیں۔

**وشال ڈڈلا نی - جتنے بھی پیغام آئے ہیں، ان سب کو جواب دیا جائیگا۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ایسے تمام سوال جن کی چرچہ صرف ٹویٹر پر ہی ہوتی ہے آج یہاں ان کے جواب ملے۔**

**شکریہ**

منیش سسو دیا - کھیوں کیلئے بہت کچھ کر رہے ہیں۔ اسکولوں کے میدان کھول دیئے گئے ہیں۔ کئی جگہ ٹریک بن رہے ہیں۔ اسکولوں میں میدان خالی پڑا رہتا ہے شام کو۔ تو اگر کوئی اکادمی چلا رہا ہے تو وہاں ٹریننگ دے سکتا ہے۔ 77 اسکولوں کے میدان کھولے گئے ہیں۔ وہاں سرکاری اسکول کے بچوں کو ٹریننگ فری ہے۔ ابھی سارے اسمبلی حلقوں میں کبڑی کرائی تھی۔ جو کھلاڑی باہر جا کر ٹریننگ لینا چاہتے ہیں ان کیلئے بھی پیسہ بڑھا یا ہے۔ ایک بڑی چیز ہے اسپورٹس یونیورسٹی۔ کھیل کو نصاب تعلیم کا حصہ بنائیں گے۔ کھیلنے پر ڈگری ملے گی۔

**اروند کچر یوال - منیش کی فلاسفی ہے کہ اگر آپ چار سال فزیکس پڑھتے ہیں تو آپ کو بی ایس سی کی ڈگری ملتی ہے، لیکن چار سال فٹبال کھیتے ہیں یا باسکٹ بال تو کوئی بھی ڈگری نہیں ملتی۔ اسپورٹس یونیورسٹی اسلئے بنائی جا رہی ہے کہ ڈگری ملے اسپورٹس میں۔ ساتھ ہی 100 مشن کا منصوبہ ہے جس میں قابل کھلاڑیوں کی پہچان کی جائیگی اور انہیں ٹریننگ دی جائیگی۔ نیشنل اور انٹرنیشنل گیمس کیلئے تیار کیا جائیگا۔ ان کے کھانے، پینے، رہنے، ٹریول کا سارا خرچ سرکار اٹھائے گی۔**

**وشال ڈڈلا نی - ٹویٹر پر ایک سوال ہے کہ پنجاب میں تمام اکیڈمیٹک ہیں جو امیگریشن کے نام پر لوگوں کو لوٹتے ہیں، کناڈا یا دوسری جگہوں پر بھیجنے کے نام پر۔ انکے خلاف کیا کارروائی کریں گے؟**

اروند کچر یوال۔ بالکل، ہماری سرکار بنی تو ان کیخلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ جو پردیش جانا چاہتے ہیں، ان کی مدد کیلئے پنجاب سرکار ایک سیل بنائے گی۔ **وشال ڈڈلا نی - سوال ہے کہ سرکاری ٹیچروں کو اچھی تنخواہ ملتی ہے، لیکن تعلیم کی حالت خراب ہے، ٹیچروں کی جواب دیہی کیلئے کیا کیا جانا چاہئے؟**

اروند کچر یوال۔ سرکاری ٹیچروں کو تنخواہ ٹھیک ٹھاک ملتی ہے۔ لیکن تعلیمی بندوبست خراب ہے۔ اس کیلئے وہ ڈپریشن میں ہیں۔ انہیں حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ دہلی میں ہم نے یہ کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ٹیچروں

پو جا سو ہتی (چنڈی گڑھ) - آداب، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ دہلی میں آپ کی سرکار بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ دہلی میں ٹیچروں کیلئے جو پالیسی بنائی ہے، کیا ویسے ہی پنجاب میں بنائیں گے؟

اروند کچر یوال - ہم لوگ جس طرح دہلی میں کام کر رہے ہیں، ویسے ہی باقی صوبوں میں بھی کریں گے۔ آپ سب کو ساتھ لیکر کریں گے۔

اندو بھاسکر (دہلی) - دہلی میں طاق و جفت کیا پھر ہوگا؟

اروند کچر یوال - ضرور غور کریں گے۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ سردیوں میں کریں گے۔ ایپ میٹڈ بس سروس کی اسکیم بھی ہے جس کی فائل ایل جی صاحب کے یہاں ہے۔ اس طرح کے کئی کام کرنے ہوں گے۔ دہلی کی ٹرانسپورٹ انتظامات سدھارنے کیلئے۔

رتن سنگھ (دہلی) - ہر روز آپ کے ایم ایل اے گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آپ کے سکریٹری بھی اریسٹ ہوئے۔ کیا آپ نے بیک گراؤنڈ چیک نہیں کیا تھا؟

اروند کچر یوال - یہ کمانڈو سریندر ہیں۔ 26/11 حملہ ہوا تو دہلی سے جو 200 کمانڈو ممبری بھیجے گئے، اس میں یہ بھی تھے ان کے سامنے بم پھٹا تو سماعت کی طاقت چلی گئی۔ دہلی کینٹ سے ایم ایل اے ہیں۔ یہ ایک دن سڑک پر جا رہے تھے تو ایک افسر سبزی والے سے پیسے مانگ رہا تھا۔ انہوں نے روکا تو جھگڑا ہوا اور پولیس نے ان کے خلاف ایس سی / ایس ٹی ایکٹ کی دفعہ لگا کر جیل بھیج دیا۔ میں غلط کام برداشت نہیں کروں گا۔ ہمارے ایک وزیر کے بارے میں پتہ چلا۔ ان کی ریکارڈنگ ملی تو 24 گھنٹے میں نکال دیا اور جانچ کیلئے سی بی آئی میں دے دیا۔ ہندوستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ اپنے وزیر کو کسی نے اس طرح سی بی آئی کو سونپا ہو۔ جب کہ معاملے کا پتہ میڈیا کو بھی نہیں تھا۔ یہ دوسری آزادی کی لڑائی ہے۔ مارے گئے تو شہید کہلائیں گے، جیت گئے تو نہایت بہادر اور بھاگ گئے تو بزدل۔ ہم بزدل نہیں بننے دیں گے۔

اسی طرح راجیندر رمار جی سی ایم دفتر میں چیف سکریٹری تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ میری پرانی دوستی ہے۔ میری کوئی جان پہچان نہیں ہے۔ میں آئی آئی ٹی کھڑگ پور سے ہوں اور وہ کانپور سے میں سی ایم بنا تو کئی صحافیوں سے پوچھا کہ ایماندار اور باصلاحیت افسر کون ہے؟ سب نے راجیندر جی کا نام لیا تو انہیں سکریٹری بنایا ان کے ساتھ کام کرنے والے ایماندار کی قسمیں کھاتے ہیں ان پر الزام لگا کر گرفتار کر لیا۔ جانچ چل رہی ہے اگر انہوں نے گڑبڑی کی ہے تو ٹانگ دو، دوگنی سزا دے دیں۔ الزام لگا رہے ہیں کہ 2009، 2010 میں گھوٹالہ کیا اگر ایسا ہے تو اس وقت کے سیاسی لوگوں نے بدعنوانی کیا تھا۔ ہم نے ایف آئی آر 49 دن کی سرکار میں کی تھی ان کو اس لئے پکڑا گیا، کیوں کہ وہ میرے دفتر میں تھے۔ اگر وہ نہیں ہوتے تو چیئنج ہے کہ کوئی کارروائی نہیں کرتے۔ ایماندار افسر پکڑ کر لٹکا دیا تو پیغام ہے افسروں کو کہ اگر دہلی سرکار کا کام کیا تو چھوڑیں گے نہیں۔

وشال ڈڈلانی - ٹویٹر پر سوال ہے کہ اروند سروائی فائی کہاں ہے۔ اب تک کیوں نہیں ہوا؟

اروند کچر یوال - وائی فائی پر کام ہو رہا ہے کابینہ مسودہ بن کر تیار ہے۔ اسکو دو حصوں میں کر رہے ہیں۔ پوری دہلی میں فائبر آپٹیکل کابینٹ ورک بچا رہے ہیں۔ ہر گھر تک یہ جائے گا اس سے تمام سہولیت ملے گی جیسے انٹرنیٹ ملے گا، ٹی وی ملے گا، ٹیلی فون جیسی سہولیتیں۔ سی سی ٹی وی بھی جوڑ سکے گا ہم ٹینڈرنگ کر رہے ہیں جلدی، لیکن دو تین سال لگیں گے۔ تب تک فی الحال ہم ہاٹ اسپاٹ، کابینٹ ورک بنا رہے ہیں۔ مشرقی دہلی میں دسمبر یا جنوری تک لاگو ہو جائیگا۔

وشال ڈڈلانی - ٹویٹر پر امریش کپور پوچھ رہے ہیں کہ نائب وزیر اعلیٰ جی آپ دہلی میں لینڈ پولنگ پالیسی کو منظوری کیوں نہیں دے رہے ہیں؟

اروند کچر یوال - اس پر غور و خوض کیا جا رہا ہے کہ اس میں تجاویز ہے کہ ڈی ڈی اے زمین ڈیولپ کر کے 60 فیصدی واپس دے گا اور 40 فیصدی رکھ لے گا۔ ہمارا کہنا ہے کہ جو زمین ڈی ڈی اے خود رکھے گا اس میں دس فیصدی ہمیں دے دیجئے اسکول اور اسپتال جیسے چیزیں بنانے کیلئے۔ بات ہو رہی ہے۔

وشال ڈڈلانی - ہانشودتہ روہنی سیکٹر -6 سے پوچھ رہے ہیں کہ کھیلوں کے بارے میں کیا سوچا ہے، اسے بڑھاوا دینے کیلئے کیا منصوبہ ہے؟

ملتے ہیں چار کروڑ۔ ہم کہہ کر دے رہے ہیں کھل کر دے رہے ہیں۔ اگر نہیں دیں تو بدعنوانی کیلئے مجبور کریں گے۔

**پردیپ (حیدرآباد)۔** بہت سارے نوجوان حکومت میں مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کی شراکت کیسے ہو سکتی ہے اور سالڈ ویسٹ منیجمنٹ کیلئے کیا منصوبہ ہے؟

**اروند کچر یوال -** پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ نوجوانوں کی سرکار ہے۔ ہم میں زیادہ تر ایسے ہیں جن کے خاندان کے لوگ کبھی سیاست میں نہیں تھے۔ ہماری درخواست ہے کہ نوجوان سیاست میں آئیں۔ ہم لوگوں نے وزیر اعلیٰ اربن فیوشپ پروگرام شروع کیا ہے جس میں 9 ہزار لوگوں نے درخواست دی ہے۔

دہلی ملک کی راجدھانی ہے اور یہ شرم کی بات ہے کہ یہاں چاروں طرف گندگی ہے۔ راکٹ سائنس نہیں اسے صاف کرنا۔ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن مدد سیاسی ہے۔ یہ ذمہ ایم سی ڈی کے پاس ہے نہ کہ دہلی سرکار کے پاس۔ انہوں نے صفائی کا معاملہ پوری طرح برباد کر دیا ہے۔ امید ہے کہ اگلے سال حالات بدلیں گے۔ تعلیم، صحت، بجلی اور پانی میں انقلابی کام ہوا۔ صفائی میں بھی کریں گے۔ سال ڈیڑھ سال تو لگیں گے لیکن پھر دہلی کو صاف کر دیں گے۔

**سنجیو (کیرل)۔** آپ کہتے ہیں کہ مرکز اور پی ایم کام نہیں کرنے دیتے۔ کیوں نہیں آپ عام عوام کے سامنے لوگوں سے رائے شماری کراتے ہیں کہ وہ دہلی کی سرکار الگ چاہتے ہیں یا مرکز کے ماتحت؟

**اروند کچر یوال -** اچھا خیال ہے۔ ہم یہ کریں گے۔ رائے شماری قانون میں نہیں ہے، لیکن اوپینین پول کر سکتے ہیں۔ لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا پولیس، زمین وغیرہ دہلی سرکار کے ماتحت رہے؟ ہم ضرور کرائیں گے۔

**روی (گوا)۔** کیوں مرکزی حکومت کے ہمیشہ خلاف رہتے ہیں، کیا وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں؟

**اروند کچر یوال -** میں نے بتایا کہ 14 بلوں کو کیسے روکا گیا، افسروں کا تبادلہ بھی سامنے ہے۔ ہم وکٹم نہیں ہیں۔ دہلی کی عوام مصیبت زدہ ہے۔ مرکزی حکومت جس طرح سے بدلا لے رہی ہے، اس سے دہلی کے لوگ پریشان ہیں۔ دہلی کے لوگوں کو پریشان نہ کیا جائے، ہم بس یہی چاہتے ہیں۔

سے بات کی ہے، سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ کچھ پیسے کا فائدہ ملنا چاہیے۔ تب 'آفس آف پرافٹ' ہے۔ ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن مناسب فیصلہ لیں گے۔

دوسرے صوبوں میں بھی پارلیمانی سکرٹیٹری ہیں۔ انہیں تنخواہ، گاڑی، بنگلہ سب ملتا ہے۔ پنجاب، گجرات، ہریانہ، مدھیہ پردیش سب جگہ ملتا ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں، اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں پھر بھی بی بی پی اور کانگریس والوں کو دقت ہے۔

**رنجیت ماتھر (ساؤتھ دہلی)۔** آداب میرا نام رنجیت ماتھر ہے، ساؤتھ دہلی میں تعلق آباد کا لونی سے، ہماری گلی نمبر 16 میں سیور لائن بدلنے کا کام شروع ہوا تھا۔ بارش کا موسم ہے، گلی کھدی پڑی ہے۔ بچوں کے گرنے کا ڈر ہے۔

**اروند کچر یوال -** میں آپ کی ڈیٹیل نوٹ کر رہا ہوں عہدہ دار آپ کے پاس جا کر پریشانی دور کریں گے۔

**نیپال داس (چینی)۔** کیا ضرورت تھی ایم ایل اے کی تنخواہ بڑھانے کی، کیا اتنی تنخواہ کافی نہیں تھی؟

**اروند کچر یوال -** پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ ایک سرکار کرپشن پر زیر و نالینس رکھ رہی ہے۔ کوئی ایم ایل اے کرپشن نہیں کر سکتا۔ میں بھی نگاہ رکھتا ہوں۔ ابھی تک تاثر ایسا تھا کہ لوگ کرپٹ ہیں، حالانکہ کچھ ایماندار بھی ہوتے ہیں۔ کئی جگہ لوگ بنا تنخواہ کے کام کرتے ہیں، جیسے میونسپل کارپوریشن میں 200 روپے فی ٹائم پاتے ہیں، لیکن انکے بڑے بڑے بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں یہ سب؟ یہ سسٹم ہم نہیں کرنا چاہتے کہ کھلا چھوڑ دو ایم ایل اے کو کہ جو مرضی جہاں سے کمائے۔ لیکن دکھانے کیلئے تنخواہ نہیں دیں گے۔ ہم نے اسے الٹا کیا ہے۔ ہم نے عہد کیا ہے کہ تنخواہ دیں گے۔ اتنی دیں گے کہ اس کا گھر اور دفتر چل جائے۔ لیکن پھر کسی طرح کارپشن برداشت نہیں ہوگا۔ پکڑ کر جیل میں ڈال دیں گے۔

ہماری سرکار بنی تو ایک ایم ایل اے کی تنخواہ 12 ہزار روپے تھی۔ ہم نے بڑھا کر 50 ہزار کیا تو چینل والے چلانے لگے کہ 400 فیصدی اضافہ۔ ہم نے پوچھا ان سے کہ آپ کو کتنے ملتے ہیں تو کہنے لگے کہ ہماری مت پوچھو۔ انہیں

دہلی میں اچھا کام چل رہا ہے، یہ پورے ملک کو بتانا ضروری ہے تاکہ پورے ملک سے سرمایہ کاری یہاں آئے۔ پہلے سارے انٹرنیشنل ایویمنٹ یہاں ہوتے تھے۔ لیکن دس سال سے نہیں ہو رہے تھے۔ بتایا گیا کہ ایک ایویمنٹ کیلئے 27 شعبوں سے این او سی لینی پڑتی ہے۔ پانچ چھ مہینے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ ہم نے سبھی محکموں کے افسروں کو ساتھ بیٹھایا اور کئی این او سی کی ضرورت ختم کر دی۔ باقی کو آن لائن کر دیا۔ پچھلے دنوں تک منتظم میرے پاس آئے جنہوں نے بتایا کہ 20 منٹ کے اندر انہیں ایویمنٹ کرنے کی اجازت مل گئی۔ اب اگر دہلی میں ایسا کام ہو رہا ہے تو ممبئی والوں کو بتانا ضروری تو ہے۔ دہلی میں آؤ، ایویمنٹ کرو۔ پورے ملک کو نہیں دنیا کو بتانا ضروری ہے کہ دہلی میں آؤ، بزنس کرو۔

وشال ڈڈلانی - پڈوچیری سے سُدھا کر پوچھتے ہیں کہ آپ کے 21 رکن اسمبلی پارلیمانی سکریٹری بنے ہیں جس کی وجہ سے رکنیت کے ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ تنخواہ نہیں لیتے، معاوضہ نہیں لیتے تو پھر ایسے ہی کام کر سکتے تھے۔ نام دینے کی ضرورت کیا تھی۔ بغیر پوسٹ کے بھی کام کر سکتے تھے۔

اروند کچر یوال - دراصل مخالف پارٹی کو کام کرنے کی عادت نہیں ہے۔ ہمارے ایم ایل اے کام کر رہے ہیں۔ پریشانی کیا ہے۔ اگر ہمارا ایک اسکول میں راولنڈ لگا کر بتا رہا ہے کہ استاذ آئے کہ نہیں یا پڑھائی کیسی ہو رہی ہے۔ اس کام کیلئے سرکار ایک پیسہ نہیں دیتی۔ نہ گاڑی دیتی ہے نہ گھر دیتی ہے اور نہ نوکر، اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے خدمت خلق کے نام پر وہ یہ سب کام کرتا ہے۔ پھر منیش کو رپورٹ دیتا ہے۔ پھر منیش جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے ایم ایل اے اسپتالوں کے حالات پر نظر رکھتے ہیں۔ کئی ایم ایل اے کو ایسی ہی ذمہ داری ہے جس کا ایک پیسہ نہیں دیتے، ہم، تو پھر یہ آفس آف پرافٹ، کیسے ہو گیا؟

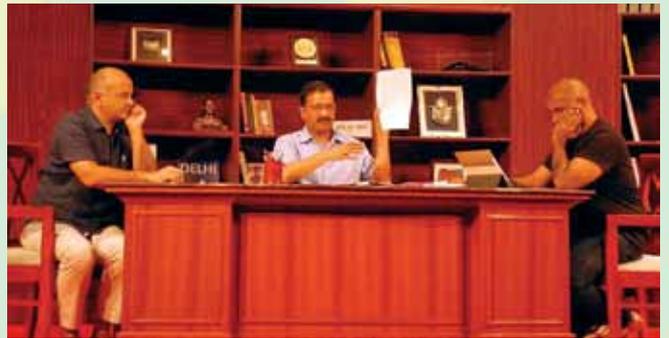
انہیں پوسٹ دینے کی ضرورت اس لئے تھی کہ ایسے اپنے اسمبلی علاقے سے باہر کوئی ایم ایل اے نہیں جاسکتا۔ تو اس کو ایک حق دیا کہ اسکول جا کر دیکھے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں۔

اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو پارلیمانی سکریٹری سے ہٹاؤ۔ یعنی گھر بیٹھے اچھے ہیں، کام نہیں کرنا چاہئے۔ کام تو کریں گے جی۔ ہم نے بڑے بڑے وکیلوں

کیلئے کمیشن آف انکوائری بنایا جسے خارج کر دیا گیا۔ اگر ساتھ دیتے، ہندوستان۔ پاکستان جیسی حالت نہ بناتے تو چار گنا کام ہو سکتا تھا۔ میں نے مودی جی سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ کوئی غلطی ہو تو معاف کر دیجئے۔ مجھے پیسے نہیں چاہئے۔ بہت بجٹ ہے۔ بس روز روز کچھ بند کر دیجئے۔ آپ صاف ہندوستان کی بات کرتے ہیں، میں دو سال میں دہلی کو لندن جیسا بنا دوں گا۔ اسکل انڈیا سب سے بہتر کر دیں گے۔ ساری تعریف آپ کی کروں گا، لیکن نہیں مانے۔

وشال ڈڈلانی کا سوال آیا ہے اشتہار بجٹ کے بارے میں۔ ممبئی سے پتلیج پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے 526 کروڑ کا بجٹ خرچ کیا ہے اشتہاروں پر اور دہلی سرکار کے اشتہار دوسرے صوبوں میں کیوں دکھاتے ہیں؟

اروند کچر یوال - پہلی چیز تو یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے 526 کروڑ اشتہار پر خرچ کئے۔ پچھلے سال اس میں خرچ ہوئے صرف 75 کروڑ۔ یہ آریس ایس افواہیں پھیلانے میں ماہر ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس معاملے میں دنیا میں انکا کوئی ثانی ہوگا۔ وہ ایک افواہ شروع کرتے ہیں اور پھیلاتے جاتے ہیں، پھیلاتے جاتے ہیں جب تک کہ وہ لوگوں کے بیچ بیٹھ نہیں جاتی ہے۔ پہلے ہر شعبہ الگ الگ اشتہار دیتا تھا اس میں گڑبڑ ہوتی تھی۔ اب ہم نے سینٹرلائز کر دیا ہے اور اس لحاظ سے 75 کروڑ زیادہ نہیں ہیں۔



دوسرا سوال ہے کہ ہم دوسرے صوبوں میں اشتہار کیوں دکھاتے ہیں۔ دو تین وجہ ہیں۔ دہلی ملک کی راجدھانی ہے۔ یہاں پورے ملک کے لوگ رہتے ہیں۔ کیرل کے، تملناڈو کے، پنجاب کے لوگ بھی۔ دہلی میں ایک چھوٹا حادثہ ہو جائے تو ٹی وی والے دن بھر دکھاتے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں کیا ہو رہا ہے اسے نہیں دکھاتے، کیوں کہ دہلی میں جو ہو رہا ہے، اسے سارے پردیش کے لوگ جانا چاہتے ہیں۔

ہم نے تین سے چار کروڑ کاربیٹ کر دیا۔ چھ گنا فی ایکڑ اضافہ ہوا اس کیلئے لڑنا پڑا۔



تاجروں کا حال بہت بُرا ہے۔ کمائی گھٹ رہی ہے جو 100 کما تھے اب 80 کما رہے ہیں۔ لیکن آٹھ، دس، پندرہ لوگ ہیں، جن کی جائیداد دو گئی۔ تین گنی ہو رہی ہے۔ ان کا منافع کہاں سے آ رہا ہے۔ مان لیجئے کسی نے تیس روپے کلودال خرید لی اور اب 200 روپے میں بیچ رہا ہے تو میری اور آپ کی جیب سے ہی جا رہا ہے اس کے پاس۔ یعنی ملک بھر میں تاجرنا خوش ہے لیکن کچھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ دھیان دینا پڑے گا۔

**وشال ڈڈلانی۔ دہلی سے پبلک پوچھتے ہیں کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مودی جی آپ کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں اور اسی وقت آپ کروڑوں کے اشتہار دیتے ہیں کہ کتنا کام کیا۔ یہ دونوں کیسے ہو سکتے ہیں؟**

اروند کچر یوال۔ میں نے جو کام گنائے ہیں وہ ہوئے ہیں۔ تصور نہیں ہے۔ جا کر دیکھ آئیے محلہ کلینک اور اسکول، پانی اور بجلی تو آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے۔ لیکن مشکلیں نہیں آتیں تو کام دو گنا۔ تین گنا ہو سکتا تھا۔ ہماری اسمبلی نے 14 قانون پاس کئے۔ جیسے ہم نے ایک قانون پاس کیا کہ اگر 15 دن میں آپ کا راشن کارڈ نہیں بنا تو ہراگلے دن کے حساب سے افسر کی جیب سے پیسا کٹے گا اور آپ کو معاوضہ ملے گا۔ اگر راشن کارڈ اور لائسنس وغیرہ بننے کا وقت متعین ہو جائے تو بدعنوانی نہیں بچے گی۔ لیکن آٹھ مہینے سے قانون مرکز کے پاس اٹکا پڑا ہے۔

جن لوگ پال بل، نوڈیشن بل بھی پڑا ہوا ہے۔ 14 بل پڑے ہوئے ہیں۔

دوسرا، کچھ دن پہلے دہلی سرکار کے 11 افسروں کا بنا ہم سے پوچھے ٹرانسفر کر دیا گیا۔ ہم مانتے ہیں کہ مرکز کو ایسا کرنے کا حق ہے پر کیا اس کا غلط استعمال ہوگا۔ جمہوریت بات چیت سے چلتی ہے۔ ہم کوئی پالیسی بناتے ہیں تو عوام سے پوچھتے ہیں۔ جو افسر سی ٹی وی لگا رہا تھا اس کا تبادلہ کر دیا گیا۔ جو غیر مجاز کالونی میں پانی بجلی، کھڑنجا، نالی کا کام کر رہا تھا، اس کا ٹرانسفر کر دیا۔

دہلی سرکار میں سکریٹری سطح پر 39 عہدے ہیں جس میں 20 عہدے خالی ہیں۔ پھر بھی اٹھا کر تبادلہ کر دیتے ہیں۔ لیکن دہلی سرکار اور اچھے سے چلے گی۔ ہم باہر سے عوام کے بیچ سے لوگوں کو لائیں گے۔

ہمارے پاس اے سی بی (اینٹی کرپشن برانچ) تھی تو 49 دن کی سرکار میں ہی بدعنوانی ختم کر دیا تھا۔ ہماری سرکار بننے کے چار مہینے بعد تک یہی حال رہا، لیکن 8 جون کو پچھلے سال مرکزی سرکار نے نیم فوجی دستہ بھیج کر اے سی بی پر قبضہ کر لیا۔ آج دہلی میں میرے سامنے کوئی رشوت لے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے 32 کیس ایک سال میں اے سی بی کے پاس ثبوت کے ساتھ بھیجا۔ 150 شکایتیں عوام نے کی ہیں۔ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔

مرکز نے تمام فائلیں روک رکھی ہیں، ڈے میل کا بُرا حال ہے۔ کرناٹک میں اسی طرح کے آکٹے پاتر پوجنا چل رہی ہے۔ اسکول والے اچھا کام کر رہے ہیں گرم کھانا، شاندار کچن۔ آٹھ صوبوں میں وہ کام کر رہے ہیں۔ گجرات، چھتیس گڑھ، کرناٹک وغیرہ میں۔ ہر جگہ نامزدگی کی بنیاد پر۔ وہ این جی او ہیں، ٹینڈر میں درخواست نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم منافع نہیں کما تے۔ الٹا ڈونیشن لے کر آتے ہیں۔ ہم نے بھی فائل چلائی، کا بینہ میں تجویز پاس کر کے بھیجا کہ دہلی میں ڈے میل میں انکی مدد لیں گے۔ لیکن ایل جی صاحب نے منع کر دیا۔

منیش نے آٹھ ہزار کمرے بنائے، 45 نئے اسکول بنائے۔ اب ہمیں 20 ہزار ٹیچر چاہیئے۔ 15 ہزار عارضی استاذ ہیں۔ ہم نے انہیں پکا کرنے کیلئے فائل چلائی لیکن روک دی گئی۔ بتائیے کہ اسکول کیسے چلائیں۔ ہم نے دس نئے اسپتالوں کیلئے فائل بھیجی ہیں پیسہ دے رہے ہیں لیکن زمین دینے کو تیار نہیں ہیں۔ خواتین کی حفاظت

## جمع خوری نہیں رُکی تو 400 روپے کلو بکے گی دال: کجریوال

ملک میں دالوں کی قیمتوں میں آگ لگی ہوئی ہے کیوں بڑھ رہی ہے قیمت اتنی زیادہ؟ دال 17-18 ملین ٹن دال پیدا ہوتی ہے ملک میں۔ چار پانچ ملین باہر سے منگاتے ہیں۔ قریب 22-23 ملین کھپت ہے۔ اس سال بھی ویسا ہی ہے۔ پھر آگ کیوں لگی ہوئی ہے دال میں؟ گیہوں کا کم سے کم تحوک قیمت 1450-1500 روپے ہیں، بازار میں 17-18 روپے فی کلو مل رہا ہے۔ ارہر، مونگ کا ہے 50 روپے، بازار میں 200 روپے کلو ہے۔ کہاں جاتے ہیں 150 روپے۔ بیج میں بڑے بڑے بیج خور پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ 8-10 لوگ ہیں جو جمع خوری کر رہے ہیں۔

میں نے وزیر اعظم جی سے کہا سٹیجک میں، بڑے بڑے لوگ دال کی جمع خوری کر رہے ہیں۔ ایسے الزام ہیں تو جانچ تو ہو۔ اگر اس پر سختی نہ ہوئی تو 400 روپے کلو دال کی قیمت ہو جائیگی، نہ ہم کھاپائیں نہ آپ۔

لوگ کہنے لگے کہ جل بورڈ بر باد ہو جائے گا۔ سال بھر بعد ہمیں 173 کروڑ ٹیکس زیادہ ملا جب کہ پانی مفت دینے، کیوں کہ ہم نے بدعنوانی کم کی۔ پانی بر باد بھی نہیں ہوا۔ لوگ کہتے تھے فضول استعمال کریں گے، لیکن ہوا یہ کہ 3 ملین گیلن ہردن کی بچت ہونے لگی۔ کیونکہ بیس ہزار لیٹر کے اوپر پانی استعمال ہونے پر پورا بل دینے کا ڈر تھا۔

ایک پریشانی بل کی ہے۔ پورے ملک میں یہ پریشانی ہے، یہاں بھی غلط بل آتے تھے۔ جسے ٹھیک کرانے کے نام پر بدعنوانی ہوتی تھی۔ ہم نے سرکار میں آنے کے بعد سب کا پرانا بل معاف کر دیا۔ تین چار لاکھ تک کا بل معاف ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی موبائل فون سے خود میٹر ریڈنگ لے کر کے بل بنانے کا بندوبست کر دیا۔ میٹر ریڈنگ کا انتظام ختم ہوا۔

بہت سے علاقے میں جہاں اب تک پانی نہیں پہنچا تھا ہم نے 263 نئی کالونیوں میں پائپ بچھا کر پانی پہنچایا۔ ہم نے دسمبر 2017 تک ہر گھر تک پانی پہنچانے کا ہدف رکھا ہے۔ پانی بھی ایسا کہ ٹوٹی کھول اور پنی لو۔ پہلے بھی نہ آرا ہوتا تھا اور نہ پلاسٹک کی بوتل۔ ٹوٹی سے ہم لوگ پانی پیتے تھے تو ہم نے صاف پانی کا ہدف بھی رکھا ہے۔

کسانوں کیلئے بھی ہم نے بہت کچھ کیا۔ کسانوں نے کہا کہ فصلیں بر باد ہوئیں۔ 20 ہزار روپے فی ایکڑ اور 50 ہزار ہیکٹر کے حساب سے معاوضہ دیا۔ ملک میں کبھی نہیں ہوا ایسا۔ اسی طرح اراضی ایکوائر میں پہلے 54 لاکھ روپے فی ایکڑ سرکار دیتی تھی جب کہ مارکیٹ ریٹ تین کروڑ کے قریب تھا۔

آتے ہی دام آدھے کر دیئے۔ دہلی میں اگر کوئی خاندان دو سو یونٹ بجلی خرچ کرتا ہے تو اس کا بل آتا ہے 550 روپے، گجرات میں آتا ہے 1170 روپے، ممبئی میں 1950 روپے اور پنجاب میں 1229 روپے کا بل آتا ہے۔

اگر دہلی میں 400 یونٹ بجلی خرچ ہو تو بل آتا ہے 1370 روپے، گجرات میں 2615، ممبئی میں 4300، کوکاتہ میں 2927 روپے اور پنجاب میں 2690 روپے۔

Sl. No.	Description	Rate	Quantity	Amount
1	Electricity	1.00	144.00	144.00
2	Electricity	1.00	0.00	0.00
3	Electricity	1.00	0.00	0.00
4	Electricity	1.00	0.00	0.00
5	Electricity	1.00	0.00	0.00
6	Electricity	1.00	0.00	0.00
7	Electricity	1.00	0.00	0.00
8	Electricity	1.00	0.00	0.00
9	Electricity	1.00	0.00	0.00
10	Electricity	1.00	0.00	0.00
11	Electricity	1.00	0.00	0.00
12	Electricity	1.00	0.00	0.00
13	Electricity	1.00	0.00	0.00
14	Electricity	1.00	0.00	0.00
15	Electricity	1.00	0.00	0.00
16	Electricity	1.00	0.00	0.00
17	Electricity	1.00	0.00	0.00
18	Electricity	1.00	0.00	0.00
19	Electricity	1.00	0.00	0.00
20	Electricity	1.00	0.00	0.00
21	Electricity	1.00	0.00	0.00
22	Electricity	1.00	0.00	0.00
23	Electricity	1.00	0.00	0.00
24	Electricity	1.00	0.00	0.00
25	Electricity	1.00	0.00	0.00
26	Electricity	1.00	0.00	0.00
27	Electricity	1.00	0.00	0.00
28	Electricity	1.00	0.00	0.00
29	Electricity	1.00	0.00	0.00
30	Electricity	1.00	0.00	0.00
31	Electricity	1.00	0.00	0.00
32	Electricity	1.00	0.00	0.00
33	Electricity	1.00	0.00	0.00
34	Electricity	1.00	0.00	0.00
35	Electricity	1.00	0.00	0.00
36	Electricity	1.00	0.00	0.00
37	Electricity	1.00	0.00	0.00
38	Electricity	1.00	0.00	0.00
39	Electricity	1.00	0.00	0.00
40	Electricity	1.00	0.00	0.00
41	Electricity	1.00	0.00	0.00
42	Electricity	1.00	0.00	0.00
43	Electricity	1.00	0.00	0.00
44	Electricity	1.00	0.00	0.00
45	Electricity	1.00	0.00	0.00
46	Electricity	1.00	0.00	0.00
47	Electricity	1.00	0.00	0.00
48	Electricity	1.00	0.00	0.00
49	Electricity	1.00	0.00	0.00
50	Electricity	1.00	0.00	0.00
51	Electricity	1.00	0.00	0.00
52	Electricity	1.00	0.00	0.00
53	Electricity	1.00	0.00	0.00
54	Electricity	1.00	0.00	0.00
55	Electricity	1.00	0.00	0.00
56	Electricity	1.00	0.00	0.00
57	Electricity	1.00	0.00	0.00
58	Electricity	1.00	0.00	0.00
59	Electricity	1.00	0.00	0.00
60	Electricity	1.00	0.00	0.00
61	Electricity	1.00	0.00	0.00
62	Electricity	1.00	0.00	0.00
63	Electricity	1.00	0.00	0.00
64	Electricity	1.00	0.00	0.00
65	Electricity	1.00	0.00	0.00
66	Electricity	1.00	0.00	0.00
67	Electricity	1.00	0.00	0.00
68	Electricity	1.00	0.00	0.00
69	Electricity	1.00	0.00	0.00
70	Electricity	1.00	0.00	0.00
71	Electricity	1.00	0.00	0.00
72	Electricity	1.00	0.00	0.00
73	Electricity	1.00	0.00	0.00
74	Electricity	1.00	0.00	0.00
75	Electricity	1.00	0.00	0.00
76	Electricity	1.00	0.00	0.00
77	Electricity	1.00	0.00	0.00
78	Electricity	1.00	0.00	0.00
79	Electricity	1.00	0.00	0.00
80	Electricity	1.00	0.00	0.00
81	Electricity	1.00	0.00	0.00
82	Electricity	1.00	0.00	0.00
83	Electricity	1.00	0.00	0.00
84	Electricity	1.00	0.00	0.00
85	Electricity	1.00	0.00	0.00
86	Electricity	1.00	0.00	0.00
87	Electricity	1.00	0.00	0.00
88	Electricity	1.00	0.00	0.00
89	Electricity	1.00	0.00	0.00
90	Electricity	1.00	0.00	0.00
91	Electricity	1.00	0.00	0.00
92	Electricity	1.00	0.00	0.00
93	Electricity	1.00	0.00	0.00
94	Electricity	1.00	0.00	0.00
95	Electricity	1.00	0.00	0.00
96	Electricity	1.00	0.00	0.00
97	Electricity	1.00	0.00	0.00
98	Electricity	1.00	0.00	0.00
99	Electricity	1.00	0.00	0.00
100	Electricity	1.00	0.00	0.00

ایک دو صوبے کو چھوڑ کر دہلی میں سب سے سستی بجلی ملتی ہے۔ لیکن ایک چیلنج ہے۔ بجلی کا انفراسٹرکچر بے حد خراب ہے۔ جنگلی پیمانے پر ٹرانسفارمر لگا نے ہیں۔ لوکل فالٹ بہت ہوتے ہیں۔ دہلی میں بجلی کی کمی نہیں ہے لیکن اب ہم ٹھیک کریں گے۔

**پانی۔** ہم مانتے ہیں کہ پانی بنیادی حقوق ہے۔ لیکن نجکاری اور کنزرویورزم کے دور میں ماحول بنایا جا رہا ہے کہ پانی ملنا چاہیے۔ میرا ماننا ہے کہ پانی تو ہر حال میں چاہیے۔ پانی تو غریب سے غریب آدمی چھے گا۔ نہیں دو گے تو چوری کر کے چھے گا۔ تو پیاس بجھانے لائق فری پانی دینا سرکار کا فرض ہے۔

ہم نے سرکار بنانے کے بعد 20 ہزار لیٹر پانی مفت کر دیا۔ پانچ لوگوں کا پر یوار ہو تو اتنا پانی بہت ہے۔ لوگوں کو یقین نہیں ہوا۔ بل زیرو ہو گیا۔ کئی

ابھی تک ہم امریکا سے سیکھنے کی بات کرتے تھے اب وہ ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا پہلی بار ہوا کہ اب تک 100 ڈسپینسری بن چکی ہیں۔ سب بہت اچھی چل رہی ہیں اس سال 31 دسمبر تک دہلی میں ایسی ہزار ڈسپینسری بن جائیں گی۔

صحت حفاظت کا اگلا درجہ ہے پولی کلینک۔ اس میں الٹرا سائونڈ سے لیکر ایکس رے تک کا بندوبست ہو گا اور ایک ساتھ سات آٹھ طرح کی بیماریوں کے ماہر خصوصی یہاں موجود ہوں گے۔ یہاں مریض بھرتی نہیں کئے جائیں گے۔ ہاں، بیماری سنجیدہ ہوئی تو ساری جانچ اور ڈاکٹری صلاح موجود ہوگی۔ اب تک 22 پولی کلینک بن چکے ہیں ابھی میں پانچ و ہار کا پولی کلینک دیکھنے گیا تو وہاں اوسط طبقہ کے لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ پانچ اسٹار اسپتالوں میں بھی ایسی سہولیات موجود نہیں ہے۔ اب اگر مالدار لوگ اوسط درجہ کے لوگ سرکاری اسپتالوں میں علاج کرانے آرہے ہیں تو یہ صحت کے میدان میں انقلاب ہی ہے۔

تیسرا درجہ ہے بڑے اسپتال، ملٹی سپر اسپیشلسٹی اسپتال، ہم نے ساری دوائیں اور جانچ مفت کر دی ہیں۔ اس لئے کہ ہم مانتے ہیں کہ صحت اور علاج کی سہولت بنیادی حقوق جیسا ہے۔ بڑی بیماری ہو تو پرائیویٹ اسپتالوں میں جانے پر غریب آدمی کا سب کچھ لٹ جاتا ہے۔

آخر دہلی سرکار کے پاس یہ سب کرنے کیلئے پیسہ کہاں سے آرہا ہے۔ پہلے تو لوگ پیسے کی قلت کی بات کرتے تھے دراصل یہ ایماندار سرکار ہے۔ اسلئے خوب پیسہ بچ رہا ہے۔ دہلی میں اگر ایسا ہو رہا ہے تو پنجاب، گوا، ہماچل ہر جگہ حالات سدھر سکتے ہیں۔

کئی بار سنتے ہیں کہ کسان نے خودکشی کر لی کیوں کہ بیماری ہونے پر لاکھوں کا بل چکانے کیلئے قرض لیا تھا۔ چکا نہیں پایا اور خودکشی کر لی۔ میں نے انٹر۔ اسٹیٹ کونسل کی اجلاس میں وزیر اعظم جی کے سامنے یہ مدعا اٹھایا۔ اگر مرکزی سرکار پیسے دیکر سرکاری اسپتالوں میں دوائیں اور علاج فری کرانے کا بندوبست کرا دیں تو پورا ملک تعریف کریگا۔ کسانوں کی خودکشی کم ہوں گی۔

**بجلی۔** بجلی کو لے کر بھی ہماری سرکار نے وعدہ پورا کیا۔ جب ہماری سرکار بنی تو ملک میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی شاید دہلی میں تھی۔ ہم نے

کیا۔ گاؤں والے پکڑ کر ایک لوکل ڈسپینسری میں لے گئے۔ ورننگ ڈے تھا۔ قریب 11 بجے تھے لیکن وہاں تالا لگا تھا۔ نہ مریض نہ ڈاکٹر نہ ہی نرس یہ حالت ہے پبلک سیکٹر کی۔



جب ہم نے دہلی میں کام شروع کیا تو یہاں کے سرکاری اسپتالوں کا بھی حال بُرا تھا۔ یہاں بھی ہم نے سب سے پہلے بجٹ بڑھایا جیسے تعلیم میں 100 فیصدی بڑھایا ویسے ہی صحت میں پچاس فیصدی بجٹ بڑھایا۔ دہلی سرکار کا کل بجٹ 40 ہزار کروڑ ہے۔ اس میں سے قریب دس ہزار کروڑ لگ بھگ 25 فیصدی تعلیم پر اور 18-19 فیصدی صحت پر خرچ کیا جاتا ہے۔

ابھی دہلی میں بڑے بڑے اسپتال اور ڈسپینسریاں ہیں۔ کھانسی، زکام ہونے پر بھی لوگ ایمس بھاگتے ہیں تو ہم نے طے کیا کہ اچھی ڈسپینسریاں بنے۔ ہم نے اس کے تین مرحلوں کی منصوبہ بنائی ہے۔ سب سے نیچے ہے محلہ کلینک تاکہ چھوٹی موٹی بیماریوں کیلئے محلے میں ہی علاج ہو جائے۔

ہم نے پیرا گڑھی میں پہلا عام آدمی کلینک بنایا جھگی بستی میں ایئر کنڈیشن۔ وہاں علاج کے علاوہ 212 قسم کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں جس میں ایک دو تو ایسے ہیں جن میں ایک ہزار روپے تک خرچ ہوتے ہیں۔ سب کچھ فری دوا سے لیکر ٹیسٹ تک۔ لوگوں کو یقین نہیں ہوا کہ ایسے ڈسپینسری بن سکتی ہے۔ پہلے ایسی ڈسپینسری بنانے میں پانچ کروڑ روپے لگ جاتے تھے۔ ہم نے 20 لاکھ میں بنایا۔ اس کی تعریف صرف میں نہیں کر رہا ہوں۔ امریکا سے ایک رپورٹر آیا واشنگٹن پوسٹ کا، اس نے اسے دیکھا اسے اتنا اچھا لگا کہ واشنگٹن پوسٹ نے خبر چھاپی کہ کیا امریکا دہلی کے محلہ کلینک سے سیکھ سکتا ہے؟

## مرکز یہ چار قدم اٹھائے توڑکے گی کسانوں کی خود کشی۔ کجریوال

میں نے انٹر-اسٹیٹ کاؤنسل میں وزیراعظم مودی جی سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کی پورے ملک میں کسان خود کشی کر رہے ہیں۔ چار چیزیں کر دیجئے تو یہ پریشانی دور ہو سکتی ہے۔

- سارا لون معاف کر دیجئے کسانوں کا۔ بہت ثواب ہوگا۔ ملک کے کسان دعائیں دیں گے۔
- سو اسی ناٹھن رپورٹ لاگو کر دیجئے۔ مودی جی نے لوک سبھا چناؤ سے پہلے اسے لاگو کرنے کا وعدہ کیا تھا اس میں ہے کہ لاگت سے پچاس فیصدی جوڑ کر فصل کا دام طے کیا جائے گا۔ گےہوں کی لاگت آرہی ہے 1950 روپے فی کوئٹل اور سرکار نے قیمت طے کی ہے 1450 روپے۔ کسان خود کشی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟
- اگر ملک کے کسی حصے میں کسانوں کی فصل برباد ہو تو جیسے دہلی میں 20 ہزار روپے فی ایکڑ معاوضہ دیا گیا۔ ویسے ہی مرکز ریاستی سرکار کو دے۔
- اسپتالوں میں دوائیاں اور سارے ٹیسٹ فری کر دیئے جائیں۔

گیا لیکن پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ کئی بار ڈپریشن میں بچے خود کشی کر لیتے ہیں۔ بچے کو برباد کر رہی ہے یہ نوڈیٹیشن پالیسی۔ پہلے اگر کوئی کمزور ہوتا تھا تو کمپارٹمنٹ آ جاتی تھی۔ سب کو پڑھنا پڑتا تھا۔ ہم نے اس پالیسی کو ہٹانے کا بل پاس کر کے مرکز کو بھیجا ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ مرکز جلد سے جلد اس کی منظوری دے۔

دہلی میں ہم نے 100 فیصدی بجٹ بڑھایا ایجوکیشن میں کیوں کہ نیت صاف تھی۔ مرکزی سرکار نے تعلیم کے بجٹ میں 25 فیصدی کٹوتی کر کے 82 ہزار کروڑ سے 68 ہزار کروڑ کا کر دیا تھا۔ اب اُسے 71 ہزار کروڑ کیا ہے۔ جبکہ ہم نے پانچ ہزار سے دس ہزار کروڑ کر کے 100 فیصدی بڑھایا۔

سرٹیکس، فلٹائی اور، نالی سب ضروری ہے۔ پر سب سے ضروری تعلیم ہے۔ ایک سرٹک نہیں بنے گی تو کام چل جائے گا، پر بچے نہیں پڑھے لکھیں گے تو پورا ملک برباد ہو جائیگا۔ میرا اپنا ماننا ہے کہ ہر ریاستی سرکار کو اور مرکز کو تعلیم پر بجٹ بہت بڑے درجے پر بڑھانا پڑے گا تاکہ ملک کے بچے پڑھ لکھ سکیں۔

**صحت** - ہماری دوسری اولیت ہے صحت، ہم تعلیم اور صحت میں خرچ کو سرمایہ کاری مانتے ہیں۔ پورے ملک میں سرکاری اسپتالوں اور ڈسپینسریوں کا بُرا حال ہے۔ ابھی پنجاب گیا تھا تھوڑے دن پہلے، وہاں ایک گاؤں

دہلی میں کئی پرائیویٹ اسکول ایسے ہیں جو دکان بن گئے ہیں۔ انا پ شاپ فیس ہر سال بڑھاتے ہیں عوام ناخوش ہیں۔ آج تک کوئی ان کی لگام نہیں کس کسا۔ ایسے اسکول سرکار کو کچھ نہیں سمجھتے تھے کیوں کہ ہر وزیر اور وزیر اعلیٰ وہاں سفارش سے داخلہ کراتے تھے۔ ہم نے ایک بچے کی بھی سفارش نہیں کی۔ میرا اپنا بیٹا نو بیٹا میں پڑھتا ہے چاہتا تو دہلی کے کسی بھی اسکول میں داخلہ کرا دیتا لیکن نہیں کرایا۔ کیوں کہ پھر میں انہیں فیس بڑھانے سے کیسے روکتا وہ کہتے کہ آپ کا بیٹا ہمارے یہاں پڑھتا ہے میں کمزور ہو جاتا۔ میں نے یا منیشن نے کسی کا بھی داخلہ نہیں کرایا۔ اس لئے ہمارے پاس ہمت ہے اور ہم زیادہ وصولی گئی فیس واپس کر رہے ہیں۔

ہم جانچ کر رہے ہیں اگر لگے گا کہ فیس بڑھانے کی ضرورت ہے تبھی بڑھے گی یہ پہلی بار ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں کی لگام کسی گئی ہے اگر یہ دہلی میں ہو سکتا ہے تو گجرات، گوا، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتا۔ ہمارا تجربہ بتاتا ہے کہ نیت صاف ہو تو بالکل ہو سکتا ہے۔ میں ملک کو آگاہ کر رہا ہوں کہ اگر ملک کی تعلیمی معیار بہتر نہیں ہوئی، نقل اور فرضی ڈگری کا سلسلہ چلا تو ملک کیلئے ٹھیک نہیں ہے۔

کچھ سال پہلے نوڈیٹیشن پالیسی آئی۔ آٹھویں تک کسی کو فیل نہیں کیا جاتا۔ اچانک نویں میں امتحان ہوتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ بچہ نویں میں پہنچ

سوچتے رہتے ہیں ہم کسی بھی صوبے میں جائیں تو سرکاری اسکولوں کی بُری حالت دیکھتی ہے۔ بیت الخلاء نہیں ہے، بچے چھٹی سے پہلے بھاگ جاتے ہیں استاذ پڑھاتے نہیں، ٹاپ کرنے میں گھوٹالہ نکل رہا ہے۔ ڈگریاں بٹ رہی ہیں، نقل چل رہی ہے ایسے میں ملک کا کیا ہو گا۔ سوچنے کی بات ہے۔



دہلی میں سرکار بناتے ہی ہم نے چیئنج قبول کیا۔ ہم نے سمجھا کہ تعلیم اور صحت میں خرچ دراصل سرمایہ کاری ہے۔ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ تعلیم کا بجٹ دوگنا کر دیا جائے پانچ ہزار کروڑ سے سیدھے دس ہزار کروڑ، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تعلیم کا بجٹ 100 فیصدی بڑھا ہو آزادی کے بعد ایسا پہلی بار ہوا ہے۔

دہلی کے سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولتیں نہیں تھی۔ بیت الخلاء میں تالے لگے رہتے تھے یا ان کی حالت بہت خراب تھی ہم نے انہیں درست کر لیا جہاں بیت الخلاء نہیں تھے، وہاں نئے بنوائے۔ تقریباً 1100 سرکاری اسکولوں میں بیت الخلاء، پینے کے پانی، صفائی اور رکھ رکھاؤ کا انتظام کیا گیا۔ پھر پتہ چلا کہ ایک کلاس میں ڈیڑھ سو بچے ہیں۔ ہم استاذ کو کیسے کہتے کہ وہ ٹھیک سے نہیں پڑھا رہے ہیں۔ ہم نے پتہ کیا کہ کتنے کلاس روم کی ضرورت ہے۔ ایک سال میں 8000 نئے کلاس روم بنائے گئے۔ چالیس کمروں کا درمیانی حساب لگائے تو یہ 200 نئے اسکولوں کے بننے کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ 45 نئے اسکول بن کر تیار ہیں۔ 100 نئے اسکولوں کیلئے زمین کی نشاندہی کر لی گئی ہے۔ ہم نے انہیں شاندار بنانے کیلئے بہتر آرکیٹیکٹ ڈھونڈے ہیں۔ ہمارا ماننا ہے کہ غریب بچوں کو اچھی تعلیم مل گئی تو وہ خود ترقی کر لیں گے۔

سرکار میں پیسے کی نہیں نیت کی کمی ہے۔ اسکول، پانی، بجلی، اسپتال سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہمارے سفر نے ثابت کیا کہ ہم جو کہتے تھے وہ ٹھیک تھا۔ جو کام پہلے سو روپے میں ہوتا تھا، وہ اب 60-70 روپے میں ہوتا ہے۔

فروری میں وزیر اعظم مودی جی نے حاجی پور میں ریل روڈ پل کا افتتاح کیا۔ جب 2009 میں یہ پل بنا شروع ہوا تھا تو لاگت تھی 600 کروڑ۔ اب یہ تین ہزار کروڑ کا ہو گیا۔ دہلی میں ایک رانی جھانسی فلائی اور ہے۔ 2008 میں 70 کروڑ کی تخمینہ لاگت کی بنیاد پر ایم سی ڈی (دہلی سرکار نہیں) نے بنانا شروع کیا۔ ابھی بن کر تیار نہیں ہوا اور لاگت 200 کروڑ ہو گئی۔ گوا میں ماٹو وی برج 2014 سے بنا شروع ہوا تھا تو تخمینہ لاگت تھی 470 کروڑ۔ اب دو سال میں ہی یہ بڑھ کر 886 کروڑ ہو گئی۔

پورے ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ کام وقت پر پورا نہیں ہوتا اور لاگت بڑھتی جاتی ہے۔ دہلی میں کچھ فلائی اور بن رہے تھے جب ہم آئے۔ پرانی سرکار کام شروع کر گئی تھی۔ ایک کی کہانی بتاتا ہوں۔ دس فیصدی کام ہوا تھا دو ڈھائی سال پہلے کام شروع ہوا تھا تو تخمینہ لاگت تھی سوا تین سو کروڑ۔ ہم نے یہ فلائی اور دو سو کروڑ میں بنا کر دکھایا، وہ بھی وقت سے پہلے۔ ایسی مثال کہیں نہیں ہے۔ 300 کروڑ کی لاگت کا کام ڈیڑھ ہزار کروڑ میں تو ہوتا تھا 200 کروڑ میں پہلی بار ہوا۔

ہماری سرکار نے پانچ فلائی اور میں بچائے کل ساڑھے تین سو کروڑ منگول پوری میں آئی ٹی آئی 24 کروڑ روپے میں بنا تھا ہم نے 16 کروڑ میں بنایا پہلے ڈسپنسری چار پانچ کروڑ روپے میں بنتی تھی اب 20 لاکھ میں ایئر کنڈیشن ڈسپنسری بن رہی ہیں۔ اس بچت سے ہمیں پیسہ ملا تو تمام چیزوں پر ٹیکس کم کر دیا لوگوں نے کہا کہ ٹیکس کم کرنے سے آمدنی گھٹے گی لیکن ان کا فائدہ ہوا۔ دہلی میں ٹیکس کلکیشن بڑھ گیا۔

سرکار کا چار چیزوں پر سب سے زیادہ دھیان ہے۔ تعلیم، صحت، بجلی اور پانی۔  
**تعلیم**۔ منیش سوسو دیارات دن تعلیم کو بہتر کرنے کے بارے میں

ٹاک ٹو اے کے . میں عوام سے سیدھا مکالمہ

TALK TO AK

## مرکز ساتھ دے تو دو سال میں دہلی کولنڈن بنا دیں گے: کجریوال

**اروند کجریوال**۔ وقت وقت پر میں میڈیا کو انٹرویو دیتا رہا ہوں، لیکن جب عوام کے بیچ جاتا ہوں تو لگتا ہے کہ عوام کے سوال اور میڈیا کے سوال الگ الگ ہیں، پچھلے دنوں میں نے گوا میں نوجوانوں کو خطاب کیا تھا۔ قریب ایک ہزار نوجوان وہاں تھے، ان سے سیدھے بات کی تو پتہ چلا کہ نوجوانوں کے من میں کیسے کیسے سوال ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ دہلی میں بھی ایسا کریں۔ عوام سے سیدھے بات کرنے کا کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ عوام کے سوالوں کا سامنا تبھی کر سکتے ہیں جب آپ ایماندار ہوں۔ آج ہم ایسا کر رہے ہیں یہ ہماری ایماندار سیاست کا ثبوت ہے۔

**دہلی** کے وزیر اعلیٰ ارونڈ کجریوال نے 17 جولائی کو عوام کے تمام سوالوں کا سیدھا جواب دے کر سرکار کیخلاف پھیلائی جا رہی تمام افواہوں کی سچائی بتائی۔ ساتھ ہی اپنی سرکار کی کامیابیوں اور یوجناؤں کا خاکہ پیش کیا۔ ٹاک ٹو اے کے (بات کریں ارونڈ کجریوال سے) پروگرام میں عوام کے سوالوں کو پیش کرنے کا ذمہ مشہور سنگیت کاروشال ڈولانی نے اٹھایا۔ جواب دینے کیلئے وزیر اعلیٰ کے علاوہ نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا بھی موجود تھے۔ سوال ٹویٹر، ایس ایم ایس کے ذریعے پوچھے گئے اور سیدھے فون کر کے بھی۔ پیش ہے۔ اس پروگرام کی شروعات میں وزیر اعلیٰ ارونڈ کجریوال کے خطاب اور بعد میں ہوئے سوال و جواب کے ایڈیٹڈ حصے۔



# 50 फ़ीसदी बढ़ी न्यूनतम मज़दूरी

“हम सब जानते हैं कि कितनी महँगाई है। गरीब को बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। दाल 200 रुपये किलो बिक रही है। एक कहावत है कि जिनको भगवान ने कम दिया है, उन्हें कानून में ज्यादा देना चाहिए। गाँधी जी ने कहा था कि जब भी कुछ करो सबसे अंतिम आदमी के बारे में सोच कर करो। हमारी सरकार सबके लिए काम करती है, लेकिन गरीब आदमी के लिए सबसे ज्यादा करती है। हम न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का ऐलान कर रहे हैं।

आज दिल्ली में अकुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 9,568 रुपये है इसे बढ़ाकर 14000 रुपये किया जा रहा है। अर्धकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 10,600 रुपये से बढ़ाकर 15,400 और कुशल श्रमिक की 11,600 रुपये से बढ़ाकर 17000 रुपये प्रतिमाह किया जा रहा है। अभी तक विकास का जो मॉडल है उसमें अमीर और अमीर हो जाता है और गरीब और गरीब। सरकार की जिम्मदारी है कि जो हाशिये पर हैं, उनकी बेहतरी के लिए नीतियाँ बनाए। गरीब लोगों की जेब में पैसा होगा तो माँग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था बेहतर होगी।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का यह ऐतिहासिक फैसला पूरे देश में लागू करें।”

(स्वतंत्रता दिवस समारोह के भाषण में मुख्यमंत्री केजरीवाल का ऐलान)



श्री सज्जन सिंह यादव, निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 द्वारा प्रकाशित एवं आकांक्षा इम्प्रेसन्स, 18/36 स्ट्रीट नं. 5, रेलवे लाइन साइड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-05 द्वारा मुद्रित